अमर उजाला
प्रवाह
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948
नई दिल्ली ■ बुधवार, 25 सितंबर 2024

धर्म का उद्देश्य खुद पर नियंत्रण करना है, न कि दूसरों की आलोचना करना। -दलाई लामा

सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चों के यौन शोषण से संबंधित सामग्री को डाउनलोड करने, अपने पास रखने या देखने को भी पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में रखने संबंधी जो ताजा फैसला सुनाया है, वह ऐतिहासिक व स्वागत योग्य है, लेकिन इसे प्रभावी बनाने के लिए समाज को भी आगे आना होगा।

बच्चों की गरिमा

सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने बच्चों के यौन शोषण से संबंधित सामग्री को डाउनलोड करने, अपने पास रखने या देखने को भी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में रखने संबंधी जो ताजा फैसला सुनाया है, वह कानूनी दृष्टिकोण से तो अहम है ही, समाज के नैतिक मानदंडों और बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से भी एक ऐतिहासिक फैसला है। उल्लेखनीय है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने एक मामले में कहा था कि ऐसी सामग्री को डाउनलोड कर देखने में कोई अपराध नहीं है, बशर्ते व्यक्ति की मंशा इसे प्रसारित करने की न हो। लेकिन बाल यौन सामग्री देखना कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है, बल्कि इससे उन अपराधियों को प्रोत्साहन मिलता है, जो इस प्रकार की सामग्री का निर्माण व प्रसार करते हैं। लिहाजा शीर्ष अदालत द्वारा इस फैसले को रद्द किया जाना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत की यह व्याख्या भी गौरतलब है कि ऐसी सामग्रियां साइबर दुनिया में मौजूद रहती हैं और सभी को आसानी से सुलभ भी हो जाती हैं। ऐसे में, बच्चों की गरिमा और अधिकारों का उल्लंघन करने वाली ऐसी सामग्री को सिर्फ देखना या अपने पास रखना भी यौन शोषण के दायरे में ही आता है। इसके अतिरिक्त, किसी भी न्यायिक निर्णय में 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' शब्द के बजाय 'बाल यौन उत्पीड़न एवं दुर्व्यवहार सामग्री (सीएसईएएम)' के उपयोग का शीर्ष अदालत का आदेश भी स्वागतयोग्य है। शीर्ष अदालत ने इस निर्णय के साथ ही यौन शिक्षा को व्यापक रूप से लागू करने का जो सुझाव दिया है, उसने लंबे समय से विवादों में घिरे इस विषय पर चर्चाओं को पुनर्जीवित कर दिया है। देश में कई लोग इसे भले ही अनावश्यक और समाज की पारंपरिक मान्यताओं के खिलाफ मानते हों, लेकिन आज के डिजिटल युग में, जहां इंटरनेट पर मौजूद सामग्रियों तक पहुंच हर व्यक्ति के लिए आसान हो गई है और यौन उत्पीड़न व

बाल शोषण की घटनाएं बढ़ रही हैं, यौन शिक्षा को लेकर भ्रम व गलत धारणाएं दूर करना बेहद जरूरी हो गया है। आम धारणा यह भी है कि बच्चों को यौन शिक्षा देने से वे गलत राह भी पकड़ सकते हैं, लेकिन शोध बताते हैं कि अगर बच्चों को सही उम्र में और सही तरीके से यौन शिक्षा दी जाती है, तो वे अधिक जागरूक और जिम्मेदार बनते हैं। जाहिर है कि शीर्ष अदालत का फैसला बच्चों की गरिमा, सुरक्षा और अधिकारों के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है, लेकिन इसे प्रभावी बनाने और इंटरनेट के जिम्मेदार उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए स्कूलों व परिवारों सहित पूरे समाज का सहयोग जरूरी है।

कितना बदल गया इन्सान

तिरुमला मंदिर के पवित्र प्रसादम में प्रयुक्त घी में मिलावट के मुद्दे पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को निश्चित ही अनुत्तरित सवालों पर ध्यान देना चाहिए, जो फिल्म *उपकार* में इंदीवर द्वारा लिखित प्रसिद्ध गीत *देते हैं भगवान को धोखा, इन्सान को क्या छोड़ेंगे* में व्यक्त भावनाओं को ही अभिव्यक्त करते हैं।

शंकर अय्यर
वरिष्ठ पत्रकार

प्रिय श्री नारा चंद्रबाबू नायडू,
मैं यह पत्र भगवान वेंकटेश्वर के लाखों भक्तों में से एक के रूप में तिरुमला मंदिर में पवित्र प्रसाद तैयार करने में मछली के तेल, गोमांस की चर्बी और पशु वसा मिलाए गए घी के इस्तेमाल के बारे में चौंकाने वाले खुलासे पर पीड़ा और गुस्सा व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं। पवित्र भावनाओं का उल्लंघन राजनीतिक संरक्षण द्वारा समर्थित व्यवस्थागत उदासीनता से उपजा है। इस पत्र का फोकस इस बात पर नहीं है कि 'किसने' यह किया, बल्कि क्या, क्यों और कैसे कारक इस आक्रोश को बढ़ावा देते हैं।

मैं आपको 1990 के दशक से जानता हूं, जब आप संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मैं इस उम्मीद से लिख रहा हूं कि आप इस मुद्दे पर उचित ध्यान देंगे। यह स्थिति फिल्म *'उपकार'* में इंदीवर द्वारा लिखित प्रसिद्ध गीत *'देते हैं भगवान को धोखा, इन्सान को क्या छोड़ेंगे'* में व्यक्त भावनाओं की प्रतिध्वनि है। मुझे यकीन है कि आप आपूर्ति शृंखला की अनदेखी के जोखिम और तिरुमला तथा अन्य मंदिरों में जाने वाले लाखों लोगों के लिए इसके भयावह परिणामों को समझते हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी चिंता व्यक्त की है। मुझे उम्मीद है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। कृपया मुझे कुछ असहज करने वाले सवाल पूछने की इजाजत दें। मिलावट का पता लगाने की प्रक्रिया क्या है और निर्णय का समर्थन करने वाले उपकरण कैसे दिखते हैं? सरकार के खुलासे से पता चलता है कि मिलावट पर रिपोर्ट जुलाई में ही प्राप्त हुई थी। सरकार ने इसे सार्वजनिक करने के लिए 20 सितंबर तक इंतजार क्यों किया? तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) हर दिन करीब साढ़े तीन लाख लड्डू तैयार करता है। तीर्थयात्री भारत और दुनिया भर में अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस बहुमूल्य प्रसाद को साझा करते हैं। यदि इस नृशंस कृत्य के बारे में पहले से ही प्रचार-प्रसार होता, तो श्रद्धालु सतर्क हो जाते। फिर रिपोर्ट मिलने

और उसके खुलासे के बीच के अंतराल को क्या समझा जाए? सामान्यतः किसी गड़बड़ी का पता चलने पर कार्रवाई की जाती है। टीटीडी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्यामला राव से हमें पता चला है कि मंदिर के लिए गुणवत्तापूर्ण घी खरीदने की प्रक्रिया पर टीटीडी को सलाह देने के लिए चार डेयरी विशेषज्ञों का एक पैनल बनाया गया है। लेकिन गंभीर बात यह है कि जनता को अब तक यह नहीं बताया गया है कि यह सिर्फ एक कंपनी है। और अपराधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? क्या जुलाई में पता लगने के बाद से टीटीडी या सरकार ने मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की है?

एक खबर में बताया गया कि 'एक निजी कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए चार टैंकर घी संदिग्ध प्रतीत हुए।' क्या संदेह वैज्ञानिक जांच की कठोरता से गुजरा है? सबसे बुरी बात है कि अधिकारियों ने स्वीकार किया कि 'आपूर्तिकर्ताओं ने इन-हाउस जांच की सुविधा नहीं होने का फायदा उठाया।' सौभाग्य से, टीटीडी की जल एवं खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला में कार्यरत एक पुण्यात्मा ने जोखिमों से चिंतित होकर गुजरात स्थित पशुधन एवं खाद्य विश्लेषण एवं अध्ययन केंद्र (सीएएलएफ) को परीक्षण के लिए नमूने भेजे। एफएसएसएआई द्वारा प्रमाणित 210 प्रयोगशालाओं (जिनमें से आधा दर्जन आंध्र प्रदेश में हैं) में से एक सीएएलएफ के चयन ने कई राजनीतिक लोगों की भौंहें टेढ़ी कर दी हैं। मानो समानांतर परीक्षण की कोई नई व्यवस्था लागू कर दी गई हो। यह भी स्पष्ट नहीं है कि घी के केवल एक या सभी आपूर्तिकर्ताओं के नमूने परीक्षण के लिए भेजे गए थे। आदर्श रूप से, मिलावट का पता चलने के बाद अनिवार्य रूप से सभी आपूर्तिकर्ताओं के नमूने जांच के लिए भेजे जाने चाहिए। बहुमूल्य लड्डू तीर्थयात्रियों द्वारा चढ़ाए जाने वाले प्रसादों में से एक है, जिन्हें वे घर ले जाते हैं। लाखों भक्त अब इस डर से जूझ रहे हैं कि क्या मिलावट हो सकती है। भगवान वेंकटेश्वर को चढ़ाए जाने वाले नैवेद्यम की तैयारी में इस्तेमाल की जाने वाली अन्य सामग्रियों में मिलावट की पहचान करने की प्रक्रिया क्या है? क्या खरीद प्रतिस्पर्धी बोली या गुणवत्ता द्वारा तय की जाती है?

क्या इन उत्पादों की सामग्रियों का गुणवत्ता परीक्षण होता है और यदि हां, तो कितनी बार? टीटीडी को विश्वास और भरोसा बनाए रखने के लिए रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। वास्तव में, टीटीडी को एक कदम और आगे जाना चाहिए। अमेरिकी न्यायाधीश लुइस ब्रैंडिस ने अपने निबंध 'प्रचार क्या कर सकता है' में कहा, 'सूर्य के प्रकाश को सबसे अच्छा कीटाणुनाशक कहा जाता है।' टीटीडी को पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए और सभी सामग्रियों के सभी आपूर्तिकर्ताओं के नाम प्रकाशित करने चाहिए। प्रिय मुख्यमंत्री जी, यह कटु सच्चाई है कि भावनाओं का अपमान यथास्थिति बनाए रखने और प्रणालीगत खामियों के कारण होता है।

टीटीडी सबसे धनी संस्थानों में से एक है। 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के बजट, 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की जमाराशि और 1,000 किलोग्राम से अधिक सोने के साथ, इसके पास समय के अनुरूप संसाधनों के प्रबंधन का खाका तैयार करने के संसाधन हैं। उसे अपने किसी विश्वविद्यालय में एक आधुनिक, इन-हाउस, एफएसएसएआई-प्रमाणित प्रयोगशाला स्थापित करनी चाहिए। इस प्रयोगशाला को टेंडर तय होने पर, आपूर्ति मिलने पर और जब चढ़ावे के लिए सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, तब सामग्री परीक्षण करने का काम सौंपा जाना चाहिए। हैदराबाद, चेन्नई और बंगलूरू स्थित आईआईटी और आईटी दिग्गज निश्चित रूप से प्रसाद की सामग्रियों और उसे बाहर भेजे जाने का प्रबंधन करने के लिए उद्यम समाधान तैयार और स्थापित करने में मदद कर सकते हैं। आधुनिक प्रणाली अनुप्रयोगों और प्रौद्योगिकी को अपनाने से पैमाने और जटिलता की चुनौतियों में कमी आएगी तथा सुरक्षा और विश्वास को बढ़ावा मिलेगा। ऐसा लगता है कि शक्ति और धन के संगम पर कुछ भी पवित्र नहीं है और यह अशुभ है। जैसा कि कवि प्रदीप ने लिखा है-देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इन्सान! ईश्वरत्व में विश्वास रखने वालों के रूप में, यह जरूरी है कि हम पवित्र चीजों को सुरक्षित रखें।

साभिवादन।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

खलील जिब्रान

प्रेम में वह शक्ति है, जो मृत्यु को दूर भगा देती है। प्रेम वह जादू है, जो शत्रु को भी जीत लेता है। भयभीत मत हो, क्योंकि मैं युद्ध पर प्रेम की विजय प्रकट करने वाला सत्य हूं।

अंधेरे को देखो, जो सूर्य को जन्म दे रहा है

वृक्षों की शाखाओं को झुकाने और खेत में धान के पौधों को जोर से झुकाकर रौंद देने के बाद तूफान शांत हो गया। तारे बिजली के भग्न अवशेषों की तरह दिखाई दे रहे थे, परंतु अब सब पर निस्तब्धता का साम्राज्य था, जैसे प्रकृति का युद्ध कभी लड़ा ही नहीं गया हो। उस बड़ी एक नवयुवती अपने कमरे में प्रविष्ट हुई और सिसकियां भरकर रोते हुए अपने बिस्तर के पास घुटने टेककर बैठ गई। उसका हृदय असहनीय पीड़ा से जल रहा था, परंतु अंत में वह अपने होंठ खोलकर मात्र यही कह सकी, हे प्रभु! मेरे प्रियतम को सुरक्षित मेरे पास ले आओ। मेरे आंसू सूख चुके हैं और मैं अब और कुछ नहीं कर सकती। हे प्रेम और दया के सागर!

मेरा धैर्य चुक गया है और विपत्ति मेरे हृदय पर कब्जा करना चाहती है। प्रभु! मेरे प्रियतम को युद्ध के लौह-पंजों से मुक्त करो, उसे ऐसी निर्दय मृत्यु से बचाओ, क्योंकि वह दुर्बल है। हे स्वामी! मेरे प्रिय की रक्षा करो, जो तुम्हारा अपना पुत्र है, उसे उस शत्रु से बचाओ, जो तुम्हारा भी शत्रु है। मृत्यु-द्वार की ओर जबरदस्ती ले जानेवाले मार्ग से उसे अलग करो, उसे मेरे पास ले आओ या मुझे उसके पास ले चलो।

एक नवयुवक चुपचाप प्रविष्ट हुआ। मुक्त हुए जीवन से भीगी पट्टी से उसका सिर लिपटा हुआ था। आंखों में आंसू भरे मुस्कराकर अभिवादन करता हुआ वह उसके निकट आया, फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और फिर उस पर अपने जलते हुए होंठ रख दिए। और उस वाणी से, जिसमें अतीत का शोक, मिलन का आनंद और उसकी प्रतिक्रिया की अनिश्चितता की झलक थी, वह बोला : 'मुझसे डरो मत, क्योंकि मैं वही हूं, जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। अब तुम प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि शांति मुझे तुम्हारे पास सुरक्षित लौटा लाई है और मानवता ने वह सब वापस कर दिया है, जो लालच ने हमसे छीनने का प्रयास किया था। 'तुम उदास मत हो, बल्कि मुस्कुराओ मेरी प्रियतमे! आश्चर्य मत करो, क्योंकि प्रेम में वह शक्ति है, जो मृत्यु को दूर भगा देती है। प्रेम वह जादू है, जो शत्रु को भी जीत लेता है। मैं तुम्हारा ही हूं। मुझे मृत्यु के नगर से निकालकर तुम्हारे सौंदर्य के घर आनेवाली प्रेतात्मा मत समझो। भयभीत मत हो, क्योंकि मैं गोलियों और तलवारों से बचा हुआ-लोगों के समक्ष युद्ध पर प्रेम की विजय प्रकट करने वाला सत्य हूं। मैं खुशी और शांति के खेल का परिचय देने वाला शब्द हूं।' फिर नवयुवक चुप हो गया और उसके आंसू दिल की भाषा बोल रहे थे, और खुशी के दूत उस घर के चारों ओर मंडरा रहे थे, और दोनों हिलों ने उस मिलन को फिर से पा लिया, जो उनसे छीन लिया गया था। उषाकाल में दोनों तूफान से आहत प्रकृति के सौंदर्य को निहारते हुए खेत के बीच खड़े थे। एक गहरी और सुखदायक निस्तब्धता के बाद सैनिक ने अपनी प्रेमिका से कहा, 'अंधेरे को देखो, जो सूर्य को जन्म दे रहा है।'

(लेबनानी-अमेरिकी लेखक खलील जिब्रान की 'द प्रोफेट' पुस्तक के अनूदित अंश)

प्रेम पर भरोसा करें

सूत्र

प्रेम से की गई प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। हर प्रार्थना सुनी जाती है। युद्ध पर शांति की विजय होती है और मानवता वह सब लौटा देती है, जो लालच हमसे छीनने का प्रयास करता है। प्रकृति का सौंदर्य आहत मन को सुकून देता है। प्रेम से दुश्मन को अपना बनाया जा सकता है।

दूसरा पहलू

आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के डोड्डीगुंटा गांव में करीब 900 परिवार रहते हैं, इनमें से 300 परिवारों में जुड़वां बच्चे हैं।

एक अनोखा गांव, जहां हर तीसरे घर में हैं जुड़वां बच्चे

माता-पिता बनने का एहसास बहुत खास होता है। गोद में खेलते बच्चे की मां के ममत्व को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये खुशियां तब और भी बढ़ जाती हैं, जब घर में जुड़वां बच्चे किलकारियां मारें। यह खुशी हर किसी को नसीब नहीं होती। देश में औसतन एक हजार बच्चों के जन्म पर चार ही जुड़वां पैदा होते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश का एक गांव ऐसा है, जहां हर तीसरे घर में जुड़वां बच्चे पैदा हो रहे हैं।

पूर्वी गोदावरी जिले के पिदापुरम मंडल में छोटा-सा गांव है डोड्डीगुंटा। यहां लोगों की आजीविका का मुख्य साधन खेती है। लगभग 4,800 आबादी वाले इस गांव में करीब 900 परिवार हैं। इनमें से करीब 300 परिवारों में जुड़वां बच्चे हैं। जुड़वां बच्चे पैदा होने का यह सिलसिला करीब दो दशकों से चल रहा है। अब गांव के ज्यादातर घरों के आंगन में जुड़वां बच्चे खेलते हैं। हमशक्ल कई जुड़वां अब युवा हो गए हैं। डोड्डीगुंटा में प्रवेश करते ही बहुत से जुड़वां बच्चे सड़कों पर खेलते-घूमते दिखते हैं। इसी गांव में क्यों पैदा हो रहे हैं जुड़वां बच्चे, इस सवाल पर गांव के सरपंच मणिकंटा दावा करते हैं कि यह एक कुएं के पानी की वजह से है, लेकिन उनके इस दावे का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। चिकित्सा विशेषज्ञ इस तर्क को सिरे से खारिज करते हैं। इसी गांव के जुड़वां बच्चों के पिता रामबाबू कहते हैं कि आप डोड्डीगुंटा में अलग-अलग आयु वर्ग के जुड़वां देख सकते हैं। इस वजह से हमारा गांव देश-दुनिया में मशहूर हो गया है।

गांव के भीतर तालाब के किनारे बने एक छोटे से कुएं पर काफी रौनक है। रामबाबू इशारा कर तेलुगु में बताते हैं-यही वह कुआं है, जिसका छह माह तक नियमित पानी पीने से जुड़वां बच्चे होते हैं। कुएं से पानी लेने विजयवाड़ा से जेसम भी आए हैं। जेसम कहते हैं कि शादी के पांच साल बाद भी उनके घर में बच्चा नहीं है। इसी उम्मीद से पानी लेने वह पत्नी के साथ आए हैं। रामबाबू के अनुसार, हर रोज कई लोग यहां दूर-दराज से पानी लेने के लिए आते हैं। आंध्र के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और हैदराबाद तक इस कुएं का पानी जा रहा है। उधर, चिकित्सा विशेषज्ञ ऐसे किसी भी दावे को सिरे से खारिज करते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ एंसस्टेड रिप्रोडक्शन (आईएसएआर) के अध्यक्ष डॉ. निर्मल भसीन कहते हैं कि कुएं का पानी पीने से संतान या जुड़वां बच्चे होने की बात का कोई आधार नहीं है। जीन और वंशानुगत कारक जुड़वां बच्चों के जन्म के लिए जिम्मेदार होते हैं।

बचिंद्र वशिष्ठ

डोड्डीगुंटा में प्रवेश करते ही बहुत से जुड़वां बच्चे सड़कों पर खेलते-घूमते दिखते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, दो दशकों से जुड़वां बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं।

गांव के सरपंच मणिकंटा दावा करते हैं कि गांव में जुड़वां बच्चे एक कुएं के पानी की वजह से हो रहे हैं, लेकिन उनके इस दावे का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। चिकित्सा विशेषज्ञ कहते हैं, पानी नहीं आनुवंशिक कारक इसके जिम्मेदार हैं।

आंकड़े

बैंक कर्ज

बैंकों से कर्ज लेकर लोग अपनी आर्थिक स्थिति सुधार रहे हैं। होम लोन के अलावा क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन भी बैंक खूब बांट रहे हैं।

होम लोन	48.6%
पर्सनल लोन	33.1%
वाहन	11.1%
क्रेडिट कार्ड	4.9%
शिक्षा	2.3%

आंकड़े मार्च 2024 तक के, प्रतिशत में | स्रोत : RBI

अंतर्यात्रा
संकलित

तारकासुर से त्रस्त होकर देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि इसका वध महादेव का पुत्र ही कर सकता है। इसके लिए शिव-पार्वती का विवाह कराना होगा।

ब्रह्मा ने बताया देवताओं को उपाय

एक बार सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे आग्रह किया कि तारकासुर ने हमें बहुत त्रस्त कर दिया है, उससे हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि उसे तो भोलेनाथ ने वरदान दे रखा है कि उसकी मृत्यु उनके पुत्र के हाथों होगी। देवताओं के सामने बहुत बड़ा संकट आ गया, क्योंकि माता सती खुद को भस्म कर चुकी थीं। इधर सती ने हिमाचल के यहां पार्वती के रूप में अवतार ले लिया था, लेकिन उनका भगवान शंकर से विवाह नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, भोलेनाथ गहन तपस्या में लीन थे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से उपाय पूछा, तो उन्होंने कहा कि आप सब मिलकर शंकर जी की तपस्या भंग करवाकर उन्हें पार्वती जी के साथ विवाह के लिए राजी करें।

देवताओं ने जगत के कल्याण के लिए कामदेव से भगवान भोलेनाथ की तपस्या भंग करवाने के लिए निवेदन किया। कामदेव भी देव और लोक कल्याण के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना महादेव की तपस्या भंग करवाने के लिए पहुंच गए।

कामदेव ने अनेक प्रयासों के बाद अपना कामास्त्र चलाकर भगवान शंकर की तपस्या भंग की। देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने महादेव से पार्वती जी से विवाह करने का आग्रह किया। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह के बाद उनका, जो पुत्र हुआ, उनका नाम षडानन यानी कार्तिकेय रखा गया। इसके बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की।

अमर उजाला
पुराने पन्नों से — 28 फरवरी, 1960

संयुक्त अरब गणराज्य व इस्राइल में तनातनी जारी

संयुक्त अरब गणराज्य व इस्राइल के बीच तनातनी का पूरे अरब क्षेत्र पर बुरा असर पड़ रहा है। वहीं, अमेरिका के विदेश विभाग ने एक बयान में कहा कि उसे आशा है कि संयुक्त अरब गणराज्य व इस्राइल संयम से काम लेंगे।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत

डॉ. लोहिया के विकास संबंधी विचार आज भी प्रासंगिक हैं, जिनके अनुसार, समावेशी विकास तभी मुमकिन है, जब सभी आत्मनिर्भर हों।

सतीश सिंह | समाज

डॉ. राममनोहर लोहिया को समाजवादी सिद्धांत का प्रणेता कहा जाता है। उनके अनुसार, समाजवाद ही वह सिद्धांत है, जिस पर चलकर वंचित तबके को भी विकास की मुख्यधारा में लाया जा सकता है। समाजवाद की परिभाषा के अनुसार, यह एक ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था है, जिसमें उत्पादन के साधनों और संपत्ति पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है और सरकार द्वारा यह नियंत्रित नहीं किया जाता है। इसका मूल सार यह है कि उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व समाज में समानता लाने में अहम भूमिका निभाता है।

इसी वजह से दुनिया के अनेक देशों में इसे विकास का सबसे बेहतर सिद्धांत माना जाता है। वैसे, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। अर्थात यहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकारी और निजी, दोनों हाथों में है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह पूंजीवाद और समाजवादी सिद्धांतों का मिश्रण है। समाजवादी सिद्धांत के अनुरूप डॉ. लोहिया समावेशी विकास के समर्थक

थे। वह देश के विकास में सभी लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना चाहते थे। यह तभी मुमकिन था, जब देश के सभी लोग आत्मनिर्भर हों, यानी कोई रोजगार करें या स्वरोजगार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र के भी वे पैरोकार थे अर्थात सभी लोग व्यक्तिगत तौर पर स्वतंत्र हों, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें, लेकिन साथ में कुछ निश्चित जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करें, क्योंकि तभी हमारा समाज और देश विकास के पथ पर आगे बढ़ सकता है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के तौर-तरीकों के बारे में महात्मा गांधी और डॉ. लोहिया की विचारधारा में समानता थी। डॉ. लोहिया के अनुसार, देश की ग्रामीण आबादी को सक्षम बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर व लघु उद्योगों की स्थापना करना आवश्यक है। डॉ. लोहिया का मानना था कि देश में पूंजी और तकनीकी कौशल की कमी है। इसलिए यूरोप या रूस की विकासात्मक रणनीति को अपनाकर भारत में विकास की गति को तेज नहीं किया जा सकता है। वे चाहते थे कि देश में गांधी जी के कुटीर उद्योग और नेहरू के भारी उद्योग के नजरिये के बीच का रास्ता अपनाया जाए, ताकि देश में समावेशी विकास को बल मिल सके।

उनके अनुसार, कृषि और औद्योगिक विकास की गति में समानता हो, ताकि किसानों व ग्रामीणों को भी विकास की राह पर आगे लेकर बढ़ा जा सके। डॉ. लोहिया चाहते थे कि रेल, इस्पात आदि भारी उद्योग केंद्र सरकार की देखरेख में चलें, लेकिन कृषि आधारित उद्योगों का स्वामित्व एवं प्रबंधन जिलों, तहसील और गांवों पर छोड़ दिया जाए। वह युवाओं और महिलाओं को विशेष तरजीह देते थे। उनका मानना था कि युवा देश के कर्णधार हैं, क्योंकि वे एक लंबे समय तक देश के विकास में सहभागी बने रहते हैं। इसलिए उन्हें कौशलयुक्त बनाने की जरूरत है, ताकि वे बेरोजगार नहीं रहें और देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में सतत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें। डॉ. लोहिया लिंग के आधार पर भेदभाव करने के सख्त खिलाफ थे। उनके अनुसार, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों के बराबर का स्थान देकर लैंगिक भेदभाव की समस्या को जड़ से खत्म्या किया जा सकता है। वह महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना चाहते थे।

डॉ. लोहिया जानते थे कि भारत जैसे बड़े देश में वंचित तबकों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसलिए, देश में अकाल पड़ने पर भोजन की समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश के देवरिया और बिहार के डालटनगंज में चल रहे 'घेरा डालो' आंदोलन का समर्थन उन्होंने किया था। वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार के पक्षधर थे, लेकिन किसी भी मामले में एकतरफा कारोबार के हिमायती नहीं थे, यानी आयात और निर्यात बराबर होना चाहिए।

भारत लगभग 200 साल की गुलामी के बाद आजाद हुआ था, जिसके कारण वह अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण मानकों पर पिछड़ चुका था। उस कालखंड में देश की एक बड़ी आबादी गांवों में रहती थी। फिर भी, डॉ. लोहिया चाहते थे कि देश के विकास को देश के जनमानस का विकास करके सुनिश्चित किया जाए और इस सफर में सभी को आत्मनिर्भर बनाकर और हर क्षेत्र को विकसित करके ही विकास के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता था।

डॉ. लोहिया के मुताबिक, ग्रामीण भारत में खेती-किसानी के साथ-साथ कुटीर व लघु उद्योगों को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। इनके माध्यम से ही ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। विकास में सभी की भागीदारी होने से स्वतः ही देश आर्थिक रूप से सशक्त हो सकता था और इसके लिए सत्ता को विकेंद्रित करने की भी जरूरत है। उनके अनुसार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाकर ही समग्रता में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है।

चिंतन

श्रीलंका में वामपंथ की जीत भारत रखे पैनी नजर

इस साल फरवरी में अनुरा कुमारा दिसानायके जब भारत आए थे, तो किसी ने शायद ही सोचा होगा कि क़रीब सात महीने बाद वे श्रीलंका के राष्ट्रपति बनेंगे। 22 सितंबर को वे श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। उनकी जीत श्रीलंका में जनता की ओर से वैचारिक तख़्तापलट स्वरूप है। श्रीलंकाई मतदाताओं ने चुनावी उलटफेर में धुरंधरों को हराया और राष्ट्रपति के रूप में गरीबी के खिलाफ अभियान चलाने वाले एक वामपंथी नेता को चुनकर देश को नई दिशा के लिए मतदान किया। मार्क्सवादी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके की विजय वर्ष 2022 में देश को आर्थिक पतन के कगार पर ले जाने के लिए दोषी ठहराए गए स्थापित दलों और नेताओं को हाशिये पर धकेले जाने की प्रतीक है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, जातीय हिंसा, भ्रष्टाचार व गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे दक्षिण एशियाई देश श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में दिसानायके की गद्दी कांटों के ताज से कम नहीं है। दिसानायके नेशनल पीपुल्स पावर गठबंधन (एनपीपी) और जनता विमुक्ति पेरामुना (जेवीपी) दोनों का नेतृत्व करते हैं। मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर जेवीपी की स्थापना 1960 के दशक में समाजवादी क्रांति के माध्यम से सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से की गई थी। वर्ष 1971 और 1987-89 में दो असफल सशस्त्र विद्रोहों जिनमें हजारों लोगों की जान गई थी, के बाद पार्टी लोकतांत्रिक राजनीति की ओर मुखातिब हुई और तीन दशकों से अधिक समय से इसी पर कायम है। इस चुनाव से पहले तक जेवीपी श्रीलंका के राजनीतिक परिदृश्य में तीसरी पार्टी बनी रही, जबकि सत्ता दो पारंपरिक राजनीतिक दलों यूनाइटेड नेशनल पार्टी और श्रीलंका फ्रीडम पार्टी या उनसे निकले दलों के नेतृत्व वाले गठबंधनों के बीच में ही रही। दिसानायके के नेतृत्व में 2019 में एनपीपी का गठन कई अन्य संगठनों के साथ एक समाजवादी गठबंधन के रूप में किया गया, जबकि जेवीपी मार्क्सवादी सिद्धांतों का पालन करती रही। एनपीपी ने एक मध्य-वाम, सामाजिक लोकतांत्रिक मंच का रुख अपनाया, ताकि व्यापक समर्थन हासिल किया जा सके। इन तमाम पहलों के बावजूद दिसानायके को 2019 के राष्ट्रपति चुनाव में महज तीन प्रतिशत मत मिले थे। लेकिन 2022 के आर्थिक संकट के दौरान राजनीतिक स्थिति बदल गई, सात दशकों से अधिक समय तक देश पर शासन करने वाली दो पारंपरिक पार्टियों से निराश श्रीलंकाई मतदाताओं ने एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में एनपीपी को अपनाया। पार्टी का भ्रष्टाचार विरोधी रुख दृढ़ता से प्रतिध्वनित हुआ क्योंकि कई लोगों ने आर्थिक संकट के लिए राजनीतिक भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया। इस रुख ने दिसानायके को 42.31 प्रतिशत मत हासिल करने में मदद की। यह श्रीलंका के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि दिसानायके बहुमत के समर्थन के बिना चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। उनकी तात्कालिक चुनौती आगामी चुनावों में संसदीय बहुमत हासिल करना होगा, जो उनके प्रशासन के लिए प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए महत्वपूर्ण है। श्रीलंका में इस परिवर्तन को भारत ने गंभीरता से लिया है। पीएम नरेन्द्र मोदी ने तुरंत बधाई दी, भारतीय उच्चायुक्त दिसानायके से मिले, नए राष्ट्रपति अनुरा ने भी भारत से मजबूत संबंध के प्रति श्रीलंका की प्रतिबद्धता दिखाई। कठिन आर्थिक संकट के समय भारत ने ही श्रीलंका की मदद की थी। चूंकि अतीत में जेवीपी का रुख भारत विरोधी रहा है, इसलिए भारत को अनुरा सरकार पर पैनी नजर रखनी होगी। वैसे श्रीलंका के सामने मालदीव का सबक है।

पं दीनदयाल के विचार मानवता के लिए प्रेरणादायक

जयंती विशेष
डॉ. रमन सिंह

एकात्म मानववाद के प्रणेता के रूप में एक ओर वे समकालीन विचारकों के बीच चमचमाते रत्न हैं। दूसरी ओर, भारतीय राजनीति में सकारात्मक, राष्ट्रवादी आग्रह और संस्कारित कार्य व्यापार के विकल्प प्रदाता के रूप में वरेण्य हैं। उनके बहुआयामी व्यक्तित्व की अनेक तेजोमय पश्मियां हैं। एक कुशल संचारक, पत्रकार, संपादक, प्रकाशक, लेखक, संगठनकर्ता, राजनेता और समाजसेवी के रूप में इन रश्मियों का आलोक हमें चमत्कृत कर देता है।

भारतीय संस्कृति की अप्रतिम विशेषता इसकी समरसता है। तरह-तरह की परंपराएं, भांति-भांति के लोग, व्यापार और लोक व्यवहार को समग्रता में देखना और स्वीकारना यहां सहज है। यही एक कारण है कि लोकतंत्र का वर्तमान संसदीय-स्वरूप हमारे यहां फल-फूल रहा है। कुछेक विसंगतियों और कमियों के होते हुए भी विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र के रूप में संसार-समाज हमें स्वीकार करता है। सन 1947 में अंग्रेजों से स्वतंत्र होने के बाद देश की राजनीति के विकास क्रम में इस वैचारिक परिष्कार को स्पष्ट देखा जा सकता है। पश्चिम-प्रेरित कांग्रेसवाद से भिन्न, अपनी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव से ओतप्रोत एक विकल्प रातो-रात खड़ा नहीं हुआ। इस प्रकृति की विचार गंगा को जो भगीरथ लोगों के बीच लाए ऐसे पं. दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम उस पंक्ति में बहुत श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है।

एकात्म मानववाद के प्रणेता के रूप में एक ओर वे समकालीन विचारकों के बीच चमचमाते रत्न हैं। दूसरी ओर, भारतीय राजनीति में सकारात्मक, राष्ट्रवादी आग्रह और संस्कारित कार्य व्यापार के विकल्प प्रदाता के रूप में वरेण्य हैं। उनके बहुआयामी व्यक्तित्व की अनेक तेजोमय पश्मियां हैं। एक कुशल संचारक, पत्रकार, सम्पादक, प्रकाशक, लेखक, संगठनकर्ता, राजनेता और समाजसेवी के रूप में इन रश्मियों का आलोक हमें चमत्कृत कर देता है।

वैश्वीकरण के इस दौर में पं. दीनदयाल जी के विचार धुर-पूंजीवाद और असत्याचल उन्मुख साम्यवाद, दोनों से आगे जाकर विश्व राजनीति की एक सकारात्मक, व्यावहारिक दिशा प्रदान करने में समर्थ हैं। वसुधैव कुटुम्बकम का आदर्श किस प्रकार से व्यवहार रूप में परिणित किया जा सकता है, उसे समझना हो तो पं. दीनदयालजी का समाजार्थिक और राजनीतिक चिन्तन हमें एक कुंजी देता है।

किसी विचारक की सबसे बड़ी सफलता यह होती है कि जब समाज में अपना वर्णन सामने रखे तो यह व्यवहारिक भी हो। दीनदयाल जी की पूरी सोच इस कसौटी पर खरी उतरती है। एक राजनीतिज्ञ और कार्यकर्ता के रूप में, हमने उनके विचारों का जब क्रियान्वयन किया तो यह बात हमारे सामने स्पष्ट हुई। जिस जमाने में अमेरिका से पीएल 48 के तहत नेहरू सरकार गेहूं आयात कर रही थी उस समय दीनदयालजी ने कृषि उत्पादन की विपुलता का सिद्धान्त सामने रखकर बताया था कि हमारे उपनिषदों में अन्न अधिक उपजाना एक व्रत या प्रण है। जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उस समय प्रदेश में सामने बार-बार पड़ने वाले अकाल की चुनौती थी। इस समस्या के समाधान के लिए दीनदयालजी की बातों को धरातल पर लाने सरकार ने ठानी। तय किया कि प्रदेश में धान सहित अन्य फसलों का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेंगे। योजनाबद्ध ढंग से कई कार्यक्रम चलाए गए। आज नतीजा आपके सामने है। दाने-दाने को तरसने वाला छत्तीसगढ़ लगातार धान और दलहन के रिकॉर्ड उत्पादन के लिए भारत सरकार का कृषि कर्मण अवार्ड पाता है। छत्तीसगढ़ अब अपनी खाद्यान की जरूरत पूरी करने के अलावा हजारों टन धान अपने देश, यहाँ तक कि विदेशों में निर्यात करने की स्थिति में आ चुका है।

व्यवहारिक सोच का यह अद्भुत गुण दीनदयालजी में क्यों आया? क्योंकि इनकी दृष्टि समग्र और व्यापक थी। वे समस्या को, परिस्थिति को किसी एक निश्चित कोण से नहीं देखते थे। वे मानते थे समग्रता में सार है। राष्ट्र के जीवन का हर दृष्टि से अध्ययन, जगह-जगह घूमना, लोगों से मिलना उनसे जुड़ना और उन्हें जोड़ना। ऐसी चमत्कृत कर देने वाली थी उनकी साधना। तब कहीं जाकर वे अंत्योदय जैसी सर्व-कल्याणकारी अवधारणा तक पहुंच पाए। पूरे विश्व-समाज को अखंड मंडलाकार रूप में उन्होंने तभी पहचान लिया था जब अर्थव्यवस्था में ग्लोबलाइजेशन का 'ग' भी शुरू नहीं हुआ था। वे समय के पार देख सकते थे, सोच सकते थे और उसको शब्द दे सकते थे।

दीनदयाल जी महज किसी दल या संगठन या देश-विशेष के ही गौरव नहीं हैं, वे सच्चे अर्थ में विश्व मानव हैं, जिनका विराट व्यक्तित्व पूरी मानवता को समर्पित है। ऐसे महान व्यक्तित्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 108वीं जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन करते हुए, हम सभी को उनके विचारों प्रेरणा लेकर 'अंत्योदय' की उनकी परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहिए।

-लेखक छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं।

सादा जीवन और दृढ़ संकल्प व्यक्तित्व के धनी

पंडित दीनदयाल उपाध्याय सादा जीवन, उच्च विचार और दृढ़ संकल्प व्यक्तित्व के धनी थे। वे एक मेधावी छात्र, संगठक लेखक, पत्रकार, विचारक, राष्ट्रवादी और एक उत्कृष्ट मानवतावादी थे। उनके सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में सबसे कमजोर और सबसे गरीब व्यक्ति की चिंता सदैव कचोटती थी।

गरीबों व मा भारती की सेवा करने के भाव को लेकर जबरदस्त उत्साह, जज्बे, जुनून और दृढ़ विश्वास के साथ, वे 1937 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में शामिल हुए। इसके बाद जनसंघ के महासचिव के रूप में राजनीति में कदम रखा और 29 दिसम्बर 1967 को जनसंघ के अध्यक्ष बने। उन्होने 1951 से 1967 तक इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया। यह देश में कांग्रेस का राजनीतिक विकल्प था।

उन्होंने स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी के एक मजबूत, जीवंत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के विचार को आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। पूंजीवाद और समाजवाद की जगह पण्डित दीन दयाल उपाध्याय ने स्वराज के रूप में गांधी जी द्वारा परिकल्पित नैतिक मूल्यों और लोकव्यवहार के आधार पर आर्थिक नीतियों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उनके लिए राजनीति जन सेवा का माध्यम थी। वे कहते थे कि राजनीतिक व्यक्ति को जन सेवक के रूप कार्य करना चाहिए।

स्वदेशी आर्थिक मॉडल को अपनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एकात्म-मानववाद को रेखांकित किया। इसमें समावेशी और जन समुदाय को सशक्त बनाने का विचार था। उनका मानना था कि स्वदेशी और लघु उद्योग भारत की आर्थिक योजना की आधारशिला होनी चाहिए, जिसमें सद्भाव, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय नीति और अनुशासन का समावेश हो। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने सुशासन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में व ग्रामीणों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में दीन दयाल उपाध्याय जी के पदचिन्हों का अनुसरण किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 'लोकल से वोकल' का सपना देखना वास्तव में हमारे लिए खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी की इस सोच में पण्डित दीन दयाल जी के विचार पूरी तरह झलकते है।

जयंती

अशोक बजाज

प्रधानमंत्री आवास : अंत्योदय की उपज

महान विचारक एवं राजनीतिक चिंतक पं. दीनदयाल उपाध्याय ने समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए 20 वी सदी में अंत्योदय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, उन्होंने जब महसूस किया कि देश में अमीरी व गरीबी के बीच की खाई दिनों दिन गहरी होती जा रही है। एक ओर जहां समाज में ऐसे लोग हैं जिसके पास बेशुमार धन संपदा है वहीं दूसरी ओर एक बड़ा तबका ऐसा भी है जिसकी कमाई सीमित है, उनके लिए अपनी दैनंदिनी की आवश्यकता की आपूर्ति करना कठिन और दुष्कर है। यह तबका आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है । इन्हें अपनी आजीविका के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। इनका अपना कोई आशियाना भी नहीं है। अंग्रेजी हुकूमत ने इस वर्ग का काफी आर्थिक शोषण किया. उस दौर में इन्हें ना ही अपने श्रम का उचित मूल्य मिलता था और ना ही सम्मानजनक जीने का अवसर। अतः वे जमींदारों व साहूकारों के चंगुल में फंस कर गरीबी, बेकारी व भुखमरी के शिकार हो गए। उन्हें अपने जीवन यापन के लिए बंधुआ मजदूरी भी करनी पड़ी। अमीरी व गरीबी की खाई के साथ में सन 1947 में आजाद भारत का जन्म हुआ लेकिन आजादी के बाद भी यह समस्या नासूर बनी रही। इस व्यवस्था से व्यथित पं. दीनदयाल ने कहा कि आर्थिक असमानता की खाई को पाटने के लिए आवश्यक है कि हमें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के उत्थान की चिन्ता करनी चाहिए क्योंकि 'अर्थ का अभाव और अर्थ का प्रभाव' दोनों समाज के लिए घातक है। पं. दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि हमारे प्रयास और हमारी विकास की योजनाएं ऐसी हों कि समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का विकास पहले हो। समाज के उपेक्षित व शोषित व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़कर आर्थिक समानता स्थापित करने का काम अन्त्योदय के सिद्धांत से ही हो सकता है। पं. दीनदयाल जी ने इस आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए 'अंत्योदय' के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा कि 'हमारी भावना और सिद्धांत है कि वह मैले कुचैले, अनपढ़ लोग हमारे नारायण हैं, हमें इनकी पूजा करनी है, यह हमारा सामाजिक व मानव धर्म है। जिस दिन हम इनको पक्के सुंदर, स्वच्छ घर बनाकर देंगे, जिस दिन इनके बच्चों और स्त्रियों को शिक्षा और जीवन दर्शन का ज्ञान देंगें, जिस दिन हम इनके हाथ और पांव की बिवाईयों को भरेंगें और जिस दिन इनको उद्योगों और धर्मों की शिक्षा देकर इनकी आय को ऊंचा उठा देंगें, उस दिन हमारा मातृभाव व्यक्त होगा।' उनका मत था कि हमारी नीतियां, योजनाएं व आर्थिक कार्यक्रम कमजोर लोगों को ऊपर लाने की होनी चाहिए ताकि वे भी समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें और उन्हें भी समाज के अन्य वर्ग के साथ बराबरी में खड़े होने का अवसर मिल सके।

मोदी सरकार ने सामान्य लोगों के आत्मगौरव और आत्मविश्वास को बढ़ाने तथा उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने वाली अंत्योदय प्रेरित योजनाओं पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। इन दिनों शिक्षा, स्वास्थ्य व आर्थिक विकास की असंख्य योजनाएं देश भर में चल रही है। यह अंत्योदय प्रेरित योजना है जिसमें गरीब और बेघर लोगों को अपना खुद का घर बनाने के लिए सरकारी सहायता का प्रावधान है। इस योजना के तहत पिछले 10 सालों में पात्र गरीब परिवारों के लिए लगभग 4 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। पी.एम.ए.वाई. के तहत, लाभार्थियों का चयन सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना (SECC) 2011 के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। भारत सरकार ने अभी अभी इस योजना में बदलाव कर इसका दायरा बढ़ा दिया है। नए नियम के अनुसार जिन नागरिकों के पास ट्रू व्हीलर, मछली पकड़ने की नाव, रेफ्रीजरेटर, लैंडलाइन फोन है या जिनकी आय 15,000 रुपए प्रतिमाह तक है उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र माना जाएगा। इसके साथ साथ ही जिनके पास ढाई एकड़ सिंचित या पांच एकड़ असिंचित भूमि है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगें. यह मोदी सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसका क्रियान्वयन उन व्यक्तियों को लक्ष्य करके किया गया है जिन्हें पं. दीनदयाल उपाध्याय ने 'समाज के अंतिम व्यक्ति' की संज्ञा देकर सबसे पहले उनके उदय (विकास) की बात रखते हुये अंत्योदय का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। मोदी सरकार लक्ष्य अन्त्योदय, प्रण अन्त्योदय व पथ अन्त्योदय के ध्येय के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं - 'घर की चाबी सम्मान, आत्मविश्वास, सुनिश्चित भविष्य, नई पहचान और बढ़ती संभावनाओ के द्वार खोलती है'। वास्तव में हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसका स्वयं का एक पक्का आशियाना हो। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ कर गरीबों के इस सपने को साकार करने का काम किया है। पं. दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय प्रधानमंत्री आवास के रूप में फलीभूत हो रहा है। वास्तव में उनका यह सिद्धांत 21 वी सदी में विकसित भारत का आधार बन चुका है।

-लेखक पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत, रायपुर

सफलता पाने क्यों मन पर अंकुश लगाना ज़रूरी है?

संकलित
दर्शन

मन अधिक चंचल है, क्योंकि वह माया में रमा हुआ है। उसे जीवन सफलता के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए बड़े अंकुश की आवश्यकता होती है। परमात्मा के भय से बड़ा कोई नियंत्रक नहीं है। वह दृष्टिगोचर नहीं है। फिर भी सर्वव्यापी है। उसके कोई अधिकारी नहीं हैं। फिर भी उसका राज्य अनंत एवं व्यवस्था अति सुचारु है। उसने कोई संविधान नहीं बनाया। फिर भी वह गुण-दोष परखकर फल देता जा रहा है। परमात्मा अंतर्यामी है। कुछ भी उसकी दृष्टि से ओझल नहीं है। उसका न्याय होकर रहता है। सांसारिक विधानों से बचा जा सकता है, किंतु परमात्मा की परम शक्ति से नहीं। परमात्मा की सत्ता को स्वीकार कर उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना ही दंड से बचने का एकमेव उपाय है। परमात्मा निराकार है, किंतु उसका कौतुक जीवन को प्रत्यक्षतः प्रभावित करता है। परमात्मा का सबसे बड़ा प्रभाव मनुष्य का तन है, जो पांच तत्वों जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश के संयोग से बना है। ये पांचों तत्व परस्पर विपरीत प्रकृति के हैं। वे एक साथ नहीं रह सकते। परमात्मा की ही महिमा है कि एक साथ जीव के तन में बस रहे हैं। इससे बड़ा चमत्कार कोई और नहीं हो सकता। परमात्मा ने अगण्य जीव रचे हैं और नित्य रचता जा रहा है। वह जीवों को रचता ही नहीं, उनका प्रतिपालन भी करता है। उसकी कृपा एवं उसका दंड पल-पल संसार में प्रकट होते हैं। वह राजा से रंक, रंक से राजा, ज्ञानी से अज्ञानी एवं अज्ञानी से ज्ञानी बना रहा है। उसकी लीला वही जानता है।

दान की बड़ी महिमा

संकलित
प्रेरणा

एक बार राजा भोज एक जंगल के रास्ते से जा रहे थे। साथ में उनके राजकवि पंडित धनपाल भी थे। रास्ते में एक विशाल बरगद के पेड़ में मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा छत्ता लगा था। जो शहद के भार से गिरने ही वाला था। राजा भोज ने ध्यान से देखा तो पाया कि मधुमक्खियां उस छत्ते से अपने हाथ पैर घिस रही हैं। उन्होंने राजकवि से इसका कारण पूछा। राजकवि बोले- महाराज ! दान की बड़ी महिमा है। शिवि, दधीचि, कर्ण, बलि आदि अनेक दानियों का नाम उनके न रहने के बाद भी चल रहा है। दधीचि ने तो वज्र बनाने के लिए इंद्र को अपना कंकाल तक दान कर दिया था। कर्ण को आज सभी सबसे बड़े दानी के रूप में जानते हैं। जबकि केवल संचय करने और दान न करने वाले बड़े बड़े राजा महाराजाओं का आज कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। इन मधुमक्खियों ने भी आजीवन केवल संचय ही किया है, कभी दान नहीं किया। इसलिए आज अपनी संपत्ति को नष्ट होते देखकर इन्हें दुःख हो रहा है। इसीलिए ये अपने हाथ पैर घिस रही हैं। अतः आवश्यकता से अधिक संचय हमेशा दुःख का कारण होता है। संचय किए हुए धन पर हमेशा राज दूसरे ही करते हैं, अतः कहा गया है की आप जितनी कमाई करते है उसका कुछ भाग अवश्य दान करें।

अंतर्मन

आज की पाती

आयुष्मान योजना की कमियों को दूर किया जाए

देश को मुफ्त इलाज की सुविधा देने के लिए केंद्र सरकार ने जो आयुष्मान योजना आरंभ की थी, उसके छह साल पूरे हो गए। इन छह सालों में यह योजना कितनी कामयाब रही, इस पर सभी के अपने-अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने हाल ही में इस योजना का विस्तार करते हुए इसके अंतर्गत 70 साल से ऊपर हर वर्ग के बुजुर्गों को इसमें शामिल किया। यह सरकार का बहुत ही अच्छा प्रयास है और उम्मीद है कि भविष्य में सरकार इस योजना का विस्तार करेगी जिससे देश के हर नागरिक को इसका लाभ पहुंचेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माना है कि भारत में प्रति व्यक्ति औसतन लगभग 6500 रुपए बीमारियों पर ही बर्बाद होते हैं। आयुष्मान योजना की कमियों को दूर किया जाना चाहिए। - *सत्येंद्र त्रिपाठी, दुर्ग*

ट्रेंड

यूएसए यात्रा उपयोगी

वह एक उपयोगी यूएसए यात्रा रही है, जिसमें विविध कार्यक्रमों को शामिल किया गया और हमारे यह को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। -नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

रोजगार के अवसर छीने

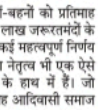

10 वर्षों से बाजपा ने हरियाणा समेत देशभर के युवाओं से रोजगार के अवसर छीनकर उनके साथ धोखेबाज़ी किया है। टूटे वादों और हारे मन से बाजपा लोकर युवा 'वादाखाफ़ी' को याद कर रहे है। मासूम लौटने पर उनके परिवार से मिला तो उनकी आंखों ठर से छलक उठीं। -राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद

जयंती

भावना बोहरा

नए भारत के निर्माण की राह दिखाने वाले पंडित दीनदयाल

पं. दीनदयाल उपाध्याय भारतीय राजनीति के एक प्रमुख विचारक हुए जिन्होंने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीयता और अंत्योदय के विकास पर देश की राजनीति को एक नई दृष्टि दी। 'अंत्योदय' का सिद्धांत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए समर्पित है।

स्वतंत्रता के बाद एक तरफ जहां भारत प्रगति के नए सपने देख रहा था वहीं दूसरी ओर समाज की पंक्ति में आगे खड़े लोगों की दुर्दशा पंडित जी को बेचैन कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि देश की तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था इस अंतर को मिटाने में सक्षम नहीं है क्योंकि व्यवस्था का दृष्टिकोण भारतीय नहीं है। इस उद्देश्य से उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए अंत्योदय को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। दीनदयाल जी का मानना था कि विकास का असली मतलब केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, बल्कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग के उत्थान में है। किसी भी समाज की सच्ची प्रगति उस समाज के अंतिम व्यक्ति की भलाई से मापी जाती है। दीनदयाल जी के अंत्योदय का सिद्धांत न केवल आर्थिक विकास पर केंद्रित है, बल्कि इसमें सामाजिक न्याय और समानता भी शामिल है। उपाध्याय का मानना था कि जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति अपने अधिकारों और संसाधनों से वंचित रहेगा, तब तक वास्तविक विकास संभव नहीं है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों से प्रेरित और अंत्योदय के प्रति समर्पित हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी राष्ट्रनिर्माण की दिशा में अपने तीसरे कार्यकाल में सतत समर्पित हैं। विगत 10 वर्षों में श्री मोदी जी को सरकार ने देश के अन्नदाताओं के लिए किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रतिमाह 6000 रुपए की राशि सुनिश्चित की है, जिसके माध्यम से 2.25+ लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में जमा हुए हैं। इसके साथ ही श्री मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। इसके साथ ही लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए श्री मोदी जी ने 33% आरक्षण की सौगात भी दी है। तीन तलाक से मुस्लिम महिलाओं को आजादी दिलाने से लेकर गांव-गरीब-मजदूर तक ढेरों योजनाएं संचालित कर माननीय श्री मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को धरातल पर साकार किया है।

छत्तीसगढ़ में इसी अंत्योदय के विचार पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जरूरतमंदों के लिए 1 किलो चावल, निशुल्क नमक, आदिवासी अंचल में निःशुल्क चरण पादुकाओं का वितरण समेत ढेरों योजनाएं संचालित की। इसके साथ ही आज माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में प्रदेश की 70 लाख माताओं-बहनों को प्रतिमाह 1000 का आर्थिक सहयोग, 18 लाख जरूरतमंदों के लिए प्रधानमंत्री आवास समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं आज छत्तीसगढ़ का नेतृत्व भी एक ऐसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के हाथ में हैं। जो अंत्योदय के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं वह आदिवासी समाज जिसे पंक्ति में सबसे पीछे समझा जाता था आज वह हम सभी छत्तीसगढ़वासियों का नेतृत्व कर रहे हैं।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत में स्वावलंबन की भावना भी निहित है, ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उन्होंने शिक्षा को अंत्योदय के लिए एक महत्वपूर्ण साधन माना। उनका मानना था कि शिक्षा ही लोगों को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक कर सकती है।

दीनदयाल उपाध्याय का जीवन और उनके विचार भारतीय समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। उनका अंत्योदय का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है और यह दर्शाता है कि समाज के अंतिम व्यक्ति की भलाई के बिना सच्चा विकास संभव नहीं है। उपाध्याय जी की सोच और दृष्टि हमें यह सिखाती है कि एक सशक्त और समान समाज की स्थापना के लिए हमें मिलकर प्रयास करना होगा। उनके विचारों को अपनाकर हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहाँ हर व्यक्ति का सम्मान हो और हर किसी के अधिकार सुरक्षित हों।

-लेखक विधायक, पंडरिया विधानसभा

दैनिक जागरण

क्षमा दान ही अपने मन को शांत करने की औषधि है

जलने लगी पराली

अभी मानसून की विदाई ही हुई है, लेकिन पंजाब में फसलों के अवशेष यानी पराली जलनी शुरू हो गई। यह इसलिए अनपेक्षित है, क्योंकि आम तौर पर पंजाब में अक्टूबर के पहले सप्ताह से पराली जलाने का सिलसिला शुरू होता है। यह ठीक है कि पंजाब में पराली जलाए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और उसने बायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से स्पष्टीकरण भी मांग लिया, लेकिन इसके आसार कम ही हैं कि उसे कोई संतोषजनक जवाब मिल सकेगा और पंजाब में पराली जलाने के सिलसिले को थामा जा सकेगा। पंजाब में पराली जलाए जाने से यही पता चलता है कि अभी तक वहां ऐसे प्रबंध नहीं किए जा सके हैं कि किसानों को फसलों के अवशेष न जलाने पड़ें और यदि वे ऐसा करें तो उन्हें इससे रोका जा सके। यह निराशाजनक है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि में पराली को जलाने से रोकने के लिए पिछले कई वर्षों से तमाम प्रयत्न किए जा रहे हैं, लेकिन वे प्रभावी नहीं सिद्ध हो पा रहे हैं। चिंताजनक यह है कि इन राज्यों की देखादेखी अन्य राज्यों में भी पराली जलाई जाने लगी है। ऐसा इसीलिए हो रहा है, क्योंकि किसानों के समक्ष ऐसे उपाय पेश नहीं किए जा सके हैं, जिससे उन्हें पराली न जलानी पड़े।

चूंकि पंजाब, हरियाणा आदि में पराली जलाए जाने से उठने वाला धुआं देश की राजधानी में बायु की गुणवत्ता को कहीं अधिक प्रभावित करता है, इसलिए केंद्र सरकार भी सक्रियता दिखाती है और सुप्रीम कोर्ट भी, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सर्दियों में दिल्ली समेत उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा बायु प्रदूषण की चपेट में आ जाता है और बह लोगों के स्वास्थ्य के लिए संकट पैदा करता है। हैरानी नहीं कि इस बार भी ऐसा ही हो, क्योंकि लगता नहीं कि सभी राज्यों ने ऐसे प्रबंध कर लिए हैं, जिससे पराली न जले। यह ध्यान रहे कि सर्दियों में बायु की गुणवत्ता केवल पराली जलाए जाने से ही प्रभावित नहीं होती। इसके अतिरिक्त बह सड़कों एवं निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल, बाहनों के उत्सर्जन और कूड़ा-करकट जलाने से भी प्रभावित होती है। अच्छा होगा कि प्रदूषण रोधी एजेंसियां पराली को जलाए जाने से रोकने के अतिरिक्त बायु प्रदूषण के अन्य कारणों का भी निवारण करें। निःसंदेह सुप्रीम कोर्ट को भी इस ओर ध्यान देना होगा। उसे दिल्ली के साथ शेष देश के पर्यावरण की भी चिंता करनी होगी।

इस क्रम में यह भी समझना होगा कि यदि बायु प्रदूषण की चिंता केवल सर्दियां आने पर ही की जाएगी तो अपेक्षित नतीजे नहीं मिल सकते। बायु प्रदूषण से निपटने की तैयारी वर्ष भर करनी होगी, क्योंकि अब बरसात को छोड़कर देश के बड़े हिस्से बायु की खराब गुणवत्ता से जूझते रहते हैं। बायु प्रदूषण केवल जनजीबन पर ही बुरा असर नहीं डालता, बल्कि बह देश की छबि भी मलिन करता है।

सुरक्षित सफर की चुनौती

उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मामले में देर से सही परिबहन विभाग और पुलिस की नींद टूटती दिख रही है। इन विभागों को अब समझ आ रहा है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी के लिए सभी श्रेणियों के मार्गों का सुरक्षा आडिट जरूरी है। कहा जा रहा है कि इन पर दुर्घटनाओं के लिहाज से संबेदनशील क्षेत्रों को चिह्नित किया जाएगा। यह बात भी विभागों में तब समझ आई, जब पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक में पेच कसे। विभागों से दुर्घटनाओं के संबंध में मार्गबार बिबरण जुटाने को कहा गया है। कहां-कहां दुर्घटनाएं अधिक हो रही हैं और इनकी प्रकृति क्या है, इसका अध्ययन कराया जा रहा है। यह ठीक है कि मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद परिबहन और पुलिस बिभाग ने इस दिशा में नए सिरे से काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन यह प्रश्न अपनी जगह बना हुआ है कि विभागों ने इस पर स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया। आंकड़े गबाही दे रहे हैं कि सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ रहा हैं। पिछले आठ महीने के अंतराल में राज्य में तकरीबन आठ सौ दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। पिछले दो सालों की तुलना में यह पच्चीस फीसद अधिक है। इनमें कुछ दुर्घटनाएं तो चालकों की लापरबाही के कारण हुई हैं, पर बड़ा आंकड़ा उनका भी है जिनकी बजह सड़कों की तकनीकी खामी रही है। ऐसे स्थल ब्लैक स्पाट की श्रेणी में रखे गए हैं, पर इनमें से ज्यादातर का समुचित उपचार नहीं हुआ है। अब जबकि दुर्घटनाओं के लिहाज से खतरनाक क्षेत्रों का फिर से ब्योरा जुटाया जा रहा है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि यह आंकड़े फाइलों तक ही सीमित नहीं रहेंगे। इनके उपचार की दिशा में भी बिभाग तत्परता दिखाएंगे। अन्यथा, इस कसरत का कोई फायदा नहीं होने बाला। राज्य सरकार को इसकी नियमित मानीटरिंग की व्यबस्था करनी चाहिए। जनता के बीच इस बात का स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि सफर सुरक्षित बनाने की दिशा में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है।

सरकारी नियंत्रण से मुक्त हों मंदिर

विकास सारस्वत

तिरुपति प्रसाद प्रकरण दर्शाता है कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्ति मिलनी चाहिए

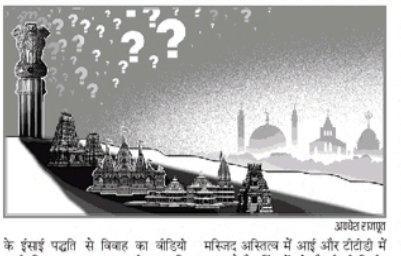

अवधेश राजपूत

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बीते दिनों यह कह कर सनसनी फैला दी कि पूर्ववर्ती जगनमोहन रेड्डी के शासन में तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद में चर्बी युक्त घी का प्रयोग हुआ था। उल्लेखनीय है कि तिरुपति मंदिर का प्रबंधन तिरुमला तिरुपति देबस्थानम यानी टीटीडी नामक सरकारी ट्रस्ट करता है। टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी जे. श्यामला राब ने बताया कि नई सरकार बनने के बाद टीटीडी के नए कार्यकारी अधिकारी के रूप में उन्होंने प्रसाद में प्रयोग होने बाले घी की गुणबत्ता जांचने के आदेश दिए थे। घी के पांच आपूर्तिकर्ताओं में से एक एआर डेरी के नमूनों में घोर अनियमितता मिली। घी की शुद्धता एवं बैल्यू में मापी जाती है और इसका निर्धारित मानक 95.68 से लेकर 104.32 के बीच रहना चाहिए, लेकिन एआर डेरी के सैंपल की एस बैल्यू मात्र 19.72 पाई गई। सैंपल के इतने निम्न स्तर को देखते हुए उसके घी में बसा यानी बीफ टैलो, सुअर की चर्बी और मछली के तेल के मिश्रण की आशंका व्यक्त की गई। यहां यह उल्लेख करना आबश्यक है एआर डेरी को ही द्रमुक शासनकाल में तमिलनाडु के पलनी मंदिर में भी घी आपूर्ति का ठेका मिला है।

हालांकि जगन रेड्डी और एआर डेरी ने आरोपों को निराधार बताया है, परंतु नमूनों की लैब रिपोर्ट कुछ और ही कहानी कहती है। यह सबाल उठना स्वाभाबिक है कि तिरुपति जैसे संपन्न मंदिर में जिस प्रसाद को श्रद्धालु पैसे देकर खरीदते हैं, बहां सरकारी कंपनी केमएफ के भरोसेमंद उत्पाद नंदिनी को छोड़कर अनजान आपूर्तिकर्ताओं से घी क्यों लिया गया? हिंदू बिरोधी छबि से ग्रस्त जगन रेड्डी और द्रमुक सरकारों द्वारा एक ही डेरी को अनुबंधित करना भी असामान्य लगता है। घी में पशु चर्बी होने का आरोप अत्यधिक गंभीर है। ध्यान रहे कि अतीत में घीखे से गोमांस खिलाकर हिंदुओं के सामने मतांतरण माफिया ने धर्म भ्रष्ट होने का डर और ऐसी स्थिति में मतांतरण को ही एकमात्र समाधान बताकर पेश किया है। जगन द्वारा आरोपों के खंडन पर इसलिए भी भरोसा मुश्किल है, क्योंकि टीटीडी पर कब्जे और उसकी गतिबिधियों में जगन एवं मुख्यमंत्री रहे उनके पिता बाई. सैमुअल राजशेखर रेड्डी का रिकार्ड बिबादास्पद रहा है। ईसाई मूल के पिता-पुत्र ने ऐसे दो लोगों को टीटीडी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया, जिन पर ईसाई होने के आरोप लगे। हालांकि इन दोनों अधिकारियों करुणाकर रेड्डी भूमना और बाईबी सुब्बा रेड्डी ने इन आरोपों का खंडन किया, परंतु भूमना की पुत्री के ईसाई पद्धति से बिबाह का बीडियो सार्वजनिक हुआ था। नक्सली पृष्ठभूमि से आए करुणाकर रेड्डी का ऐसा बयान भी सार्वजनिक है, जिसमें उन्होंने भगवान बेंकटेश्वर की मूर्ति को काला पत्थर बताकर उसे चप्पल से पीटने की बात कही है। पेरियार सरोखे घृणित बयान देने बाले व्यक्ति को पिता और पुत्र ने दो बार टीटीडी का अध्यक्ष बनाया।

रेड्डी पिता-पुत्र की मंशा पर इसलिए भी सबाल उठते हैं, क्योंकि वह अपने खास रिश्तेदारों को टीटीडी अध्यक्ष पद पर कायम रखना चाहते हैं। भूमना और बाईबी रेड्डी दोनों ही जगन के करीबी रिश्तेदार हैं। तिरुपति स्थित तिरुमला की सात पहाड़ियों को भगबान बेंकटेश्बर का पृथ्बी पर निबास माना गया है और यहां किसी और मजहब के उपासना स्थल बनाने की मनाही है, लेकिन राजशेखर रेड्डी के मुख्यमंत्री काल और करुणाकर रेड्डी के टीटीडी कार्यकारी अधिकारी रहते दोनों ने पबित्र क्षेत्र को केबल दो पहाड़ियों तक सीमित करने के प्रयास किए। उसी दौरान तिरुपति में कई चर्च और एक बड़ी मस्जिद अस्तित्व में आई और टीटीडी में बहुत से गैर-हिंदुओं की नौकरी भी मिली। इसके साथ ही तिरुपति में अम्यूजमेंट पार्क जैसे मनोरंजन स्थलों को बढ़ाबा देकर हिंदू आस्था के एक बड़े तीर्थ की पबित्रता को हल्का करने का प्रयास भी हुआ।

तिरुपति प्रसाद पर पैदा हुआ बर्तमान बिबाद हिंदू आस्था पर भीषण आघात है। श्रीश्री रबिशंकर समेत कई आध्यात्मिक गुरुओं ने इस प्रकरण की तुलना 1857 की क्रांति में गोमांस से भरे कारतूसों के उपयोग से पैदा हुए उत्तेजनात्मक कृत्य से की है। यह दुखद स्थिति इसलिए भी निर्मित हुई, क्योंकि सरकारी नियंत्रण होने के कारण बड़े-बड़े मंदिर गैर हिंदू और नास्तिकों के कब्जे में आते रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब तक किसी संस्थान को लेकर स्पष्ट कानून न हो, संबिधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत वे सभी संस्थान भी राज्य की परिभाषा में आ जाते हैं, जिन पर स्थायी या अस्थायी रूप से सरकारी नियंत्रण हो। ऐसे में नियुक्तियां, खरीद और प्रबंधन इत्यादि पर राजकीय नीतियां ही लागू होती हैं। इस कारण गैर-हिंदुओं की नियुक्तियां कानूनसम्मत हो जाती हैं, जिनका उपयोग बुरी नीयत बाले नेता हिंदुओं को मूंह चिढ़ाने और उनकी आस्था को रौंदने के लिए करते हैं। आज तिरुपति प्रसाद में चर्बी मिलाने का मामला है तो कभी मंदिरों से मूर्तियों की तस्करी, गहने चुराने और मंदिरों की जमीन हड़पने की खबरें आती रही हैं।

तिरुपति मंदिर के ठीक सामने ईसाईयत के प्रचार को बढ़ाबा दिया गया है। मंदिरों पर श्रद्धापूर्वक चढ़ाए गए चढ़ाबे का गैर-धार्मिक कार्यों में किया गया उपयोग दानराशि की सरकारी लूट का माध्यम बन गया है। तिरुपति में हुए हालिया अनाचार के बाद यह चौंकाने बाला तथ्य सामने आया कि सलाना करीब 1,200 करोड़ रुपये का चढ़ाबा प्राप्त करने बाले मंदिर में प्रसाद समग्री की गुणबत्ता जांचने के लिए एक छोटी सी प्रयोगशाला भी नहीं है। इस प्रकरण में जिस तरह हिंदू भाबनाओं को रौंदा गया, उसे देखते हुए दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, जो एक मिसाल बने। इसके साथ ही हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्ति भी मिलनी चाहिए। इसके लिए यह भी आबश्यक है कि हिंदू समाज स्वयं सरकार के समक्ष मंदिर प्रबंधन और प्रशासन का एक सर्बसमाबेशी और मजबूत खाका पेश करे। यदि इतने गंभीर प्रकरण के बाद भी मंदिरों को हिंदू नियंत्रण में बापस देने की कबायद शुरू नहीं होती तो इस प्रकरण पर उपजा आक्रोश व्यर्थ है। अन्य समुदायों को अपने धर्मस्थलों की देखरेख का जैसा अधिकार है, आखिर बैसे हिंदुओं को क्यों नहीं है?

(लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य एवं बरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

नई विभाजक रेखाएं खींचने की कोशिश

राजीव सचान

बेलगाम हो रही जाति, पंथ और भाषा के सहारे की जाने वाली विभाजनकारी राजनीति

राहुल गांधी के बयान का विरोध करते सिख। एएनआइ

अपने देश में बिभाजनकारी राजनीति नई नहीं है। हम भारतीय तो इसे बिस्मृत कर ही नहीं सकते कि किस तरह इसी राजनीति ने भारत का बिभाजन कराया। तब केबल हिंदुओं और मुसलमानों को ही अलग-अलग कौम यानी राष्ट्र ही नहीं बताया गया था, बल्कि हिंदू और उर्दू में भी भेद पैदा कर यह साबित करने की कुचेष्टा की गई थी कि उर्दू मुसलमानों और हिंदी हिंदुओं की भाषा है। ऐसी ही बिभाजनकारी राजनीति नए सिरे से सिर उठाती दिख रही है। यदि कोई यह कहे कि भारत में अन्य भारतीय भाषा भाषियों पर हिंदी को न केबल थोपा जा रहा है, बल्कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि बोलने बालों से यह भी कहा जा रहा है कि उनकी भाषा, उनकी संस्कृति और उनका खानपान कमतर है तो यह हर दृष्टि से एक बिभाजनकारी और बैमनस्य पैदा करने बाला बयान है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का काम पहले भी किया गया है, लेकिन यह पहली बार सुनने को मिल रहा है कि अन्य भारतीय भाषा भाषियों से कहा जा रहा है कि उनकी भाषा के साथ उनकी संस्कृति और उनका खानपान भी कमतर है। कहना कठिन है कि राहुल गांधी के पहले भाषा को लेकर इतनी बेतुकी और भड़काऊ बात किसने कही थी। अपने हालिया अमेरिका दौरे के दौरान वह केबल यहीं तक सीमित नहीं रहे। बहां उन्होंने यह भी समझाने की कोशिश की कि भारत में सिखों के सामने कड़ा, पगड़ी धारण करने और गुरुद्वारे जाने का संकट खड़ा हो सकता है। इसका बिरोध हुआ तो उन्होंने पंजाब कांग्रेस के नेताओं प्रताप सिंह बाजबा और चरणजीत सिंह चन्नी को अपने कहे को सही ठहराने के लिए मैदान में उतार दिया। इस दौरान प्रताप सिंह बाजबा यह बोले कि केंद्र सरकार ने पंजाब की आर्थिक नाकाबंदी कर रखी है और चन्नी ने यह समझाया कि मोदी सरकार पंजाब की खेती को नष्ट करना चाहती है। ऐसे बयान खालिस्तान समर्थकों के मन की मुराद पूरी करने बाले ही हैं।

यह आश्चर्यजनक नहीं कि खालिस्तानी आतंकी गुरपतबंत सिंह पन्नू ने राहुल गांधी के बयान से सहमति जताई। इसके बाद भी पिछले दिनों राहुल को और से यही कहा गया कि उन्होंने अमेरिका में सिखों को लेकर जो कुछ कहा था, उस पर बह कायम हैं। इसके पहले जब बह जून 2023 में अमेरिका गए थे, तब उन्होंने कहा था कि भारत में अल्पसंख्यकों और एससी-एसटी समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। तब बह कांग्रेस के सांसद भर थे। अब नेता प्रतिपक्ष भी हैं। राहुल गांधी पिछले कुछ समय से जाति गणना पर भी जोर देने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के साथ अन्य अनेक दल भी जाति गणना की मांग कर रहे हैं और अब तो राष्ट्रीय स्वयंसेबक संघ ने भी यह कह दिया है कि जाति गणना होती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। पता नहीं कि जनगणना के साथ जाति गणना होगी या नहीं, लेकिन यदि कोई यह समझा रहा है कि इससे देश की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो ऐसा होने बाला नहीं। इसके बाद भी यदि कोई ऐसा ही मानकर चलता है तो उसे ऐसा मानने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन जाति गणना की मांग करते हुए यह माहौल बनाना शुद्ध बिभाजनकारी राजनीति है कि दलित छात्र इसलिए फेल हो जाते हैं, क्योंकि ऊंची जाति के लोग प्रश्नपत्र तैयार करते हैं।

अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने यह कहानी सुनाई थी कि अमेरिका में आइआइटी जैसी एक परीक्षा में अश्बेत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि प्रश्नपत्र श्बेत लोग बनाते थे। फिर एक बार अश्बेतों ने प्रश्नपत्र बनाया तो सारे गोरे फेल हो गए। यह काल्पनिक कहानी सुनाने के बाद उनका कहना था, 'अगर आइआइटी में अपरकास्ट लोगों के बनाए प्रश्नपत्र के कारण दलित छात्र फेल हो रहे हैं तो एक बार दलितों से प्रश्नपत्र बनबा कर देखें।' भारत में जाति के सहारे जातीय बैमनस्य फैलाने की राजनीति पहले भी होती रही है। अनेक दल ऐसे हैं, जो जाति आधारित राजनीति करने के लिए ही जाने जाते हैं। जाति की यह राजनीति अब ऐसे दौर में पहुंचती दिख रही है कि हर किसी की जाति खोजी जा रही है और यहां तक कि अपराधियों की जाति का उल्लेख कर यह माहौल बनाया जा रहा है कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। यह माहौल कुछ इस तरह बनाया जा रहा है कि बिभिन्न जातियों के बीच बैमनस्य पैदा होने का खतरा उभरने लगा है।

जातिबादी राजनीति के चलते सोशल नेटबर्क साइट्स पर ऐसे हैंडल लगातार बढ़ रहे हैं, जो दूसरे जाति बालों को निशान बनाते हैं, उन पर छींटाकशी करते हैं और उन्हें नीचा दिखाते हैं। हाल के समय में इसका सिलसिला महिला पहलबानों के धरना-प्रदर्शन के समय शुरू हुआ था। लोकसभा चुनाब के समय इसने अन्य जातियों को भी अपनी घपेट में ले लिया। लोकसभा चुनाब खत्म हो गए, लेकिन यह सिलसिला थमने के बजाय और तेज होता दिख रहा है। अब इसमें एससी-एसटी आरक्षण में उपबर्गीकरण के समर्थक और बिरोधी भी शामिल हो गए हैं। खतरा इसका है कि जातीय और भाब कहीं इंटरनेट की दुनिया से निकलकर जमीन पर न उतर आए। जातियों भारतीय राजनीति की एक सच्चाई हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाए और उनके बीच बैमनस्य पैदा किया जाए। ऐसा लगता है कि भारतीय समाज की पुरानी बिभाजक रेखाओं को कुरेदने के साथ नई बिभाजनकारी रेखाएं खींची जा रही हैं। बिडंबना यह है कि जो बिपक्षी दल भाजपा पर बिभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाते हैं, बे खुद ऐसी ही राजनीति न केबल खुलकर कर रहे हैं, बल्कि उसकी धार तेज भी कर रहे हैं।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

जीवन की राह

मृत्यु जीबन का सबसे बड़ा सत्य है। इस सत्य को जानते हुए भी हम अपनी नासमझी के कारण रोज किसी न प्रकार मरते रहते हैं। कभी हताशा से तो कभी हमें अहंकार मार देता है। कभी कुंठा हमें मार देती है। कभी चिंता में मरते हैं तो कभी सपने में मरते हैं। इतनी सारी समस्याओं के बीच जिंदगी जीना मानो पैराशूट लेकर बिमान से कूदने जैसा साहस भरा काम है। हालांकि जिन्हें जीबन की मूल्यबत्ता का बोध है, बे जीबन के हर पल का सम्मान करते हैं। दुखों का जलजला हो या सुनामी की लहरें, ये लोग उभरते जीबन को टूटने नहीं देते। यादृ रहे कि जीने के लिए भोजन, पानी, बायु जरूरी हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आयु, जबकि मरने के लिए कुछ भी नहीं। केबल एक क्षण।

उम्र पाना एक पहलू है और उस उम्र तक जीना दूसरा पहलू है। उम्र चाहे बढ़ रही हो, परंतु जिंदगी घट रही है। उम्र तब तक बढ़ती जाएगी जब तक कि जीबन डोर है, किंतु जीना अपनी समझ, दृष्टि और बोध पर आधारित है। जब तक हम जीबन को समझपूर्बक नहीं जिएंगे तब तक यही कहा जाएगा कि लंबी उम्र तो पाई, किंतु यह कहना मुश्किल है कि हमने लंबा जीबन भी जिया कि नहीं? जीबन बिकसित या बृद्ध होने की प्रक्रिया हो सकता है। बिकसित होना बर्षों में जीबन को जोड़ना है, बृद्ध होना जीबन में बर्षों को जोड़ना है। बस्तुतः, उम्र का आंकड़ा नहीं, अपितु जीबन को जीना मायने रखता है। यह अधिक महत्व रखता है कि कौन कितनी गहराई से या सुगमता से जीता है।

हमारे पूरे जीबन का अमूमन एक तिहाई हिस्सा तो नींद के नाम चला जाता है और एक बड़ा हिस्सा पढ़ाई की घुटाई में लग जाता है। इसके बाद जो समय बचता है उसका अधिकांश हिस्स धन अर्जन की उठापटक में गल जाता है। शेष बचा समय खानपान, मौज-शौक, मित्र और रिश्तेदारों आदि के नाम खर्च हो जाता है।

डा. निर्मल जैन

केरल का 'जल बजट'

सुधीर कुमार

अगर हमें पहले से पता हो कि हमारे पास कितना पानी शेष है और वह कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा तो हम उसका बुद्धिमतापूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं

केरल 'जल बजट' अपनाने बाला देश का पहला और इकलौता राज्य है। इसे अपनाकर केरल ने जल की मांग और आपूर्ति व्यबस्था को सुधारने, भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने, कृषि उत्पादन की सुनिश्चितता, पर्यावरण व समग्र जल सुरक्षा और पानी की बर्बादी रोकने की दिशा में मिसाल कायम किया है। दक्षिण-पश्चिम मानसून से पहली बर्षा केरल के समुद्री तट पर ही होती है, बाबजूद इसके गर्मी के दिनों में राज्य के कुछ इलाके पानी की कमी का सामना करते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए ही केरल ने जल बजट बनाने का फैसला किया है।

जल बजट जल संसाधन की मात्रा निर्धारित करने और उनके प्रबंधन पर केंद्रित एक रणनीति है। यह जल की उपलब्धता और उसके उपयोग का सालाना ब्यौरा देता है। जल बजट किसी बर्ष बिशेष में प्राप्त पानी की बितरित और प्रबंधित करने का समाधान प्रस्तुत करता है। यह जल के उपभोग की सीमा निर्धारित करता है, जिससे भूमिगत जल पर प्रतिकूल प्रभाब नहीं पड़ता है और इसके भंडारण को स्थायी रूप से सूखने से बचाय जा सकता है। यह भूजल की स्थिति की जानकारी भी प्रदान करता है। जल बजट निर्धारण का सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर होता है, जब बर्षा ऋतु समाप्त हो जाता है। इसके तहत उपलब्ध जल संसाधन को बिभिन्न उपयोगों में खर्च करने की योजना बनाई जाती है और उसी के अनुसार जल संसाधन का कुशल उपयोग किया जाता है। अगर हमें पहले से पता हो कि हमारे पास कितना पानी शेष है और वह कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा तो हम उसका बुद्धिमतापूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आसन्न जल संकट को भी टाला जा सकता है।

सूखे और मानसून की अनिश्चितता तथा जल बजट जैसी व्यबस्था न होने के कारण ही देश में कई शहर 'डे-जीरो' की स्थिति का सामना कर रहे हैं। बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहर अपने निबासियों की प्यास के साथ-साथ अन्य जरूरतों के लिए पानी उपलब्ध कराने में असमर्थता पेश कर चुके हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि 2030 तक देश की 40 प्रतिशत आबादी के पास पीने के लिए पानी का अभाब रहेगा। निःसंदेह स्वच्छ पेयजल की प्राप्ति हमारा संबैधानिक अधिकार है। 'सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य' (1991) मामले में सुनबाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि अनुच्छेद 21 के तहत 'जीबन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हबा का अधिकार शामिल है।' हालांकि यह तभी संभब है, जब हरेक स्तर पर जल संरक्षण के सार्थक प्रयास हों। जल संकट के व्यापक होने का प्रमुख कारण भूमिगत जल का अंधाधुंध दोहन है।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

मेलबाक्स

अपना हित समझे मुस्लिम समुदाय

'मुसलमानों को फिर से डराने की साजिश' शीर्षक से लिखे आलेख में मुख्तार अब्बास नकबी ने बक्फ बोर्ड के इतिहास का बर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिश्लेषण का प्रयास किया है। उनका कहना है कि पिछले कुछ मुद्दों की तरह इस बार भी मुसलमानों को डराने का प्रयास किया जा रहा है और उन्हें भड़काया जा रहा है। गैभीर सबाल यह उठता है कि आखिर देश का मुसलमान किसी के भड़काने में आता ही क्यों है? वह अपने हित को समझ पाने में क्यों नाकाम है? कहीं इसके पीछे उसकी मजहबी मान्यताओं के प्रति कट्टरता और शिक्षा व्यबस्था तो नहीं है? देश का बाकी समाज जहां आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर बिभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है, बहीं मुस्लिम समाज के एक बर्ग में मदरसा जैसी मजहबी शिक्षा को ही जरूरी मान लिया गया है। मुस्लिम समाज को यह समझना होगा कि राष्ट्र की उन्नति में ही उनकी भी उन्नति निहित है। इसलिए संकीर्ण सोच बाले लोगों के बहकावे में आने के बजाय उन्हें अपने सोच का दायरा बढ़ाना होगा। तभी उनकी समृद्धि की राह भी खुलेगी?

बेदप्रकाश पाण्डेय, अंबेडकर नगर (उप्र)

सही सलाह

'राहुल की आत्मघाती आक्रामकता' शीर्षक आलेख में डा. एके बर्मा ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को सलाह दी है कि बे लड़कपन छबि से बाहर निकल कर भारतीय जनमानस की संस्कृति को अपनाएं। अमेरिका की अपनी यात्रा में राहुल गांधी के टिप्पणियों ने भारत में राजनीतिक बिबाद को जन्म दिया, जबकि पड़ोसी दुश्मन देशों में राहुल के बयानों को जमकर तारीफ की जा रही है। जानकार बताते हैं कि देश में सिख समुदाय को किसी तरह के धार्मिक उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि बर्ष 1984 में कांग्रेस शासनकाल में एक सोची-समझी साजिश के तहत तीन हजार सिख्खों का नरसंहार किया गया और इस नरसंहार में कांग्रेस के कई नेता शामिल थे। पुरी ने कहा कि मैं पिछले 60 साल से भी अधिक समय से पगड़ी और कड़ा पहन रहा हूं और मुझे आज तक एक कोई नहीं मिला जो कहे कि उसे पगड़ी और कड़ा पहनने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

संवैधानिक व्यवस्था का करें सम्मान

दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने अपने संवैधानिक पद की गरिमा का अपमान करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरबिंद केजरीबाल की कुर्सी को छोड़ कर खड़ाऊं शासन चलाने का नया अध्याय और प्रयोग आरंभ किया है। अभी चार माह बाद दिल्ली में बिधानसभा चुनाब होने हैं, ऐसे में उनका चार माह का शासन अरबिंद केजरीबाल के लगभग दस बर्षों के शासन के मुकाबले कितना सार्थक और प्रभाबशाली होगा, यह तो समय बताएगा, परंतु उन पर अरबिंद केजरीबाल के लिए कुर्सी छोड़ने का दबाब अपनी बास्तबिकता जनमानस के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। अरबिंद केजरीबाल के जेल से बेल पर बाहर आने के बाद भगबान श्री राम से उनकी तुलना न केबल अपमानजनक है, बल्कि हास्यास्पद है। आतिशी की तुलना भरत से करना भी तुलसीदास जी की रामचरित मानस और ऋषि बाल्मीकि की रामायण का उपहास है। आम आदमी पार्टी के राम और भरत राजबोग और राजसत्ता का पूरा आनंद ले रहे हैं। इससे तो दिल्ली की बिधानसभा को भंग करके नए बिधानसभा चुनाब की अनुशंसा करना उचित था। यह प्रशंसनीय होता कि आम आदमी पार्टी अपने दस बर्षों का रिपोर्टकार्ड जनमानस के सामने लाए और फिर दिल्ली पर शासन करने के लिए जनता का आदेश और आशीर्बाद प्राप्त करे। घोटालों का हिसाब किताब अदालतों में होता है भीड़ से नहीं। जनता गुनहगों और गुनाहगारों का निर्णय नहीं कर पाती, नहीं तो कितने ही अपराधी और भ्रष्टाचार पृष्ठभूमि के जन प्रतिनिधि बिधायिकाओं में न बैठे होते। आतिशी की बिबशता समझी जा सकती है। दिल्ली की बिधानसभा चुनाब के परिणाम किसी के पक्ष में हो, आम आदमी पार्टी ने अबिकेपूर्ण निर्णय लिया है।

बिनोद जौहरी, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी बिषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रबंध संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी जमीन से निकाला है दिल्ली जल बोर्ड। जहां 1983 में यहां 33 फीट गहराई पर पानी निकल आता था, अब यह गहराई 132 फीट हो गई है।

अभिषेक कुमार सिंह
संस्था-टेली परफार्मेंस से संबद्ध

आजकल

उपकरणों के हथियार में बदल जाने का संकट

हाल में लेबनान और सीरिया में हिजबुल्ला के हजारों सदस्यों द्वारा इस्तेमाल में लाए जा रहे संचार उपकरण पेजर, वाकीटाकी और रेडियो सेट विस्फोट के साथ अचानक फटे, तो समूचा विश्व इनके जानलेवा होने वाले पक्ष को देखकर हैरान रह गया। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि इन हमलों के पीछे इजरायल का हाथ है। हालांकि इजरायल ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन इसे देखते हुए आज पूरी दुनिया आशंकित है कि क्या कभी उनके मोबाइल फोन, कंप्यूटर और लैपटाप आदि इलेक्ट्रानिक उपकरणों में भी इसी तरह विस्फोट कराया जा सकता है?

आधुनिक किस्म की जंग में तकनीक एक बड़े हथियार की भूमिका निभाने की स्थिति में आ चुकी है। प्रतीकात्मक

इस आधुनिक युग में सूचना-संचार से लेकर ऐसे दर्जनों काम हैं, जिनमें विज्ञान की देन कही जाने वाली तकनीकों, मशीनों और उपकरणों ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है। हालांकि तकनीक के दूसरे पहलू की अपनी कई समस्याएं भी हैं। जैसे इंटरनेट और मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल के कारण कई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें पैदा होने का हवाला अक्सर दिया जाता है। अक्सर यह भी कहा जाता है कि तकनीक तो असल में हमारी जान की दुश्मन बन गई है, लेकिन क्या यह वास्तव में जानलेवा हो सकते है? हाल में लेबनान और सीरिया में हिजबुल्ला के हजारों सदस्यों द्वारा इस्तेमाल में लाए जा रहे संचार उपकरण पेजर, वाकीटाकी और हैंडहेल्ट रेडियो सेट विस्फोट के साथ अचानक फटे, तो दुनिया इनके जानलेवा होने वाले पक्ष को देखकर हैरान रह गई। दावा किया गया कि पेजर और वाकीटाकी के अलावा घरों में लगे सोलर पैनलों में भी ऐसे ही विस्फोट हुए। दावा है कि इन हमलों के पीछे इजरायल का हाथ है। इजरायल ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन आज लेबनान समेत पूरी दुनिया आशंकित है कि क्या कभी उनके मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटाप जैसे उपकरणों का युद्धक के रूप में इस्तेमाल हो सकता है? क्या दुनिया उस दौर में पहुंच गई है जहां कोई देश अपने शत्रु के सैनिकों-नागरिकों को कोई वास्तविक जंग छेड़े बिना घर बैठे महज एक बटन दबाकर नुकसान पहुंचा सकता है?

जंग में क्या सब जायज है : लेबनान ने जब यह सवाल अंतरराष्ट्रीय संगठनों से पूछा, तो प्रतिक्रिया में पेजर और वाकीटाकी को हमलों का जरिया बनाने को अनैतिक और युद्ध-अपराध कहा गया। असल में बीते करीब एक साल से इजरायल गाजापट्टी में आतंकी संगठन हमास के सहयोगी हिजबुल्ला के साथ युद्ध की स्थिति में है। इस जंग में जिसका जहां दांव लग रहा है, वह उस तरीके से अपने शत्रु पर हमला कर रहा है। इस जंग में अपनी ओर से ये ये देश कई ऐसी सावधानी भी बरत रहे हैं, ताकि वे अपने दुश्मन की नजर में न आएं। जैसे कि हिजबुल्ला के शीर्ष नेतृत्व ने अपने लड़ाकों को संचार के लिए मोबाइल या इंटरनेट के बजाय पेजर नामक उस उपकरण के इस्तेमाल का आदेश दे रखा है, जिसमें कोई सिम कार्ड जैसी चीज नहीं होती। पेजर मोबाइल फोन से पहले के जमाने की तकनीक है। इसके जरिये अमूमन कोई संदेश अंकों और अक्षरों के आदान-प्रदान तक सीमित रहता है। पेजर की खासियत यह है कि इसके उपयोगकर्ता की मौजूदा स्थिति यानी लोकेशन का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसी तरह वाकीटाकी से भी संदेश प्राप्त किए और भेजे जा सकते हैं, लेकिन एक समय में एक ही व्यक्ति बात कर सकता है। यह बैटरी से चलता है और इसे सेलुलर नेटवर्क की जरूरत नहीं होती। हिजबुल्ला को यह खतरा रहा है कि इजरायल की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी-मोसाद उसके लड़ाकों की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। लिहाजा उसने अपने लड़ाकों को कम तकनीक क्षमता वाले पेजर और वाकीटाकी प्रयोग करने के लिए दिए थे। पेजर और वाकीटाकी ऐसे बेसिक उपकरण हैं जिन्हें इस्तेमाल करने वाले की लोकेशन का पता लगाकर उस पर कोई हमला नहीं किया जा सकता, लेकिन हाल के हमलों ने साबित कर दिया है कि सिर्फ पेजर और वाकीटाकी ही नहीं, हर किस्म के उपकरण हथियार में तब्दील किए जा सकते हैं, बशर्ते उसके निर्माण की प्रक्रिया और सप्लाई चेन में कोई सेंध लगाई जा सके। अंदाजा है कि यह खुफिया सूचना कि हिजबुल्ला अपने लड़ाकों के लिए हजारों पेजर एक साथ खरीदने वाला है, किसी तरह इजरायल के हाथ लग गई होगी। माना जा रहा है कि निर्माण अथवा सप्लाई चेन में ही किसी स्तर पर मोसाद ने घुसपैठ कर ली होगी और पेजर-वाकीटाकी आदि में विस्फोटक लगा दिए होंगे। ये विस्फोटक इस प्रकार लगाए गए थे कि इन्हें कोई संदेश भेजकर सक्रिय किया जा सके।

कैसे हथियार में बदली तकनीक : वैसे तो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर चलने वाले पेजर और वाकीटाकी आज के आधुनिक दौर में गुजरे जमाने के उपकरण लग सकते हैं, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में ये आज भी इस्तेमाल में आ रहे हैं। जैसे पुलिस, पैरामिलिट्री, हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स और कोयला खदानों समेत कई ऐसे सेंसेटनशील उद्योगों में-जहां मोबाइल नेटवर्क आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। चूंकि इनकी बैटरी लाइफ अच्छी होती है, इसलिए आपात स्थितियों में मोबाइल फोन के मुकाबले ये ज्यादा विश्वसनीय संचार उपकरण साबित होते हैं। प्रायः प्लास्टिक से बने पेजर और वाकीटाकी किसी सिग्नल को ग्रहण कर उसे दिखोड नहीं कर सकते। इनकी संरचना में एंटीना, स्पीकर, माइक्रोफोन, बैटरी, ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं। स्पीकर और माइक्रोफोन को छोड़ दें, तो शेष तीनों विस्फोटक के कंटेनर का काम कर सकते हैं। यही नहीं, इन उपकरणों के अंदर बैटरी के आसपास इतनी खाली जगह होती है, जहां छोटा-मोटा विस्फोटक लगाया जा सकता है। यहां एक बड़े सवाल और आशंका ने जन्म लिया है। वह यह कि इस तरह तो मोबाइल फोन, स्मार्ट टीवी, माइक्रोवेव, रेफ्रीजरेटर समेत हर उपकरण को कैद किया जा सकता है और उसे युद्धक हथियार में बदला जा सकता है।

क्या वम में बदल सकता है मोबाइल : इसमें संदेह नहीं है कि यदि किसी भी उपकरण के निर्माण और आपूर्ति प्रक्रिया में कोई दोश जंग के इरादे से सेंध लगाने में सफल हो जाए, तो उन उपकरणों को वांछित समय पर निर्देश देकर विस्फोट करने अथवा कोई अन्य गड़बड़ी करने के लिए सेट किया जा सकता है। इनमें से मोबाइल या कहें कि स्मार्टफोन तो अपनी अत्याधुनिक कार्यप्रणालियों और वायरलेस कनेक्टिविटी के कारण पेजर और वाकीटाकी की तुलना में कहीं ज्यादा असुरक्षित हैं। इंटरनेट, जीपीएस ट्रैकिंग और रिमोट कंट्रोल आदि जिन सहूलियतों ने मोबाइल फोन को अत्यधिक सुविधाजनक उपकरण में तब्दील किया है, वे सभी इसे जंग का सबसे खतरनाक हथियार बनाने में कारगर हो सकते हैं। इससे सबसे जरूरी सूचना यानी लोकेशन तो एक आम ईसान तक हासिल कर सकता है। सेना या बड़ी एजेंसियां इन्हें ठैक करके इन पर कोल और मैसेज भेजकर धमाके तक कर सकती हैं। मोबाइल फोन तो वैसे भी अपनी लिथियम आयन बैटरियों से जुड़ी समस्याओं के कारण पहले से ही कुख्यात रहे हैं। ज्यादा गर्म हो जाने पर इनमें स्वतः विस्फोट हो जाने के दर्जनों हादसे प्रकाश में आए हैं। शार्ट सर्किट होने से लीथियम आयन बैटरी के फटने की समस्या बहुत आम रही है। वैसे तो स्मार्टफोन में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को पेजर और वाकीटाकी के मुकाबले ज्यादा पुख्ता माना जाता है, लेकिन बैटरी कंट्रोलर सिस्टम को ही अगर कोई हैक कर ले, तो जब चाहे उसमें विस्फोट करा सकता है। यह काम कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। यही नहीं, मोबाइल फोन की तरह इंटरनेट आफ थिंग्स (आइओटी) तकनीक से जुड़े अन्य सारे उपकरण हैक किए जा सकते हैं और उनसे अव्यवस्था फैलाई जा सकती है।

कुल मिलाकर स्थिति यह है कि आधुनिक किस्म की जंग में तकनीक एक बड़े हथियार की भूमिका निभाने की स्थिति में आ चुकी है। पेजर, वाकीटाकी, मोबाइल फोन, ड्रोन, लेजर बम, सैटेलाइट हैकिंग और अंतरिक्ष में लड़े जा सकने वाले युद्ध-इन सभी में तकनीक का योगदान है। जो देश जासूसी और जंग के लिए इनके इस्तेमाल के तौर-तरीकों से लैस है, आज की तारीख में उसे दूसरे देशों के मुकाबले युद्ध में बढ़त हासिल है। ऐसा इसलिए, क्योंकि उसे शत्रु देश को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने सैनिकों को युद्ध के मैदान में नहीं उतारना है, बल्कि यह काम एक अत्याधुनिक कमांड स्थापित करने और घर बैठे मशीनों को संदेश देने भर से संपन्न हो जाता है।

तकनीकी आत्मनिर्भरता से बचाव संभव

आज की तारीख में मोबाइल फोन के जरिये अपना डाटा दुनिया भर की कंपनियों के हवाले करके हम खुद कई गलतियां कर चुके हैं, फिर भी हिदायत दी जाती है कि तात्र मुमकिन हो-इंटरनेट और बेहद एडवांस तकनीकों से लैस उपकरणों के इस्तेमाल से बचें। इस्तेमाल में आइओटी से लैस चीजें (जैसे कि आधुनिक कारें) सुविधाजनक लग सकती हैं, लेकिन हैकिंग की सूरत में ये खतरनाक बन सकती हैं। जनता के स्तर से अलग हटकर सरकार के स्तर पर एक समस्या और है। वह है तकनीक में आत्मनिर्भरता के अभाव की। हमारे देश ने सर्विस सेक्टर यानी आइटी इंजीनियरिंग में साफ्ट स्किल से लैस कर्मचारियों की फौज तैयार करने में महारत हासिल की, लेकिन निर्माण यानी मैन्यूफैक्चरिंग में भारत पिछड़ गया। इसके फलस्वरूप देश आज अपना ज्यादातर इलेक्ट्रानिक समान चीन, जापान, दक्षिण कोरिया आदि देशों से मंगाता है। यह स्थिति सही क्यों नहीं है, इसे ऐसे समझना चाहिए कि अमेरिका ने चीन की कंपनी-हुआवे के उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा रखा है। मोबाइल से लेकर तमाम घरेलू उपकरण और विशाल इंजीनियरिंग के सामान बनाने वाली इस कंपनी पर अमेरिका का आरोप है कि वह अपने उपकरणों के जरिये डाटा जमा करती है और जासूसी करने में चीन के नेतृत्व की मदद करती है। उपकरणों के जरिये डाटा संग्रह करने या उसे चुराने की प्रक्रिया कैसे जंग में किसी देश की मदद कर सकती है-लेबनान में हुए हालिया हादसे के मद्देनजर यह बात आसानी से समझी जा सकती है। बेशक तमिलनाडु में आइफोन की फैक्ट्री लगाकर भारत ने इस दिशा में सही पहल की है, लेकिन कोशिश करनी होगी कि सभी तरह के उपकरणों के निर्माण में देश आत्मनिर्भरता हासिल करे। ऐसा करना आर्थिक स्वावलंबन और रोजगार पैदा करने के नजरिये से ही नहीं, बल्कि युद्ध की सूरत में अपने हितों को संरक्षित करने के लिहाज से भी जरूरी है।

-अभिषेक कुमार सिंह

खरी-खरी

गगनचुंबी आशाएं और बौनी सच्चाइयां

नृपेंद्र अभिनव नृप

आजकल स्मार्टफोन की महिमा अपरंपार है। लोग नाश्ते की प्लेट से लेकर रात के सपनों तक, हर चीज को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने में मग्न हैं। ऐसा लगता है मानो जीवन का असली मकसद ही अब सेल्फी लेना हो गया है। सुबह उठते ही लोग सबसे पहले अपने फोन को ही देखते हैं, उसके बाद ही चेहरे को देखते हैं। चेहरा चाहे जैसे भी हो, फिल्टर से सब ठीक हो जाएगा। आजकल फिल्टर का जमाना है-दुनिया को जो दिखाना हो, वह दिखाओ, सच्चाई किसी को नहीं दिखती। पर असल में तो लोग खुद को खो रहे हैं, और खो रहे हैं समय, रिश्ते और सबसे बड़ी बात, वास्तविक जीवन की चमक।

धन का महत्व अब जीवन का मूल मंत्र बन चुका है। अगर आपके पास नई गाड़ी, बड़ा घर और एक महंगा स्मार्टफोन है, तो आप सफल हैं, भले ही आपकी रातों की नींद उड़ चुकी हो। यह बिंदुबना नहीं तो और क्या है कि लोग दिन-रात धन कमाने के पीछे भाग रहे हैं, और उसी धन की होड़ में जीवन का आनंद भूलते जा रहे हैं। जब आखिरकार बैंक बैलेंस बढ़ा हो जाता है, तब पता चलता है कि जीवन के असली रिश्ते छोटे हो गए हैं।

समाज भी कुछ कम नहीं है। हम समाज में बदलाव की बातें करते हैं, लेकिन खुद को बदलने की बात पर हम पल्ला झाड़ लेते हैं। स्वच्छता अभियान से लेकर महिला सशक्तीकरण तक, सब कुछ बस इंटरनेट मीडिया के हैशटैग बनकर रह जाता है। असल में बदलाव लाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, और वह हमसे नहीं होता। हम आसमान में उड़ने का सपना देखते हैं, लेकिन जमीन पर पैर रखना भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए, लेकिन उसके लिए कोई त्याग नहीं करना चाहते। हम दिखावे के पीछे इतने पागल हो गए हैं कि असली जीवन को देखना ही बंद कर दिया है। हम चाहे जितना भी दौड़ लें, अंत में सच्चाई यही है कि हमें अपने अंदर झांकना होगा। जब तक हम वास्तविक जीवन के मूल्यों को नहीं समझेंगे, तब तक यह दौड़ जारी रहेगी-बिना किसी मंजिल के, बिना किसी सुकून के।

X पोस्ट

वायरल होने की अंधी दौड़ में इंसान कितना नीचे गिरता जा रहा है। रील बनाने के लिए दूसरों को परेशान करने वाली की कायदे से कुटाई होनी चाहिए।
राजा बाबू@GaurangBhardwa1

प्रणानंद और वैशाली की मां को देखते ही आसपास की तमाम माताओं के चेहरे उभर आते हैं। ऐसा लगता है यह अपनी ही मां है, जिसने घूल्हे पर सपने सेंके हैं। बर्तन के साथ तमाम दुखों को धोया है और पति के पोलियोग्रस्त होने के बावजूद बेटे-बेटी को शतरंज का विश्व चैंपियन बना दिया है।
अतुल कुमार राय@AuthorAtul

राहुल गांधी ने शतरंज के विश्व चैंपियनों को बधाई तो दी, पर क्या खिलाड़ियों से उनकी जाति पूछी कि वे किस जाति के हैं? उन्होंने उनसे सामाजिक न्याय के बारे में पूछा?
श्रीमय तालुकदार@sreemoytalukdar

श्रीलंका में एक मार्क्सवादी राष्ट्रपति की तजपोशी हो गई। नेपाल की कमान पहले से ही कम्युनिस्टों के पास है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में अमेरिका समर्थित सेनाओं का दबदबा है। मालदीव में इस्लामिक झुकाव वाले राष्ट्रपति है। म्यांमार में विद्रोहियों को अमेरिकी शह मिल रही है। कुल मिलाकर, भारत के लिए आसपड़ोस में सब कुछ ठीक नहीं।
ब्रह्मा चेलानी @Chellaney

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या श्रीलंका में दिसानायके का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए चिंता का विषय है?

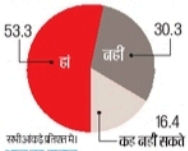

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के बाद मुख्यमंत्री सिद्दरमैया को त्यागपत्र देना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

आलराउंडर है सपा तभी हो रहा 'नाम',
नोट छापने का करे उसके नेता काम।
उसके नेता काम सभी डकैत-दुष्कर्मी,
फिर भी सीना तानकर ले, देखो वेशर्मी।
टोपी लाल लगाय करे ये खड़ा बवण्डर,
कहलाते हैं आजतभी तो आलराउंडर!
- ओमप्रकाश तिवारी

पंजाब डायरी

मंत्रिमंडल में बार-बार होते फेरबदल

इन्द्रप्रीत सिंह
ब्यूरो प्रमुख, पंजाब

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने ढाई साल के कार्यकाल के दौरान चौथी बार मंत्रिमंडल में फेरबदल कर दिया है और चार मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए पांच नए चेहरों को कैबिनेट में जगह दी है। इस पर विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा, वह रेल के डिब्बों को बार-बार बदलकर पंजाब की आर्थिकी और कानून की व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश न करें। एक बार इंजन बदलकर देख लें। उनका इशारा मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर था कि उन्हें बदलकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए। बाजवा ने कुछ दिन पहले भी इस तरह का बयान दिया था जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जगह पर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। बाजवा ने कहा था कि किसी महिला को पंजाब की कमान सौंप देनी चाहिए।

मुख्यमंत्री भगवंत मान और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा अक्सर एक-दूसरे को नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। चाहे वह सार्वजनिक मंच हो या विधानसभा सत्र, लेकिन यहां मुद्दा पांच नए मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल करने का है। आखिर इसकी क्या वजह रही कि मात्र ढाई वर्षों में ही मुख्यमंत्री को अपनी कैबिनेट में चार बार फेरबदल करने पड़े। क्या मुख्यमंत्री को अपने इन मंत्रियों की काबिलियत पर संदेह था या फिर बात कुछ और है। सरकार के बार-बार इस तरह के कदम उठाने से जहां अन्य मंत्रियों का विश्वास डगमगा रहा है, वहीं आम लोगों की उम्मीदें भी धूमिल हो रही हैं। ढाई साल पहले जिस आम आदमी पार्टी को 117 में से 92 सीटें देकर रिकार्डतोड़ जीत आम लोगों ने दी थी, अब इस तरह का फेरबदल देख-देख कर उनकी भी उम्मीदें टूटती जा रही हैं। जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के विधायकों के प्रति लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी थी, उससे लग ही रहा था कि कैबिनेट में एक बार फिर से फेरबदल होगा। दिक्कत यह हो रही थी कि जून महीने के बाद से ही पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे, जिस कारण उनसे चर्चा नहीं हो पा रही थी। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जालंधर विधानसभा के उपचुनाव में मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से जालंधर पश्चिम के लोगों को आश्वासन दिया कि वह उनकी पार्टी के नेता को विधायक बना दें, मंत्री तो वह उन्हें बना ही देंगे। जालंधर पश्चिम के लोगों ने मुख्यमंत्री की बात को रखा और भारी बहुमत से मोहिंदर भगत को चुनकर विधानसभा में इस आस से भेजा कि वह मंत्री बनकर उनके इलाके का विकास करेंगे। मोहिंदर भगत को मंत्री बनाने की तैयारी भी लगभग हो गई थी, लेकिन ऐन मौके पर उनको इंतजार करने के लिए कहा गया। यह भी कहा जा रहा है कि पार्टी में इस बात को लेकर नाराजगी है कि कुछ समय पहले ही भाजपा को छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए मोहिंदर भगत को कैसे मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है, जबकि उनसे पहले के कई विधायक मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। भगवंत मान की कैबिनेट में दो मंत्रियों की जगह पहले से ही खाली थी, तीसरी सीट कैबिनेट मंत्री मीत हेयर के सांसद बनने के चलते खाली हो गई। अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री की बात को रखने के लिए मोहिंदर भगत को कैबिनेट में तो जरूर ले लिया गया है, लेकिन उनको ऐसे विभाग दिए गए हैं, जिन्हें आमतौर पर कम महत्व का माना जाता है। उनको रक्षा सेवाएं और बागवानी विभाग दिए गए हैं।

सीएम भगवंत मान (दाएं से तीसरे) ने अपने ढाई साल के कार्यकाल में चौथी बार बदला मंत्रिमंडल। फाइल

कुछ नए चेहरों को चार से पांच बड़े विभाग देकर नवाजा गया है। पार्टी में इस बात को लेकर भी चर्चा चल रही है कि क्या इस बार फेरबदल में मुख्यमंत्री की ज्यादा चली है या फिर पार्टी हाईकमान ने अपना दबदबा कायम रखा है। पिछली सरकारों के दौरान भी 18 मंत्रियों में से चार या पांच अनुसूचित जाति के मंत्री बनाए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार 16 में ही पांच मंत्री अनुसूचित जाति से हैं। राजनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा है कि ऐसा होशियारपुर जिले में डाक्टर राजकुमार चब्बेवाल के सांसद बनने के कारण खाली हुई सीट पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए किया गया है। पार्टी का ध्यान इस जिले की आरक्षित सीट चब्बेवाल पर होने वाले उपचुनाव पर है। पार्टी अनुसूचित जाति के वोटों को ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर खींचना चाहती है।

खैर, कैबिनेट में बदलाव तो होते ही रहते हैं, लेकिन इतनी जल्दी-जल्दी उलटफेर पंजाब के राजनीतिक इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो। वह भी तब जब किसी पार्टी को तीन चौथाई बहुमत मिला हुआ है। आमतौर पर अल्पमत वाली सरकारें या गठजोड़ सरकारें के दौरान तो इस तरह के फेरबदल होने की संभावना रहती है, लेकिन पूर्ण बहुमत वाली सरकार में इस तरह देखने को कम ही मिलता है।

मंथन

चिंतित करता विषैला होता भूजल

पंकज चतुर्वेदी
पर्यावरण मामलों के जानकार

देश की राजधानी दिल्ली की आबादी बढ़ती जा रही है और उसी गति से यहां पानी की मांग भी बढ़ रही है। दिल्ली में पूरे साल पानी वितरण का तंत्र जिन टैंकरों पर टिका है, उनकी जलापूर्ति भूजल के ऐसे स्रोतों से हो रही है, जो जहर बन चुके हैं और उस जल को शुद्ध-निरापद बनाने के न तो कोई उपाय हैं और न ही प्रयास हो रहे हैं। कितना दुखद है कि मजबूरी में लोग उस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उन्हें बीमार बना रहा है। केंद्रीय भू जल बोर्ड की ताजा रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली का भूजल आर्सेनिक, फ्लोराइड और अन्य खतरनाक रसायनों से परिपूर्ण है और ये हड्डियों के रोग, दांतों को कमजोरी से लेकर कैंसर जैसी बीमारी दे रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा हड्डियों और दांतों को कमजोर कर देती है। आर्सेनिक की अधिक मात्रा से त्वचा, आंखों, कैंसर, फेफड़ों और किडनी की बीमारी होती है। वहीं लवणता बढ़ने से ब्लड प्रेशर और पथरी का रोग होता है। एक तो दिल्ली में भूजल और गहराई में जा रहा है, इसकी गुणवत्ता भी खराब हो रही है।

दिल्ली में भूजल की उपलब्धता सालाना 291.54 मिलियन घन मीटर है। पाताल खोद कर निकाले गए पानी से यहां 47 हजार पांच सौ हेक्टेयर खेत सींचे जाते हैं। 142 मिलियन घन मीटर पानी कारखानों एवं पीने के काम आता है। दिल्ली जल बोर्ड 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी जमीन से निकालता है। जहां 1983 में यहां 33 फीट गहराई पर पानी निकल आता था, आज यह गहराई 132 फीट हो गई है। इसमें भी नाइट्रेट, फ्लोराइड एवं आर्सेनिक जैसे रसायन हानिकारक स्तर पर पहुंच गए हैं। सनद रहे कि पाताल के पानी को गंदा करना तो आसान है, पर उसका परिशोधन करना करीब असंभव। जाहिर है भूजल के हालात सुधारने के लिए बारिश के पानी से रीचार्ज एवं उसके कम दोहन की संभावनाएं खोजनी होंगी। आखिर दिल्ली के गर्भ के जल को जहरीला कौन बना रहा है? इस महानगर में कूड़े का सही तरह से प्रबंधन एवं निस्तारण न होना इसका सबसे प्रमुख कारण है। यहां कूड़े के तीन विशाल पहाड़ हैं और उनका हर दिन कद बढ़ता जा रहा है। सारी दुनिया से वैध-अवैध तरीके से इलेक्ट्रानिक कचरे यहां आ रहे हैं। इनका गैर वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किए जाने से उपजे खतरनाक रसायन बहुत चुपके से धरती में गहरे तक समा रहे हैं और जीवनदायी जल को जहर बना रहे हैं। ई-कचरे के लगभग 97 प्रतिशत हिस्से को अवैज्ञानिक तरीके से जला कर या तोड़ कर उनमें से कीमती धातुएं निकाली जाती हैं एवं शेष को यूं ही कहीं फेंक दिया जाता है। इससे रिसने वाले रसायनों का एक भयानक तथ्य यह है कि इस कचरे की वजह से पूरी खाद्य श्रृंखला बिगड़ रही है। ई-कचरे के आधे-अधूरे तरीके से निस्तारण से मिट्टी में खतरनाक रासायनिक तत्व मिल रहे हैं, जो पेड़-पौधों के अस्तित्व के लिए खतरा बन रहे हैं। इसके चलते पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पा रही है। इसका असर वायुमंडल में आक्सीजन की मात्रा पर हो रहा है।

बैटरियों, कंप्यूटरों और मोबाइल फोन का कचरा सबसे खतरनाक है। इनमें पारा, कोबाल्ट, कैडमियम और न जाने कितने किस्म के जहरीले रसायन होते हैं। कैडमियम से फेफड़े एवं किडनी दोनों को गंभीर नुकसान पहुंचता है। एक कंप्यूटर का वजन लगभग 3.15 किलो ग्राम होता है। इसमें 1.90 किलोग्राम सीसा, 0.693 ग्राम पारा और 0.049 ग्राम आर्सेनिक होते हैं, जो जलाए जाने पर सीधे वातावरण में घुलते हैं। इनका अवशेष पर्यावरण के क्विंशा का कारण बनता है। शेष हिस्सा प्लास्टिक होता है। इसमें से अधिकांश सामग्री गलती-सड़ती नहीं है और जमीन में जब्ज हो कर मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित करने और भूगर्भ जल को जहरीला बनाने का काम करती है। ठीक इसी तरह का जहर बैटरियों एवं बेकार मोबाइल फोनों से भी उपज रहा है। इनसे निकलने वाले जहरीले तत्व और गैसें मिट्टी एवं पानी में मिलकर इन्हें बंजर और जहरीला बना देती हैं। फसलों और पानी के जरिये ये तत्व हमारे शरीर में पहुंचकर बीमारियों को जन्म देते हैं। बैटरियों से निकला तेजाब, नालों और वहनों से निकलने वाले प्रदूषण पाने के साथ मिल कर धरती में जहर भर रहे हैं। यहां के खेत और यमुना के कछार में सब्जी उगाने में बेशुमार रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल ने गहरे तक धरती और उसकी कोख के पानी को विष में बदल दिया है।

दिल्ली में भूजल और गहराई में जाने के साथ इसकी गुणवत्ता भी खराब हो रही है। फाइल

दिल्ली में जल आपूर्ति बगैर भूजल के संभव नहीं है। इस दूषित पानी के सेवन से यहां की बड़ी आबादी बीमार हो रही है। इससे लोगों पर आर्थिक और सामाजिक बोझ तो बढ़ ही रहा है, उनके कार्य करने की क्षमता और आर्थिक तंत्र भी गड़बड़ा रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए आज दिल्ली और इसके आसपास करीब 100 किलोमीटर के दायरे में कचरा उठाने और इनके निस्तारण (खासकर इलेक्ट्रानिक कचरे) के लिए एक कड़ी और स्पष्ट नीति बनाने की तत्काल जरूरत है। साथ ही इस समूचे इलाके में जैविक खेती भी अनिवार्य की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • बुधवार • 25 सितम्बर • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

भ्रातृभाव का अस्तित्व केवल आत्मा में और आत्मा के द्वारा ही होता है, यह और किसी के सहारे टिक ही नहीं सकता।
-श्री अरविंद

मासूमों की खातिर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना, स्टोर करना और देखना पोस्को और आईटी के तहत अपराध है। अदालत ने 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' की जगह 'बच्चों के साथ यौन शोषण और अश्लील सामग्री' करने पर विचार करना चाहिए। पॉस्को एक्ट में संशोधन के लिए संसद को कानून लाने को भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को पलटते हुए यह कहा जिसमें कहा गया था कि केवल बाल पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और देखना पॉस्को अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के अपराध नहीं है, जब तक कि नीयत इसे प्रसारित करना न हो। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले को अत्याचारपूर्ण बताते हुए उसे

चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई थी जिसके खिलाफ अपने मोबाइल पर बाल पोर्नोग्राफी सामग्री डाउनलोड करने का आरोप था। इससे पहले केरल हाई कोर्ट ने भी सितम्बर, 2023 में कहा था कि अगर कोई शख्स अश्लील फोटो या वीडियो देख रहा है, तो यह अपराध नहीं है, जब तक वह इसे दूसरे को न दिखाए। जबकि अप्रैल में इसी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बच्चे का पोर्न देखना शायद अपराध न हो लेकिन पोर्नोग्राफी में बच्चे का इस्तेमाल होना अपराध है। पीठ ने अपने फैसले में इन धाराओं के तहत पुरुषों के दोषी कृत्य निर्धारित किए जाने की बात भी की। पॉस्को एक्ट की धारा 15(1) के अनुसार बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट को न हटाने, नष्ट न करने या उसकी जानकारी न देने पर भी सजा का प्रावधान है। अदालत ने सरकार को सुझाव दिया कि वह विशेषज्ञों की कमेटी बना सकती है जो सेक्स एजूकेशन का सिस्टम तैयार करे। साथ ही, अदालत ने स्कूलों को भी सलाह दी कि वे कम उम्र में ही बच्चों को पॉस्को कानून के विषय में बताएं। सारी दुनिया के विशेषज्ञ चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने और प्रसारित करने वालों से जूझ रहे हैं। इसे लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की जाती रही है। जब तक मासूमों को गोपन अंगों, अश्लील हरकतों या यौन शोषण के प्रति जागरूक नहीं किया जाता, वे अनभिज्ञ बने रहेंगे। अपराधी प्रवृत्ति के लोग उनकी मासूमियत से यूं ही खिलवाड़ करते रहेंगे। दोषियों को सजा देने की प्रवृत्ति की बजाय बच्चों की सुरक्षा पर खास ख्याल रखना सीखना होगा। जरूरत है कानून और नैतिक प्रभाव पर विशेष तवज्जो दिए जाने की।

श्रीलंका में नई बयार

पड़ोसी देश श्रीलंका में 55 वर्षीय अनुरा कुमारा दिसानायके ने नौवें राष्ट्रपति के रूप में सत्ता संभाल ली है। देश के राजनीतिक इतिहास में दिसानायके के नेतृत्व में पहली बार मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टी की सरकार बनी है। उनकी जीत का मतलब श्रीलंका की राजनीति में एक नई शुरुआत हो रही है। लोगों को याद होगा कि दो साल पहले श्रीलंका को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। केंद्रीय बैंक को वित्तीय चूक की घोषणा करनी पड़ी थी। मुद्रास्फीति, महंगाई और आर्थिक को प्रबंधन ने राष्ट्रपति राजपक्षे और प्रधानमंत्री के विरुद्ध एक बड़ा लोकप्रिय आंदोलन (अरागालय) खड़ा हो गया था। उस समय सद्य निर्वाचित राष्ट्रपति दिसानायके ने देश की राजनीति में सकारात्मक बदलाव लाने में महती भूमिका का निर्वाह किया था।

इस चुनाव में उनके भ्रष्टाचार विरोधी और लोक कल्याणकारी मुद्दों पर भारी समर्थन मिला। राष्ट्रपति दिसानायके के मार्क्सवादी हैं इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में उनकी छवि चीन समर्थक है। जाहिर है कि यह कयास लगाया जा रहा है कि चीन समर्थक मार्क्सवादी राष्ट्रपति के शासनकाल में भारत के सुरक्षा हितों को नुकसान पहुंच सकता है। नेपाल के वामपंथी प्रचंड और केपी शर्मा के समय में दिल्ली और काठमांडू के रिश्तों का उल्लेख किया जा रहा है। हालांकि श्रीलंका की मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखकर ऐसा नहीं लगता कि राष्ट्रपति दिसानायक भारत को नजरअंदाज करेंगे। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती देश को आर्थिक संकट से बाहर निकलना है। श्रीलंका पर करीब 2.9 बिलियन डॉलर का ऋण है। 2023 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रदान किए गए बेल आउट से कुछ हद तक आर्थिक स्थिति का लाने में मदद मिली है। वास्तव में श्रीलंका की पटरी पर से उतरी आर्थिक हालात के लिए चीन पूरी तरह जिम्मेदार है। दिसानायके को भारत और चीन के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा जहां तक भारत का सवाल है तो वह 'पड़ोसी प्रथम' की नीति पर चलने वाला देश है। श्रीलंका के संकट के दिनों में भारत हमेशा मददगार रहा है। इस वर्ष फरवरी में दिसानायके भारतीय नेताओं और राजनीतिकों से मुलाकात करने आए थे। उनकी जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर अपनी प्रतिबद्धता से सहमत हूं। उम्मीद की जानी चाहिए कि दोनों देशों के रिश्ते में और अधिक मजबूत होंगे।

छात्र राजनीति/मनीष कुमार चौधरी

नीति से अनीति तक

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव 70वें साल में प्रवेश कर रहा है। यहां वोट सिर्फ डूसू की नहीं है, देश के किसी भी छात्र संघ चुनाव को उठा कर देख लीजिए, चुनाव आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते महसूस होते हैं। साठ और सत्तर के दशकों में छात्र आंदोलनों ने राष्ट्रीय राजनीति को नई दिशा दी थी। छात्र संघ चुनाव और छात्र राजनीति की प्रासंगिकता की बात करें तो इस सकारात्मक पक्ष को भी ध्यान में रखना होगा कि स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे ऊर्जस्वी पांत में तत्कालीन छात्र नेताओं की बड़ी खेप मौजूद थी।

गौरतलब है कि स्वतंत्रता आन्दोलन में छात्रों ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में छात्रों, युवकों ने वादगार भूमिका निभाई। वाद के यानी साठ और सत्तर के दशकों में तो कई छात्र नेताओं ने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी प्रतिभा का डंका बजाया। कई सांसद और विधायक हैं, जो या तो छात्र राजनीति से राजनीति की मुख्य धारा में आए या किसी न किसी छात्र संघ के पदाधिकारी रहे। विभिन्न विश्वविद्यालयों से चुने गए कई छात्र नेताओं का राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा कद है। नवें दशक तक आते-आते छात्र राजनीति में भटकन शुरू हो गई जब जाति विभेद के चलते छात्र संघ बंट गए और छात्र आंदोलनों में जातिवाद हावी हो गया। 1990 में जब वीपी सिंह सरकार ने सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों के लिए 27 फीसद आरक्षण की व्यवस्था की तो मंडल विरोधी छात्र आंदोलन ने जातिवादी छात्र राजनीति के विभाजन का ठोस आधार तैयार कर दिया। छात्र राजनीति के मूल में तटस्थ भाव होना चाहिए। लोक हित के लिए छात्रों का संघर्षरत होना उचित है, लेकिन दलगत राजनीतिक मंत्र लेकर राजनीति करना कैम्पस की मर्यादा पर कट्टा लगाने के समान है। छात्र राजनीति में कोई नई करवट या सुखद बदलाव छात्रों के बीच समाजोन्मुखता और आदर्शवाद को बढ़ावा देकर ही लाया जा सकता है परंतु जिस तरह की उच्चस्तर राजनीति देखने को मिल रही है, उससे न तो कैम्पस की खोई साख लौटती दिख रही है, और न परिवर्तन की कोई ज्यादा आस बंधती है।

सत्ता बदलाव के मायने

श्रीलंका में बहुदलीय प्रणाली से चुनाव में वामपंथी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके का राष्ट्रपति चुना जाना न केवल एशिया महाद्वीप के लिए वरन वर्तमान विश्व के लिए भी महत्त्वपूर्ण संकेत है। नेपाल के बाद श्रीलंका में वामपंथ की विजय से जहां उपनिवेशवाद विरोधी पुराने नारे को नया जीवन मिलता दिख रहा है कि 'साम्राज्यवाद की कब्र बनेगी एशिया की धरती पर', वहीं परिवर्तन का चक्र लैटिन अमेरिका से घूम कर पृथ्वी के हमारे गोलार्ध की तरफ आता भी दिख रहा है। कुछ दिन पहले न केवल वामपंथ मर गया था, बल्कि मार्क्सवाद भी फिर जीने वाला नहीं था। लेकिन नव-उदारवाद की नीति-कर्ज से विकास और समृद्धि हासिल करने-की दारुण विफलता ने पहले लैटिन अमेरिकी देशों में, अब एशियाई देशों में वामपंथ की लहर जगा दी है।

इसका सबसे बड़ा संकेत यह है कि विचार मरता नहीं। इसीलिए मृत भगत सिंह ब्रिटिश शासन के लिए जिंदा भगत सिंह से ज्यादा खतरनाक था। यह वात प्राचीन काल से चली आती है। इसीलिए चार्वाक की निंदा आदिकाव्य रामायण में करनी पड़ी थी! इसीलिए बुद्ध की मृत्यु के शताब्दियों बाद भारतीय सामंतवाद और उसके ब्राह्मणवाद को बुद्ध के प्रभाव उन्मूलन की जरूरत पड़ी। मार्क्सवाद अब तक की समस्त यथार्थवादी और क्रांतिकारी दर्शन परंपराओं का उत्कर्ष है; उस पर हमला भी उतना ही भयानक है, और उसका जीवट भी उतना ही दुर्दम्य है। ऐतिहासिक संयोग मानिए कि जिस समय दूसरे गोलार्ध पर विश्व शक्ति अमेरिका में दो पूंजीवादी दलों के बीच बहुमत पाने के लिए जबरदस्त होड़ लगी है, उसी समय अंग्रेजों के गुलाम रह चुके सिलोन (श्रीलंका) में दिहाड़ी मजदूर के बेटे ने चुनाव जीत कर लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था वाले देशों को दिशा दी है।

दिसानायके, जिनका लोकप्रिय नाम 'एकेडी' (अनुरा कुमारा दिसानायके) है, लोकप्रिय नेता होने के साथ ही निडर क्रांतिकारी रहे हैं, जिस 'जनतांत्रिमुक्ति पेरामुना' पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसने 1987 में दूसरी सशस्त्र क्रांति के प्रयत्न में असफलता के बाद 'पीपुल्स पावर गठबंधन' बनाया। 2022 में श्रीलंका के चरम आर्थिक-राजनीतिक संकट के दौरान जनता के विद्रोह का नेतृत्व करने वालों में प्रमुख थे। 2024 के चुनाव से सात महीने पहले फरवरी में वे निजी तौर पर भारत आए थे, यहां विदेश मंत्री और सुरक्षा सलाहकार से मुलाकातें की थीं। इससे पता चलता है कि श्रीलंका में परिवर्तन का जितना सीधा प्रभाव भारत पर पड़ता है, सम्राट अशोक के समय से-साढ़े तीन हजार साल के-वाणिज्यिक संबंध और वर्तमानकालिक तमिल समस्या के कारण, उतना ही प्रभाव भारत से संबंध का श्रीलंका पर भी पड़ता है। लेकिन एक मार्क्सवादी के चुनाव से भारत के 'बौद्धिक' क्षेत्र

में आशंका फैल गई कि चीन समर्थक एकेडी भारत के लिए प्रतिकूल होंगे। ऐसी ही आशंका नेपाल में मार्क्सवादी प्रचंड के राष्ट्रपति बनने के बाद व्याप्ती थी। तब 'हिन्दू राष्ट्र' के चोले से बाहर निकले नेपाल के साथ भारत के हिन्दू-हृदय-सम्राट शासकों ने संबंध खराब करने की काफी कोशिशें की थीं। नेपाल के तो चीन से भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं लेकिन श्रीलंका की स्थिति अलग है। नेपाल धरती से घिरा है तो श्रीलंका समुद्र से घिरा है। जितने सुदीर्घ नेपाल-भारत संबंध हैं, उतने ही श्रीलंका-भारत संबंध भी हैं। तीसरी शताब्दी ईसापूर्व में अशोक ने पुत्र-पुत्री महिंद-संघमित्रा को बौद्ध धर्म के साथ श्रीलंका भेजा था। नेपाल से भिन्न श्रीलंका की बहुसंख्यक आबादी बौद्ध हो गई। सदियों बाद जब दक्षिण भारत के मछुआरे और व्यापारी वहां जाकर बसे, उसके बहुत बाद बौद्ध-तमिल संघर्ष शुरू हुआ। आज के श्रीलंका में बौद्ध सिंहलियों और तमिल हिन्दुओं के बीच संघर्ष वहां संकट का बड़ा कारण है। इसलिए दोनों देशों के संबंध का निर्वाह किसी की व्यक्तिगत इच्छा या विचारधारा की सीमाओं से बंधा नहीं है। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ तो श्रीलंका 1948 में। दोनों की नियति में समानता है। दोनों ने समाजवादी रुझान वाली स्वतंत्र नीतियों पर चलने का निश्चय किया। थोड़ा आगे-पीछे श्रीलंका के लोकप्रिय नेता भंडारनायके की और भारत की प्रभावशाली नेता इंदिरा गांधी की हत्या सीआईए की योजना के तहत हुईं। इसके पहले सातवे दशक में दोनों देशों में हरित क्रांति हुई। उसके बाद कुछ आगे-पीछे दोनों ही नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों पर चले। इन नीतियों से उत्पन्न संकट ने भारत की विशाल आबादी और अर्थव्यवस्था को कुछ कम और श्रीलंका की छोटी आबादी और अर्थव्यवस्था को ज्यादा प्रभावित किया।

लॉकडाउन ने श्रीलंका में आर्थिक गतिविधियों को निष्क्रिय कर दिया। जैसे 1987 में आर्थिक संकट के साथ तमिल उग्रवाद और सिंहली राष्ट्रवाद के बीच सामाजिक तनाव बढ़ गया था, उसी तरह 2022-24 में सभी समस्याएं एक साथ घिर आईं। नतीजा यह कि 2022 में जिस संकट ने राष्ट्रपति गोटाबाया को सत्ताच्युत होकर देश छोड़ने पर विवश किया था, उसी के चलते 2024 के चुनाव में जनता ने दक्षिणपंथी दलों को बहिष्कृत करके कम्युनिस्ट क्रांतिकारी को सत्ता सौंपी। एकेडी ने अपने प्रमुख प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रपति विक्रमसिंघे पर लगभग 12 लाख मतों से विजय प्राप्त की। दो करोड़ की अल्प-जनसंख्या वाले देश में बड़ा फासला है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई दी तो वह केवल सद्भावना नहीं थी। उन्होंने उत्तर में दोनों देशों में सहयोग मजबूत होने की प्रतिबद्धता जताई, यह भी केवल औपचारिकता नहीं है। सामाजिक तनाव, सांप्रदायिक टकराव, क्षेत्रीय विषमता, घोर निर्धनता से दोनों देश परेशान हैं। पड़ोसियों में अच्छे रिश्ते दोनों के विकास में मददगार हैं। एकेडी को सिंहली बहुसंख्यकों के वोट का बहुमत मिला ही है, बड़ी संख्या में तमिल अल्पसंख्यकों का वोट भी मिला है।

आशा बंधती है कि जिन तमिल उग्रवादियों के संगठन 'लिट्टे' को अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने 'आतंकवादी' संज्ञा प्रदान की थी, उनकी नई पीढ़ी पुराना वैमनस्य भूल कर आर्थिक निर्माण और सामाजिक सौहार्द की नीतियां क्रियान्वित करने में नई सरकार का साथ देगी। जिस आशा में जनता ने एक गैर-शास्त्रज्ञ विद्रोह के बाद जनतांत्रिक माध्यम से परिवर्तन की कोशिश की है, उसी संकल्प से सरकार और विपक्ष, पूर्वी सिंहल-क्षेत्र और दक्षिणी तमिल प्रधान क्षेत्र, जनता और सरकार मिल कर इस कोशिश में सफलता पाएंगे।

(लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)

श्रीलंका
अजय तिवारी

एकेडी ने अपने प्रमुख प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रपति विक्रमसिंघे पर लगभग 12 लाख मतों से विजय प्राप्त की। दो करोड़ की अल्प-जनसंख्या वाले देश में बड़ा फासला है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई दी तो वह केवल सद्भावना नहीं थी। उन्होंने उत्तर में दोनों देशों में सहयोग मजबूत होने की प्रतिबद्धता जताई, यह भी केवल औपचारिकता नहीं है। सामाजिक तनाव, सांप्रदायिक टकराव, क्षेत्रीय विषमता, घोर निर्धनता से दोनों देश परेशान हैं। पड़ोसियों में अच्छे रिश्ते दोनों के विकास में मददगार हैं

गंभीर संकट में भारत का हीरा उद्योग

- भारत का हीरा क्षेत्र गंभीर संकट का सामना कर रहा है क्योंकि बीते तीन वर्षों में इसके आयात तथा निर्यात, दोनों में भारी गिरावट दर्ज की गई है
- आर्थिक शोध संस्थान जीटीआरआई (ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव) के मुताबिक, प्रयोगशाला में तैयार हीरों की बढ़ती मांग भी प्राकृतिक हीरों की मांग को प्रभावित कर रही है
- माना जाता है कि प्रयोगशाला में बने हीरे आर्थिक किफायती तथा टिकाऊ होते हैं। भारतीय हीरा क्षेत्र में 7 हजार से ज्यादा कंपनियां सक्रिय हैं

(फोटो: मीडिया प्रचुरता)

सीएम पद का मजाक बनाकर रख दिया है। पूरी दिल्ली में सड़कें खराब और टूटी-फूटी पड़ी हैं। सड़कों पर गंदगी और कूड़ा पड़ा रहता है। जगह जगह पानी की दिक्कत है। इस साल प्रदूषण से फिर दिल्ली गैस चेंबर बनेगी, क्या तैयारी चल रही है? मुश्किल से 3-4 महीने बचे हैं, उसमें भी चापलूसी को प्राथमिकता दी जा रही है।

स्वाति मालीवाल, सांसद
@SwatiJaiHind

शतरंज | मनोज चतुर्वेदी

महाशक्ति हैं हम

भारत अथक प्रयासों के बाद विश्व शतरंज में महाशक्ति के तौर पर उभरने में सफल रहा है। भारत ने 1956 में शतरंज ओलंपियाड में भाग लेने की शुरुआत की। इन सालों में तमाम हताशा भरे पलों से गुजरने के बाद वह पहली बार 2014 में कांस्य पदक जीतने में सफल रहा। पुरुषों के पदचिन्हों पर चलते हुए महिला टीम भी 2022 में कांस्य पदक जीतने में सफल हो गई और उनके साथ पुरुष टीम भी कांस्य पदक जीतने में कामयाब हुई। पर अब बुडापेस्ट शतरंज ओलंपियाड में भारत ने दोनों वर्गों के स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रच दिया है।

भारत की शतरंज की सफलताओं में अभी एक अध्याय और जुड़ना बाकी है। डी गुकेश सबसे कम उम्र में कैंडीडेट चैंपियन बन गए हैं। अब उन्हें 20 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक विश्व चैंपियनशिप मैच में चीन के डिंग लिरेन को चुनौती देनी है। कामयाब हो जाते हैं तो आनंद के बाद यह उपलब्धि पाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। अगर हम दोनों खिलाड़ियों के पिछले प्रदर्शनों को देखें तो गुकेश चैंपियन बनने के दावेदार हैं। लिरेन पिछले काफी समय से क्लासिकल शतरंज नहीं खेली है, और पीछे की लाइव रेटिंग में 21वें स्थान पर पिछड़ गए हैं। गुकेश शानदार प्रदर्शन से पांचवीं रैंकिंग पर हैं और 2800 ईएलओ रेटिंग तक पहुंचने के करीब हैं। भारतीय टीम के दबदबे की कहानी इस बात से भी दिखती है कि वह 32 सालों में सबसे बड़े अंतर से विजेता बनने वाली टीम है। भारतीय दबदबा इस बात से भी दिखता है कि उन्होंने 11 राउंड में खेलीं 44 बाजियों में से सिर्फ एक हारी और 27 जीतीं, बाकी बाजियां ड्रा रहीं। उन्होंने आखिरी राउंड में स्लोवेनिया को 3.5-0.5 अंकों से विजय पाकर खिताब पर कब्जा जमाया। महिला टीम ने आखिरी राउंड में अजरबेजान को फतह करके अपने की विजयी रेखा के पार पहुंचाया। भारत के लिए पुरुष वर्ग में गुकेश और अर्जुन एरिगेसी, महिला वर्ग में दिव्या देशमुख और वंतिका अग्रवाल ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते। अर्जुन भारत के नंबर एक खिलाड़ी हैं पर भारत ने उन्हें तीसरे बोर्ड पर खिलाने की रणनीति बनाई जो कारगर साबित हुई। वह 10 में से नौ बाजियां जीत कर स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब हुए। गुकेश ने पहले बोर्ड पर खेल कर दस में से आठ बाजियां जीतीं और वह भी स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे।

महिला वर्ग में 18 वर्षीय दिव्या देशमुख और 21 वर्षीय वंतिका अग्रवाल ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीत कर भारत को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई। दिव्या ने 11 में से आठ बाजियां और वंतिका ने नौ में से छह बाजियां जीतीं। दोनों खिलाड़ी अजेय रहीं क्योंकि इनकी बाजी बाजियां ड्रा रहीं। अर्जुन को तीसरे बोर्ड पर खिलाने का फायदा यह मिला कि उन्हें हर राउंड में विपक्षी टीम के तीसरे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सामना करना पड़ा। इससे उन्हें 11 राउंड में 10 बाजियां जीतने में सफलता मिली और इससे वह तीसरे बोर्ड का व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने में सफल रहे। पर गुकेश टॉप बोर्ड पर खेले और उन्होंने सभी टीमों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का सामना करके 10 में से नौ बाजियां जीत कर व्यक्तिगत स्वर्ण जीता है। वह इस ओलंपियाड के एकलौते खिलाड़ी हैं, जिन्हें प्रदर्शन रेटिंग 3056 मिली है, और वह 3000 की संख्या को पार करने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। भारत के लिए 1998-2022 में शतरंज ओलंपियाड में सबसे ज्यादा 113 बाजियां खेलने वाले के शशिकिरन ने कहा, 'मुझे खुशी है कि भारत ने मेरे जीवनकाल में ही स्वर्ण पदक जीत लिया।

यह टीम बहुत खास है, क्योंकि पहला मौका है, जब भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी ईएलओ रेटिंग में 2700 से ऊपर वाले हैं।' वह इस बात से इत्तिफाक नहीं रखते कि वह इस टीम की जीत का आधार बनाने वाले हैं। वह कहते हैं, आधार बनाने वाले विश्वनाथन आनंद हैं और मैंने आनंद और युवा खिलाड़ियों के बीच ब्रिज बनाने का काम किया है।' वह भारतीय युवाओं से 2026 से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे थे पर इन युवाओं से समय से पहले ही डंका बजा दिया है। इस सफलता के अलावा भी भारतीय खिलाड़ियों ने साल 2024 में अपना झंडा बुलंद रखा है। भारत के तीन खिलाड़ियों ने कैंडीडेट टूर्नामेंट में भाग लिया और गुकेश मात्र 17 साल की उम्र में इसे जीतने में सफल रहे। इस समय फीडे की लाइव रेटिंग में भारत के दो खिलाड़ी टॉप पांच में शामिल हैं।

अर्जुन 1797.2 अंकों से तीसरे और डी गुकेश 2794 अंकों से पांचवें स्थान पर हैं। दोनों 2800 ईएलओ रेटिंग के पार जाने के करीब हैं। इससे पहले सिर्फ आनंद ही ऐसा कर सके हैं। भारतीय महिला टीम सातवें राउंड की समाप्ति पर बढ़त बनाए हुई थी। लेकिन वह आठवें राउंड में पोलैंड से हार गई और अगले राउंड में अमेरिका ने उसे ड्रा पर रोक दिया। भारत को चैंपियन बनने के लिए आखिरी राउंड में अजरबेजान पर जीत जरूरी थी। भारत ने बाजी जीतने के साथ स्वर्ण पदक जीतना पक्का कर दिया।

योग और युवा | श्रीराम शर्मा आचार्य

आत्मा और परमात्मा को, जड़ और चेतन को, प्रति और पुरुष को जोड़ देने का नाम योग है। यह ज्ञान और कर्म के दो युग्मों में विभक्त है। ज्ञान योग वह है जो चिंतन को हेय स्तर से ऊंचा उठा कर देव स्तर तक ले जाता है और मनोवृत्तियों को ब्रह्म चेतना में नियोजित करता है। कर्मयोग वह है जिसमें दैनिक क्रियाकलाप को परमार्थ प्रयोजन के आधार पर संचालित किया जाता है। शरीर और मन को पूर्व संचित पुण्य संस्कारों से विरत करके दिव्य जीवन के लिए अभ्यस्त करने की जो शारीरिक, मानसिक व्यायाम पद्धतियां हैं, वे भी योगाभ्यास के नाम से प्रसिद्ध हैं। आसन, प्राणायाम, जप, ध्यान, व्रत, तप, मुद्रा, बंध आदि साधनाएं उसी स्तर की हैं। ज्ञान और कर्म की दोनों ही धाराएं जब पशु स्तर से ऊंची उठ कर देव स्तर की ओर अग्रसर होती हैं, तो उसे समग्र साधना कहते हैं। केवल स्वाध्याय, सत्संग, मनन, चिंतन, ध्यान प्रभृति ज्ञान पक्ष तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया अपूर्ण एवं एकांगी है। उसी प्रकार जिन्होंने चिंतन परिष्कार को तिलांजलि देकर मात्र विधि विधान को ही सब कुछ मान लिया है, वे भी एक पहिये की गाड़ी चलाने वालों की तरह असफल रहते हैं। बिजली के ठंडे और गरम दो तार जब मिलते हैं, तब विद्युत प्रवाह संचालित होता है। इसी प्रकार ज्ञान और कर्म का, समन्वित रूप से भावना और साधना का स्तर समान रूप से आगे बढ़ाया जाता है, तो योग साधना की समग्र प्रक्रिया पूर्ण होती है, और उसका लाभ मिलता है, जो सच्चे योगियों को प्राप्त होता रहा है। अध्यात्म शास्त्र में वर्णित योग साधना का महत्त्व ऐसी ही सर्वांगपूर्ण साधना से संपन्न होता है। योग न तो कठिन है, न अशक्य है। वह सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। इस मार्ग पर न्यूनाधिक जितना भी चला जा सके तो उतना लाभ ही है। हानि की आशंका तो है ही नहीं। हठयोग प्रदीपिका में कहा गया है युवा, वृद्ध, अति वृद्ध, रोगी, दुर्बल कोई भी योगाभ्यास करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है-युवा वृद्धोवृद्धो वा व्याधितो दुर्बलोपि वा।
अभ्यासात्सिद्धिमाप्नोति सर्वयोगेष्वतन्द्रितः। सिद्धि नियमित अभ्यास से मिलती है, न वेषधारण सिद्धेः कारणं न च तत्कथा। क्रियैव कारणं सिद्धेः सत्यमेतन्न संशयः। योगाभ्यास में श्रम किया जाता है निरर्थक नहीं जाता।

रीडर्स मेल

विवादित बयान से बच जाना था

काश! हमारे नेता प्रतिपक्ष अपनी ही पार्टी के सांसद शशि थरूर की भावनाओं, विचारों एवं संवेदनाओं को समझ कर स्वयं की समीक्षा कर लेते तो विदेश में विवादित बयान देने से जहां बच जाते, वहीं स्वयं, दल, समाज, राज्य, राष्ट्र एवं मानवीय मूल्यों के प्रति एक सोच एवं दिशा देने में वेहतर साबित होते। राहुल का यह संकेत है कि हमारी पार्टी विदेश नीति से जुड़े प्रमुख मुद्दों जैसे अमेरिका के साथ संबंध, आतंकवाद खत्म होने तक कोई बातचीत नहीं, बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों को लेकर चिंताओं पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के साथ हैं। विदेशों में भारत की खराब छवि को इस प्रकार से प्रस्तुत करना, क्या भारतीय विदेश नीति को खोखला करना नहीं है? विदेश में देश को नीचा दिखाना किस प्रकार से राष्ट्र की विदेश नीति में भारत सरकार का सहयोग, समर्थन, सहानुभूति तथा सत्यता के साथ सोच का सूचक है? यह बात समझ से परे नजर आती है।

मनोज श्रीवास्तव, अमेठी

उभरी अश्विन की काबिलियत

चेन्नई टेस्ट में बांग्लादेश के विरुद्ध भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए कई उपलब्धियां हासिल की हैं। ऑल राउंडर अश्विन के धमाकेदार प्रदर्शन से न सिर्फ उनकी काबिलियत उभरी है, बल्कि देश ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी बादशाहत फिर सिद्ध कर दी है। अश्विन श्रेष्ठ ऑलराउंडर के रूप में धाक जमाने में कामयाब हुए हैं। भारत के लिए चौथी पारी में सर्वाधिक विकेट लेने वालों में (99 विकेट) सबसे ऊपर अश्विन मुरलीधरन 133 मैचों में सर्वाधिक पांच विकेट (67 बार) से दूसरे नंबर पर अवश्य हैं, लेकिन इसके लिए अश्विन ने मात्र 101 मैच (37 विकेट) खेले हैं। टेस्ट मैच में सर्वाधिक शतक के साथ पांच विकेट लेने का कारनामा इयान बॉथम (5) के बाद अश्विन (4) के नाम है। इस तरह देखा जाए तो अश्विन ने न अच्छा व्यक्तिगत प्रदर्शन किया है, और देश की उपलब्धियां बढ़ाई हैं। आज भारत डावल्यूटीसी तालिका में 71.67 जीत प्रतिशत लेकर शीर्ष पर है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत की क्रिकेट में बादशाहत ऐसी शीर्ष पर पहुंचे जिसे पार करना क्रिकेट खेलने वाले देशों के लिए आसान न हो। अश्विन और विजेता भारतीय टीम को बधाई।

अमृतलाल मारू 'रवि' इंदौर, मप्र

छवि धूमिल करने का प्रयास

निस्संदेह ट्रेनों की पटरी से उतारने के लिए पटरी पर सिलिंडर, सीमेंट के ब्लॉक, लोहे की छड़ें, पत्थर, साइकिल इत्यादि रखना और फिशर प्लेटों का निकालना दुर्योग नहीं, बल्कि सोची-समझी साजिश का हिस्सा हैं। असामाजिक तत्व न केवल जान-माल की भारी क्षति पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि सरकार की छवि भी धूमिल करना चाहते हैं। पिछले 2-3 महीनों में ऐसी घटनाओं की संख्या काफी बढ़ गई है। भारतीय रेलवे, जो विश्व में चौथी सबसे बड़ी रेलवे है और जिसकी ट्रैक की लंबाई लगभग 125000 किमी. से ज्यादा है, पर हर किमी. पर निगरानी रखना मुश्किल टास्क है लेकिन क्वेस्टरी करने की घटनाओं ने भारतीय रेलवे और सरकार के सामने और कोई उपाय नहीं छोड़ा है। बुलेट ट्रेन, वंदे भारत इत्यादि सभी आधुनिक रेल देश की जरूरत है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा से ऊपर कुछ नहीं है। इस खतरनाक साजिश की तह तक पहुंचना बेहद अहम है।

बाल गोविंद, नोएडा

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इंडिया गरुड़ कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया काज़ी द्वारा सहारा इंडिया परिवार, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा से मुद्रित तथा 705-706, राजमहल कला, रजाबर हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रतन। निदेश*।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23363368, 23363369, 23363371, 23363372, फैक्स - 23363370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2560750
वर्ष-34, अंक 42
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त सामग्री के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मसलों के लिए उत्तरदायी

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 189

कारोबारियों को नुकसान

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के एक नये अध्ययन 'इक्विटी डेरिवेटिव क्षेत्र में लाभ-हानि का विश्लेषण (वित्त वर्ष 22-24)' से संकेत मिलता है कि डेरिवेटिव में कारोबार नुकसानदेह है। इसमें ब्रोकरेज और विनिमय शुल्क के कारण लेनदेन की लागत बढ़ती है और इनके कारण कुल मिलाकर डेरिवेटिव कारोबार ऐसे कारोबार में बदल जाता है जहां हर नुकसान किसी प्रतिपक्ष के लाभ के समान होता है। अध्ययन से संकेत मिलता है कि एक करोड़ से अधिक लोग जो डेरिवेटिव (वायदा एवं विकल्प यानी एफऐंडओ) में कारोबार करते हैं उनमें से 93 फीसदी को समीक्षा अवधि में औसतन दो लाख रुपये प्रति कारोबारी की दर से नुकसान हुआ। इस नुकसान में लेनदेन की लागत शामिल है। ऐसे सभी लोगों का समग्र नुकसान करीब 1.8 लाख करोड़ रुपये है। सबसे अधिक नुकसान झेलने वाले यानी करीब चार लाख कारोबारी ऐसे थे जिन्हें औसतन 28 लाख रुपये प्रति व्यक्ति का नुकसान हुआ। लेनदेन की लागत इसमें भी शामिल है। इसके विपरीत लेनदेन की लागत के बाद केवल एक फीसदी व्यक्तिगत कारोबारियों का मुनाफा एक लाख रुपये से अधिक रहा।

वित्त वर्ष 24 में प्रोपराइटरी कारोबारी और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) ऐसे वर्ग रहे जिन्होंने क्रमशः 33,000 करोड़ रुपये और 28,000 करोड़ रुपये का सकल कारोबारी लाभ (लेनदेन की लागत से पहले) हासिल किया। जबकि व्यक्तिगत कारोबारियों को लेनदेन की लागत से पहले 61,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। मुनाफा ट्रेडिंग के अलगोरिद्म से उत्पन्न हुआ। एफपीआई का 97 फीसदी मुनाफा और 96 फीसदी प्रोपराइटरी मुनाफा अलगोरिद्मिक ट्रेडिंग से हुआ। औसतन व्यक्तिगत कारोबारियों ने वित्त वर्ष 24 में एफऐंडओ लेनदेन की लागत के रूप में प्रति व्यक्ति 26,000 रुपये खर्च किए। वित्त वर्ष 22 से 24 के दौरान व्यक्तियों ने लेनदेन की लागत पर सामूहिक रूप से 50,000 करोड़ रुपये खर्च किए और इस लागत में से 51 फीसदी ब्रोकरेज शुल्क और 20 फीसदी विनिमय शुल्क है। करीब 43 फीसदी व्यक्तिगत कारोबारी 30 वर्ष से कम आयु के हैं और करीब 72 फीसदी कारोबारी शीर्ष 30 शहरों से बाहर छोटी जगहों पर रहते हैं। अध्ययन में दावा किया गया है कि 75 फीसदी से अधिक घाटा सहने वाले एफऐंडओ कारोबारी निरंतर नुकसान के बावजूद इस क्षेत्र में कारोबार करते रहे।

एक्सचेंजों में पारदर्शी और निष्पक्ष कारोबारी प्रक्रियाएं अपनाए जाने के अलावा नियामक निवेशकों को शिक्षित करने की भी बात कहता है। ऐसे अध्ययन इस बारे में मूल्यवान उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। डेरिवेटिव कारोबार परेटो सिद्धांत का शिखर उदाहरण है जहां सात फीसदी व्यक्तिगत कारोबारियों को मुनाफा हुआ जबकि शेष को नुकसान। किसी व्यक्ति के पास अलगोरिद्म संसाधनों की कमी की संभावना वाकई कम है खासतौर पर तब जबकि लेनदेन की लागत को भी ध्यान में रखा जाए। बहरहाल एफऐंडओ कारोबार को व्यक्तिगत कारोबारियों को नुकसान पहुंचाने वाला बताने के अलावा नियामक के पास ज्यादा कुछ करने को नहीं है।

निश्चित तौर पर उसने यह प्रयास भी किया कि कम पूंजी वाले निवेशकों की रक्षा की जाए। इसके लिए उसने अनुबंध के आकार और मार्जिन की समीक्षा चाही है। इस अध्ययन के मुताबिक तो यह व्यक्तिगत कारोबारियों पर निर्भर है कि वे अपने कारोबारी रुझान की समीक्षा और अंकेक्षण करें। समझदार कारोबारी इसके प्रभाव को समझकर कारोबारी रणनीतियों में बदलाव करेंगे या फिर बाजार से बाहर निकल जाएंगे।

संस्थागत नजरिये से व्यक्तिगत एफऐंडओ कारोबारी एक आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। इसकी तुलना सरकारी लॉटरी से की जा सकती है। लॉटरी का टिकट खरीदने वाले हर व्यक्ति के नुकसान सहने की संभावना होती है लेकिन फिर भी टिकट खरीदने वालों से काफी राशि एकत्रित होती है। एक जीवंत एफऐंडओ बाजार बेहतर मूल्य निर्धारण को सक्षम बनाता है और प्रतिभागी अधिक कुशलता से हेजिंग कर सकते हैं। कुल मिलाकर कारोबारी वह आकार तैयार करते हैं जिससे भारी नकदी और निम्न प्रसार तब होता है। इससे सभी कारोबारी लाभान्वित होते हैं और यह हेजिंग करने वालों के लिए खास उपयोगी है। बहरहाल, खुदरा कारोबारी भी व्यक्तिगत स्तर पर इससे मिलने वाले सबक से लाभान्वित होंगे।

जातिगत समानता को समाज में मिले बढ़ावा

गुणवत्ता भरी शिक्षा मिलने और अधिक सामाजिक पूंजी होने के बावजूद भारतीय समाज में उच्च एवं निम्न जातियों के लोगों के बीच आय में काफी असमानता है। चर्चा कर रहे हैं नितिन देसाई

किसी अर्थव्यवस्था में असमानता प्रायः लोगों को विरासत में मिली वस्तुओं में भिन्नता का नतीजा होती है। असमानता की चर्चा करने पर विरासत में मिली जिस वस्तु का जिक्र सबसे अधिक होता है वह है धन-संपत्ति। किंतु यदि सामाजिक रुतबा या ओहदा अगर आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा बन जाए तो वह भी असमानता को जन्म देता है।

भारत में सभी अच्छी तरह जानते हैं कि लोगों की जातियों से जुड़े सामाजिक प्रभाव का असर उनकी आर्थिक संभावनाओं पर पड़ता है। यह बात अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) यानी कथित निम्न जातियों के लिए सकारात्मक कार्रवाई (अफर्मेटिव एक्शन) के प्रावधानों में भी दिखती है। किंतु कुछ लोगों का तर्क है कि हमें अफर्मेटिव एक्शन के पात्र लोगों के बीच भी अधिक गरीब लोगों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इसका लाभ उन लोगों को भी मिलना चाहिए, जो निचली जाति से ताल्लुक नहीं रखते मगर गरीब हैं।

कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जाति जनगणना की हिमायत कर रहे हैं। उनका उद्देश्य इस बात की पड़ताल करना है कि समाज में सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को अफर्मेटिव एक्शन का कितना लाभ मिल रहा है और इसे कितना बढ़ाया जा सकता है। इन दो अलग-अलग नजरियों के बीच इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि सभी स्थितियां समान रहने पर भी निचली जाति के किसी व्यक्ति का आय कम तो नहीं रह जाती या उसे दूसरे लोगों की तुलना में कम आर्थिक अवसर तो नहीं मिलते।

भारतीय मानव विकास सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित दो हालिया अध्ययन इस बात का स्पष्ट संकेत देते हैं कि आय का स्तर तय करने में जाति की अहम भूमिका होती है। पहले अध्ययन में आय कम होने के कई कारण गिनाए गए हैं और कहा गया है कि निचली जातियों के लोगों की सालाना आय देश की शेष आबादी की तुलना में 21.1 प्रतिशत कम है। आंकड़ों को अलग-अलग देखें तो पता चलता है कि आदिवासियों की आय उच्च जाति समूहों की तुलना में औसतन 20.7 प्रतिशत कम है जबकि दलितों की आय 27.74 प्रतिशत, मुसलमानों की 20.17 प्रतिशत और ओबीसी की आय 19 प्रतिशत कम है।

दो बाते हैं, जो असमानता कम कर देती हैं - उच्च शिक्षा और किसी उच्च आय वाले राज्य में रिहायश। अध्ययन बताता है कि निचली जातियों में जिन लोगों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, उनकी आय ऊंची जाति के लोगों की तुलना में औसतन 10.3 प्रतिशत ही कम है। आदिवासियों के मामले में असमानता और भी कम हो जाती है। अध्ययन बताता है कि किसी राज्य में प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 10,000 रुपये बढ़ जाता है तो आदिवासियों के लिए जाति आधारित आय असमानता में औसतन 9.05 प्रतिशत कमी आ जाती है। दलितों में असमानता 7.6 प्रतिशत, ओबीसी में 4.9 प्रतिशत और मुसलमानों में 1.8 प्रतिशत अंक कम हो जाती है। लेकिन अंतर कम ही होता है, पूरी तरह खत्म नहीं होता।

इसी सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित एक दूसरा अध्ययन बताता है कि निम्न एवं उच्च जातियों के कारोबार मालिकों को किस तरह के भेदभाव झेलने पड़ते हैं। कारोबार चलाने वाले दलितों की आय उन ओबीसी, आदिवासी और मुसलमान कारोबारियों के मुकाबले कम होती है, जिन्हें समाज से अलग-थलग तो नहीं रखा जाता मगर जिन्हें सामाजिक-आर्थिक नुकसान उठाने पड़ते हैं। किसी व्यक्ति का दूसरी जातियों के अन्य पेशेवरों के साथ जो व्यक्तिगत संपर्क या तालमेल होता है, उसके दायरे को सामाजिक पूंजी कहते हैं। अध्ययन में कहा गया है कि दलित व्यक्ति की सामाजिक पूंजी अधिक हो तो भी आय में अंतर बरकरार रहता है, जिससे संकेत मिलता है कि जातिगत भेदभाव अपना असर दिखाते रहते हैं। यह भी पता चला कि शिक्षा से दलितों की आय में उसी तरह सुधार होता है, जैसे दूसरे वर्गों की आय में होता है।

ये अध्ययन तो इस वर्ष प्रकाशित हुए हैं मगर उनमें इस्तेमाल किए गए सर्वेक्षण के आंकड़े एक दशक से अधिक पुराने हैं। पहले अध्ययन में 2005 से 2012 के सर्वेक्षण नतीजे इस्तेमाल किए गए थे। इस अध्ययन के अनुसार ऊंची जातियों और निम्न जातियों में असमानता कम हुई है मगर खत्म नहीं हुई है। क्या हम यह मान सकते हैं कि आय में वृद्धि के कारण अंतर अब और कम हो गया है? संभवतः कम हुआ होगा मगर यह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। शीर्ष पर पहुंच चुके दलितों और आदिवासियों से बात करने पर पता चलता है कि वे सामान्य से एक पायदान ऊपर हैं इसलिए वे भेदभाव का मुकाबला कर पाए और इससे बाहर निकल पाए।

जिन बच्चों के माता-पिता अनियमित कामगार हैं, उन्हें ज्यादा नुकसान होता है। मैंने पाया है कि निर्माण स्थल पर ही अस्थायी रिहायश बना लेने वाले श्रमिकों के बच्चों को अक्सर शिक्षा मिल ही नहीं पाती और बड़े होकर वे भी अनियमित कामगार बनने के लिए अभिशप्त होते हैं। यहां भी दलितों और आदिवासियों तथा दूसरी जाति के लोगों में फर्क होता है। एससी/एसटी को छोड़कर अन्य जातियों पर अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2004 में अनियमित कामों में उनकी हिस्सेदारी 83 प्रतिशत थी, जो आंकड़ा 2018 में घटकर 53 प्रतिशत रह गया। इस दौरान वेतन देने वाली नियमित और बेहतर गुणवत्ता वाली नौकरी में उनकी भागीदारी इतनी ही बढ़ गई। एससी/एसटी का भी अनियमित काम कम हुआ मगर यह 86 प्रतिशत से कम होकर 76 प्रतिशत रहा यानी इसमें गिरावट कम रही।

इसलिए अफर्मेटिव एक्शन की शुरुआत इस प्रमाणित तथ्य से होनी चाहिए कि उच्च जाति के व्यक्ति के बराबर योग्य और शिक्षित होने पर भी निम्न जाति के व्यक्ति की आय में काफी कमी रहेगी। यह तथ्य भी स्वीकार करना होगा कि कारोबार का मालिक यदि दलित है तो उसे गैर-दलित कारोबारी से पिछड़ना ही पड़ता है।

जिस वास्तविक बदलाव की आवश्यकता है वह है जातियों के बीच अलगाव में कमी करना या इसे पूरी तरह खत्म करना। इस राह में सबसे बड़ी बाधा है अपनी ही जाति में विवाह को अनिवार्य मानने की रूढ़ि। यह रूढ़ि या चलन चार वर्णों में ही नहीं बल्कि उनके अंतर्गत आने वाली करीब 4,000 जातियों में भी चला आ रहा है। इसके कारण सामाजिक अलगाव बढ़ता ही जाता है। वर्ष 2005 के एक सर्वेक्षण के अनुसार केवल 6 प्रतिशत विवाह अंतरजातीय थे यानी वर और वधू अलग-अलग जातियों से थे। अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने से दीर्घकाल से चली आ रही सामाजिक असमानता खत्म करने में मदद मिल सकती है।

यह बात सरकारी योजना 'डॉ भीमराव अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर-कास्ट मैरिजेज' में स्वीकार की गई है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्ति का विवाह किसी अन्य जाति में होने पर 2.5 लाख रुपये बतौर प्रोत्साहन दिए जाते हैं। इस योजना की शुरुआत 2013-14 में हुई थी और पांच वर्षों में औसतन 17,000 से अधिक लोग इसका लाभ उठा चुके थे। किंतु इन लाभार्थियों में कोई भी बिहार या उत्तर प्रदेश से नहीं था।

एक सदी से भी पहले छुआछूत के खिलाफ शुरू किए गए राजनीतिक अभियान के कारण जातिगत भेदभाव में कमी आई है। बाद में इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए संविधान में एक प्रावधान भी लाया गया। शहरीकरण में तेजी और पेशागत स्तर पर सभी जातियों के लिए अवसर बढ़ने से भी परंपरागत जाति प्रथा के दोष कम हुए हैं। लेकिन इसका दीर्घकालिक समाधान तभी होगा जब जातीय भेदभाव खुद ही खत्म हो जाएगा। भीमराव आंबेडकर ने भी यही कहा, 'मेरे विचार से हिंदू समाज अपनी रक्षा के लिए पर्याप्त सामर्थ्य जुटाने की आशा तभी कर सकता है, जब वह पूरी तरह जातिरहित हो जाए।' आंबेडकर ने अपने भाषण 'द अनाइअलेशन ऑफ कास्ट' में यह बात लिखी थी मगर यह भाषण वह कभी पढ़ नहीं सके।

सरल शब्दों में कहें तो किसी समाज में जातीय समता को बढ़ावा तभी मिल सकता है जब विरासत में जाति का महत्त्व बहुत कम माना जाए। हमें ऐसा सामाजिक ताना-बाना तैयार करना होगा, जिसमें अधिक से अधिक परिवार अंतरजातीय तरीके से एक दूसरे से जुड़े हों।

फाइनैंस के क्षेत्र में एसआरओ की जानकारी

अगस्त में भारतीय रिजर्व बैंक ने फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पॉवरमेंट (फेस) को वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) क्षेत्र में स्वनियामक संस्था या सेल्फ रेग्युलेटरी ऑर्गनाइजेशन (एसआरओ) की मान्यता दे दी। बैंकिंग नियामक को तीन आवेदन मिले थे। इनमें से एक को एसआरओ का दर्जा दिया गया, एक से कहा गया कि वह बताई गई जरूरतें पूरी कर दोबारा आवेदन करे और तीसरे आवेदन पर विचार चल रहा है।

देश में बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए रिजर्व बैंक से मंजूरी प्राप्त कितने एसआरओ हैं? 1944 में बैंकरों के एक समूह ने देवकरण नानजी बैंकिंग कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन प्राणलाल देवकरण नानजी की अध्यक्षता में एक संघ बनाने के लिए बैठक की। दो वर्ष बाद 26 सितंबर, 1946 को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) का जन्म हुआ। बैंकिंग क्षेत्र की यह अग्रणी संस्था 1966 से ही बैंकों, रिजर्व बैंक और सरकार के बीच तालमेल बिठाने का काम कर रही है। लेकिन वह एसआरओ नहीं है। लघु वित्त बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाली नई संस्था एसोसिएशन ऑफ स्माल फाइनैंस बैंक्स ऑफ इंडिया भी एसोसिएशन है, एसआरओ नहीं।

वर्ष 1958 में स्थापित फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफईडीएआई) शायद इस क्षेत्र का पहला एसआरओ है। इसका गठन कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत किया गया है। इसका जिम्मा बैंकों और जनता के बीच अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार के नियम बनाना है। साथ ही विदेशी मुद्रा बाजार के सुधार और विकास के लिए रिजर्व बैंक के साथ मिलकर काम करना भी उसका जिम्मा है।

ट्रेजरी प्रबंधकों, विदेशी मुद्रा कारोबारियों और विदेशी मुद्रा ब्रोकरों को लेकर बनाई गई फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी एसआरओ नहीं है। इसी प्रकार फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट तथा डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बाजार की स्वैच्छिक संस्था है, एसआरओ नहीं। 2004 में स्थापित फाइनैंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल कर्ज देने वाले एनबीएफसी का प्रतिनिधित्व करती है। यह सरकार और रिजर्व बैंक से भी संबद्ध है लेकिन औद्योगिक संगठन है, एसआरओ नहीं। एनबीएफसी क्षेत्र में सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दो एसआरओ हैं: सा-धन और माइक्रोफाइनैंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (एमएफआईएन)। सा-धन की स्थापना 1999 में यानी एमएफआईएन से एक दशक पहले हुई थी। लेकिन उसे एमएफआईएन से एक वर्ष बाद 2015 में एसआरओ का दर्जा मिला।

बैंकिंग साख

तमाल बंद्योपाध्याय

एक बार फिर फिनटेक क्षेत्र के एसआरओ की बात करते हैं। उससे क्या करने की अपेक्षा रहती है? रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास कह चुके हैं कि नियमित मशविरे, फीडबैक और नीतिगत संवाद के जरिये एसआरओ मुक्त संवाद की सुविधा दे पाएंगे। इससे फिनटेक को नियामकीय अपेक्षाओं और प्राथमिकताओं के बारे में पता रहेगा।

हाल ही में इस समाचार पत्र के साथ साक्षात्कार में फेस की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुगंध सक्सेना ने कहा, 'हर तरह की फिनटेक को एसआरओ के दायरे में लाना हमारी पहली प्राथमिकता है...फिलहाल हमारे 65 सदस्य हैं लेकिन फिनटेक का संसार बहुत बड़ा है, जिसमें कई तरह के कारोबारी मॉडल और कारोबारी स्तर की कंपनियां हैं। हम चाहते हैं कि सभी फेस में शामिल हों।'

रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2022 में भुगतान व्यवस्था परिचालन मसलन कार्ड नेटवर्क, कार्ड उपभोक्ता, बैंक वॉलेट, भुगतान एग्रीगेटर्स, एटीएम और यूपीआईके लिए कायदे बनाने तथा लागू करने के मकसद से एसआरओ बनाने की बात कही तथा दिशानिर्देशों का मसौदा जारी किया।

एसआरओ का प्राथमिक काम है सभी अंशधारकों का प्रतिनिधित्व, मानक और श्रेष्ठ व्यवहार तय करना, आंकड़े जुटाना, निगरानी करना और उल्लंघन की सूचना देना, समस्याओं को हल करना, विवाद निस्तारण, उपभोक्ताओं को जागरूक करना और उनका संरक्षण करना, शोध एवं विकास में मदद करना, व्यवस्थाओं की निगरानी और रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन करना।

जून 2024 में रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी के क्षेत्र में एसआरओ की मान्यता देने के लिए आवेदन मंगाए। आवेदकों को एसआरओ की मान्यता मिलने या परिचालन शुरू होने के एक साल के भीतर कम से कम 2 करोड़ रुपये की संपत्ति तैयार करनी होगी। रिजर्व बैंक इस क्षेत्र के लिए अधिकतम दो एसआरओ को मान्यता देगा। आवेदन मंगाते समय रिजर्व बैंक ने कहा कि एनबीएफसी के लिए एसआरओ की कल्पना मुख्य तौर पर निवेश और ऋण, आवास ऋण तथा सेवा क्षेत्र के लिए की गई थी। परंतु इसमें अन्य श्रेणियां भी शामिल हो सकती हैं।

इससे पहले मई 2024 में रिजर्व बैंक ने फिनटेक एसआरओ के लिए दिशानिर्देश जारी किए। उसने कहा कि यह एसआरओ किसी भी बाहरी प्रभाव से मुक्त स्वतंत्र संस्था होगी और नियामकीय मानकों को बरकरार रखने के लिए काम भी करेगी। आशा है कि ये एसआरओ सदस्यों को मानकों पर चलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और नैतिक व्यवहार तथा बाजार के प्रति निष्ठा को बढ़ावा देंगे।

इनकी जिम्मेदारियों में प्रमुख हैं नियामकीय मानक बनाना और लागू करना, नैतिक आचरण को बढ़ावा देना, विवाद सुलझाना, सदस्यों के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही लाना। इनके दायरे में विनियमित फिनटेक, विनियम से बाहर की फिनटेक, ऋण सेवा प्रदाता, निधी बैंक्स आदि शामिल हैं।

देश में इस क्षेत्र में तकरीबन 10,000 नियमित, अनियमित और परोक्ष रूप से विनियमित संस्थाएं हैं। 2025 तक उनका बाजार करीब 150 अरब डॉलर होने का अनुमान है। अमेरिका और चीन के बाद हम इस क्षेत्र में तीसरे सबसे बड़े मुल्क हैं। सबसे बड़ा क्षेत्र है भुगतान और उसके बाद ऋण। भुगतान और ऋण की निगरानी रिजर्व बैंक करता है और फिनटेक क्षेत्र में इनकी करीब 80 फीसदी हिस्सेदारी है। मगर सभी संस्थाएं विनियमित नहीं हैं।

बहरहाल कुछ प्रश्न बरकरार हैं:

- बैंकिंग के लिए अभी तक कोई एसआरओ क्यों नहीं है? अगर औद्योगिक संगठन से काम चल सकता है तो एसआरओ की क्या आवश्यकता है?
- एनबीएफसी क्षेत्र में बहुत विविधता है। इस क्षेत्र में नियमित सदस्य सबसे अधिक होने की संभावना के बाद भी दो ही एसआरओ क्यों हों?
- बड़ी टेक कंपनियों या प्रभावशाली प्रौद्योगिकी कंपनियों मसलन अल्फाबेट, ऐपल, मेटा, एमेजॉन या माइक्रोसॉफ्ट का क्या? उन्हें टेकफिन भी कहा जाता है। वे ऋण देती हैं, डिजिटल भुगतान की सुविधा देती हैं, बीमा योजना और संपत्ति प्रबंधन की सुविधा भी देती हैं। क्या उन्हें एसआरओ के तहत आना चाहिए?
- कई संस्थाएं ऋण और भुगतान दोनों में शामिल हैं। वे कुछ के लिए सीधे तौर पर तो अन्य के लिए परोक्ष रूप से विनियमित हैं। इसे दायरे में कैसे लाएंगे?

ऐसा करने का एक तरीका यह हो सकता है कि काम के मुताबिक विभिन्न क्षेत्रों में एसआरओ स्थापित किए जाएं। साथ ही नियमित और अनियमित संस्थाओं के साथ अलग-अलग व्यवहार किया जा सकता है। एसआरओ के प्रभावी क्रियान्वयन का सूत्र यही है कि दूसरे के क्षेत्र में दखलंदाजी न हो।

आपका पक्ष

साइबर सुरक्षा अमले में वृद्धि हो, लोग सतर्कता भी बरतें

देश में साइबर अपराध पर नियंत्रण करने वाले अमले की बड़ी कमी महसूस की जा रही है। वहीं साइबर अपराधियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर अब आधुनिक और नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षित युवा टीम की पर्याप्त संख्या में शीघ्र भर्ती हो, क्योंकि साइबर ठग नित नए तरीकों से विश्व के किसी भी कोने में बैठ कर भारतीयों के बैंक खाते में सेंध लगा रहे हैं। सुशिक्षित, बैंकिंग स्टाफ और पुलिस वाले भी ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग और हनी ट्रैप आदि के शिकार हो चुके हैं। मोबाइल पर मिले संदेश, जानकारी या कॉल की बारीकी से जांच करने और शंका होने पर त्वरित शिकायत करने की जरूरत है। यही बड़ी सतर्कता होगी, जो साइबर ठगों से सुरक्षित रखेगी, अन्यथा सरकारी अमला या पुलिस भी कभी-कभी असहाय हो जाती है। साइबर सुरक्षा के लिए सतर्कता ही जरूरी है।

बी एल शर्मा, उज्जैन

देश में साइबर अपराध पर नियंत्रण करने के लिए सरकार को प्रशिक्षित टीम का गठन करना चाहिए

बजट राशि का अपव्यय रोकना जरूरी

अधिकांश राज्य सरकारें महज सत्ता में बने रहने के लिए वोट बैंक की राजनीति का लक्ष्य बनाते हुए विपुल धनराशि का अपव्यय कर रही हैं। लोकलुभावन योजनाओं के बजाय समाज के सभी वर्गों के हित में कार्य करना सरकार का पहला दायित्व है। अनुत्पादक योजनाओं और तुष्टीकरण की नीति के बजाय सृजनात्मक योजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। बजट में उपलब्ध कोष और आय व्यय के आकलन के अनुसार खर्च करने पर ही वित्तीय संकट से बचा जा सकता है।

पूर्वा लुनावत, औरंगाबाद

राजस्व बढ़ाने के उपाय करने की आवश्यकता

वित्तीय संकट से बचने के लिए राज्य सरकारों को अपने राजस्व स्रोतों को बढ़ाने के लिए नए उपाय तलाशने होंगे। कर चोरी रोकने के लिए प्रभावी निगरानी प्रणाली की आवश्यकता है। अनावश्यक खर्चों में कटौती करके वित्तीय अनुशासन भी बनाए रखना होगा। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता का सही उपयोग भी किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को इन्फ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं में सार्वजनिक-निजी साझेदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे सरकारी संसाधनों पर दबाव कम होगा और निवेश का मार्ग भी खुलेगा। राज्य सरकारों को ऋण का प्रभावी प्रबंधन और अपने लुभावने वादों पर लगाम लगाने की भी जरूरत है।

विकास कुमार शर्मा, महराजगंज

बोझ बन रही लोकलुभावन योजनाओं पर नियंत्रण जरूरी

राज्यों को अपनी आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए तथा वित्तीय संकट से बचने के लिए केंद्रित राजनीतिक नेतृत्व, सामाजिक सोच में व्यापक परिवर्तन करने की जरूरत है। इसके साथ ही इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश, कानून व्यवस्था, आबादी नियंत्रण, बढ़ते भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना होगा। इसके साथ ही राज्यों द्वारा शुरू की गई लोकलुभावन नीतियों पर नियंत्रण करना होगा जो राज्यों के खर्च पर बोझ बन जा रहीं हैं।

सपना कबीरपंथी, पन्ना

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस तलवार मंगलवार को केन्या के मोम्बासा स्थित बंदरगाह पहुंचा। इस यात्रा का उद्देश्य संबंधों को और मजबूत करना तथा रचनात्मक सहयोग एवं पारस्परिक विकास के लिए भारत के संकल्प को दोहराना है।

सम्पादकीय

जीएसटी सुधार पर दूरदर्शी सोच की दरकार

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक में अब कुछ खास नहीं रहा है। आम तौर पर इनमें जीएसटी दरों में कुछ फेरबदल किया जाता है और फौरी जरूरतों के हिसाब से छोटे-मोटे प्रशासनिक बदलाव किए जाते हैं। मगर कर संरचना में व्यापक सुधार कर इसे श्रेष्ठ बनाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया जाता। लगता है कि जीएसटी परिषद मानती है कि कर प्रणाली अब स्थापित हो गई है, इससे जुड़े लोग इसके अभ्यस्त हो चुके हैं तथा इसे स्वीकार भी कर चुके हैं। परिषद की बैठकों में निर्णय फौरी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं और पूरी कवायद मामूली सुधार तक ही सीमित रहती है। यानी जीएसटी परिषद की बैठक में दीर्घकालिक फैसले नहीं लिए जाते हैं और सोचने एवं निर्णय लेने का दायरा काफी सीमित होता है। दूर तक नजर रखते हुए कर के साथ जुड़ी तीन लागत कम करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया जाता। ये लागत हैं - संग्रह पर होने वाला खर्च, अनुपालन पर खर्च और आर्थिक विकृति। इस सोच में राजस्व गंवाने का डर और राजस्व में कमी लाए बगैर बेहतर कर व्यवस्था तैयार करने के लिए बुनियादी शोध की कमी साफ दिखती है। इसलिए अचरज नहीं हुआ, जब जीएसटी परिषद की 9 सितंबर की बैठक में विदेशी विमानन कंपनियों द्वारा आयात की जाने वाली सेवाओं को छूट, कैंसर की दवाओं और हेलीकॉप्टर यात्रा पर शुल्क में कमी और जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी की समीक्षा तथा मुआवजा उपकर के लिए दो अलग-अलग समितियों के गठन का फैसला जैसे मामूली निर्णय ही लिए गए। ये सभी फैसले तात्कालिक जरूरत ध्यान में रखते हुए लिए गए यानी इनके पीछे व्यापक सुधार या भविष्य की जरूरतों की फिक्र नहीं है।

जीएसटी की मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त रूप से कारगर नहीं है और यदि राजस्व सुनिश्चित करते हुए इसे प्रतिस्पर्द्धी बनाना है तो बड़े सुधार करने होंगे। भारत को इस सदी के मध्य तक विकसित देश बनने की अपनी अभिलाषा पूरी करनी है तो उसे प्रतिस्पर्द्धी कर प्रणाली चाहिए, जिसके अवांछित परिणाम कम से कम हों। जीएसटी व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए निस्संदेह इसमें सुधार की आवश्यकता है। इससे कर प्रणाली में शामिल वस्तुओं या सेवाओं की संख्या काफी बढ़ जाएगी, दरें कम होंगी, उनमें अंतर भी कम होगा तथा सरल एवं पारदर्शी ढांचा होगा। ऐसी किसी भी व्यवस्था में करों के साथ जुड़ी तीनों लागतें - संग्रह में खर्च, अनुपालन पर खर्च और आर्थिक विकृति कम से कम होनी चाहिए। कर प्रणाली की दिशा बदलने के लिए यह एकदम सही समय है। बड़े सुधार तभी अच्छी तरह लागू होते हैं, जब अर्थव्यवस्था तेजी से प्रगति कर रही होती है क्योंकि इससे राजस्व बढ़ा हुआ ही रहता है। दुनिया भर में मूल्य वर्द्धित कर (वैट) के अनुभव बताते हैं कि कोई एक मॉडल या ढांचा सबके अनुकूल नहीं हो सकता। प्रत्येक देश ऐसी व्यवस्था अपनाता है, जो उसकी परिस्थितियों के अनुकूल होती है और सभी को स्वीकार्य होती है। फिर भी ज्यादातर देश ऊपर बताई गई तीनों लागत कम रखने के कुछ सामान्य सिद्धांतों पर अमल करते हैं।

बच्चों को प्रतिबंधित करने वाली सोशल मीडिया की आयु सीमा बहुत कम है, बहुत देर हो चुकी है

डिजिटल समुदायों तक पहुंच को पूरी तरह से बंद करने से कुछ युवाओं, विशेषकर हाशिए पर रहने वाले समूहों के लोगों की जीवनरेखा भी खराब हो सकती है। टिकटॉक, विशेष रूप से, स्वदेशी आस्ट्रेलियाई लोगों के लिए एक लोकप्रिय मंच के रूप में उभरा है, जिससे उन्हें एक ऐसा स्थान मिल गया है जहां वे बजट-अनुकूल व्यंजनों से लेकर नस्लवाद पर संबंधित प्रतिरोध यात्राओं तक सब कुछ साझा करते हैं। दूरदराज के इलाकों में रहने वाले स्वदेशी युवा, जो अपनी कहानियों को पारंपरिक मीडिया में प्रतिबिंबित नहीं देख पाते, वे कम अलग-थलग महसूस कर सकते हैं।

विजय गर्ग

बच्चों को प्रतिबंधित करने वाली सोशल मीडिया की आयु सीमा बहुत कम है, बहुत देर हो चुकी है लेकिन शोध से पता चला है कि सोशल मीडिया के लिए आयु सीमा किशोरों को इसके संभावित नुकसान से बचाने का सबसे प्रभावी तरीका नहीं है ऑस्ट्रेलिया की सरकार 16 साल तक के बच्चों को सोशल मीडिया से प्रतिबंधित करना चाहती है, और यह पता लगाने के लिए लाखों डॉलर खर्च कर रही है। भैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि तकनीक-प्रेमी किशोरों को, जो इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब पर बड़े हुए हैं, उन्हें वापस लॉग इन करने का तरीका जानने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वादा किया गया विनियमन, वर्तमान में विवरणों पर विरल है, ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर के नीति निर्माता और माता-पिता इन प्लेटफॉर्मों के विकासशील दिमागों पर पड़ने वाले नकारात्मक परिणामों से जूझ रहे हैं। यह वैश्विक बहस वर्षों से चली आ रही है, 2021 में फेसबुक (अब मेटा प्लेटफॉर्म इंक) के पूर्व कर्मचारी फ्रांसिस हाउगेन के दस्तावेज़ लीक होने के बाद चरम पर पहुंच गई, जिसमें दिखाया गया था कि कंपनी को पता था कि उसके उत्पाद लड़कियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थे। वर्षों बाद, अमेरिकी सांसद अभी भी शक्तिशाली बिग टेक कंपनियों को युवा उपयोगकर्ताओं को होने वाले नुकसान के लिए जवाबदेह बनाए रखने के लिए संघीय विनियमन पर जोर दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया मामले को अपने हाथ में ले रहा है. प्रधान मंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने इस वर्ष आयु सीमा निर्धारित करने वाले नए कानून लाने का वादा किया, उन्होंने कहा कि सरकार कटऑफ के लिए 14 और 16 के बीच की सीमा पर विचार कर रही है। एक्स पर 'माताओं और पिताओं' के लिए पोस्ट किए गए एक वीडियो में, अल्बानीज़ ने कहा कि वह चाहते हैं कि बच्चे 'अपने उपकरणों से दूर और फुटी फ़ील्ड पर आएं।' सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई सोशल-मीडिया आयु सीमा का समर्थन करते हैं, और इस विचार को व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त है। लेकिन अल्बानीज़ भी स्वीकार करते हैं कि वे अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह वास्तव में कैसे काम करेगा। सरकार यह नहीं पहचानती है कि युवा प्रतिबंध किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर लागू होगा (क्या बच्चे व्हाट्सएप पर अपने माता-पिता को संदेश भेज सकते हैं? या यूट्यूब पर खान अकादमी के बीजगणित ट्यूटोरियल देख सकते हैं?)। यह प्रवर्तन (बिग ब्रदर-एक डिजिटल आईडी? बच्चों को और अधिक अपरधी बनाना, इस बार टिकटॉक खोलने के लिए?) पर विशेष विवरण प्रदान नहीं करता है। और ठोस नीतियों के अभाव में, इसे चुनावी वर्ष से पहले एक लोकप्रिय मुद्दे पर मतदान करने वाले माता-पिता के प्रति चिंता का संकेत देने वाले एक ठोस प्रस्ताव के रूप में नहीं देखना मुश्किल है - वास्तव में बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी पूरा किए बिना। सिलिकॉन वैली से हजारों मील दूर, ऑस्ट्रेलिया बिग टेक के प्रभुत्व पर लगाम लगाने के प्रयासों में अग्रणी रहा है। डिजिटल गलत सूचना पर नकेल कसने के उद्देश्य से अलग प्रस्तावित कानून ने एलन मस्क को भी नाराज कर दिया है, जिन्होंने पिछले हफ्ते सरकार को फासीवादी करार दिया था। (सरकार ने एक आतंकवादी हमले के हिंसक वीडियो पर मस्क के एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर मुकदमा दायर किया है, लेकिन अदालत में हार गई।) ठेक दिग्गजों को समाचार सामग्री के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर करने के लिए राष्ट्र वर्षों से लड़ाई में लगा हुआ है। ऐसे समय में जब अन्य न्यायक्षेत्र ऐसी शक्तिशाली कंपनियों को लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के बहुआयामी हमले सराहनीय हैं। लेकिन शोध से पता चला है कि सोशल मीडिया के लिए आयु सीमा किशोरों को इसके संभावित नुकसान से बचाने का सबसे प्रभावी तरीका नहीं है। युवा लोगों ने समाधान खोजने में उल्लेखनीय कौशल दिखाया है - यहां तक कि 13 वर्ष से कम उम्र के लोग भी जिन पर अधिकांश प्लेटफॉर्म पहले से ही प्रतिबंध लगाते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने तर्क दिया है कि सोशल मीडिया का उपयोग किशोरों के लिए स्वाभाविक रूप से फायदेमंद या हानिकारक नहीं है, लेकिन सख्त आयु सीमाएं किशोरों के परिपक्वता स्तर में व्यक्तिगत अंतर को नजरअंदाज करती हैं। दूसरे शब्दों में, 16 साल का हो जाना तुरंत नहीं बनाताआप 14 साल के एक परिपक्व बच्चे की तुलना में डिजिटल दुनिया में नेविगेट करने में अधिक सक्षम हैं। इस अनुभाग से और अधिक इंटेल इंटेल को सेना के लिए एमएफजी चिप्स के लिए पैटागन से 3 बिलियन प्राप्त हुए: शेयरों में बढ़त डायची जापानी कंपनी दाइची लक्षित कैंसर दवाओं की खोज में अकेले जाना चाहती है जो बिडेन, बिडेन, जो इज़राइल के रक्षा मंत्री गैलेंट ने युद्ध पर बिडेन के वरिष्ठ सलाहकार को अपडेट किया अमेरिका ने गाजा में हमलों को लेकर इज़रायली सेना के प्रति निराशा व्यक्त की है अमेरिकी न्याय विभाग का कहना है कि गूगल ने विज्ञापन स्टार्टअप ,सस्ब्द्यस को खतरे के रूप में देखा और इसे खरीद लिया व्यापक आयु सत्यापन को ऑनलाइन लागू करने की प्रक्रिया गोपनीयता संबंधी चिंताओं को जन्म देती है, जिसमें युवा उपयोगकर्ताओं के बारे में जानकारी की पहचान करने से लेकर डिजिटल गुमनामी बनाए रखते हुए इंटरनेट को स्वतंत्र रूप से ब्राउज़ करने की उनकी क्षमता में कटौती तक शामिल है। ऑस्ट्रेलिया में एलजीबीटीक्यू+ समर्थकों ने प्रतिबंध प्रभावी होने पर कमजोर समलैंगिक किशोरों के लिए कनेक्शन के संभावित नुकसान के बारे में इसी तरह की चिंता जताई है। अधिक मोटे तौर पर, तकनीकी शोधकर्तालों ने चेतावनी दी है कि युवाओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बाहर करने से वे वेब के अंधेरे, यहां तक कि कम विनियमित कोनों में चले जाएंगे। फिर भी, सबूतों का बढ़ता समूह इस बात की ओर इशारा करता है कि युवा लोगों को नुकसान का एक बड़ा भंडार हो सकता है, क्योंकि कंपनी के अधिकारी किसी भी लिंक को हटाना पसंद करते हैं। यह बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि कानून निर्माता बच्चों को इन जोखिमों से बचाने के लिए कार्रवाई करें, लेकिन जटिल, वैश्विक समस्याओं के लिए त्वरित समाधान बेचने से वास्तविक दुनिया के प्रभावी समाधानों के लिए आवश्यक कठिन नीतिगत कार्यों से ध्यान भटक जाता है। युवाओं को डिजिटल जीवन में भाग लेने से प्रतिबंधित करने में एक पीढ़ी बहुत देर हो चुकी है। वास्तविकता यह है कि आजकल किशोर बहुत अधिक ऑनलाइन बढ़ रहे हैं, यह प्रवृत्ति महामारी के कारण तेज हो गई है। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि बच्चों को इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन वयस्कों की यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी है कि यह हानिकारक न हो। नीति निर्माताओं को सोशल मीडिया कंपनियों को उनकी सेवाओं से होने वाले नुकसान, खासकर युवा उपयोगकर्ताओं को होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराने पर ध्यान देने की जरूरत है। वे यह मांग करके शुरुआत कर सकते हैं कि प्लेटफॉर्म उनके एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं, इसके बारे में अधिक पारदर्शिता प्रदान करें और अधिक बाहरी शोधकर्ताओं को जोखिमों की पहचान करने की अनुमति दें। उनकी सेवाओं को कैसे डिज़ाइन किया गया है, इस पर डेटा साझा किए बिना, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और अधिकारियों के लिए खतरों को संबोधित करने वाले समाधानों की सिफारिश करना कठिन है। कानून निर्माताओं को सोशल मीडिया कंपनियों की आवश्यकता पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो अपने उपयोगकर्ताओं को समझने, युवा लोगों के लिए अधिक रोलिंग बनाने और लागू करने के लिए काफी प्रयास करती हैं। तकनीकी कंपनियों पर अपने प्लेटफॉर्म पर जोखिम कम करने की जिम्मेदारी डाले बिना, आयु सीमा को कुछ साल बढ़ाने से अगली पीढ़ी सुरक्षित नहीं रहेगी। बाढ़ के पानी को बाल्टी में डालने के बजाय, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाहर के नीति निर्माताओं को उगलने वाले नलों को बंद कर देना चाहिए।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विधि लगाने की बात करेंगे। कल आप यह जानना चाहते हैं कि आपके जीवन के ऐसे तौरतरीके क्या हैं, जब आपके सितारे बुलंद होंगे और दुनिया तथा, आपको मिल जाने से लाभकर लगता पहिए। यह न सिर्फ आपके ग्रहों में और व्यक्ति पहुंचे को सुलझाने तथा स्वास्थ्यलाभ उनमें को सफलता देनेवे, संभव फलप्राप्ति संकेतों में हो, जहां तक स्वास्थ्यलाभ हमें संकेत और बातचीत में लाभ पहुंचा देनेवे

मेष
आज आपको अचानक आर्थिक लाभ होने की संभावना है। धार्मिक कामों और उसमें सफलता प्राप्ति के लिए समय उत्तम है। आपको अभी नए काम नहीं शुरू करना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके विरोधी आपकी तकलीफ बढ़ा सकते हैं।

वृष
साहित्य-कला के प्रति आज आप में रुचि रहेगी। पेट से सम्बंधित परेशानी से शरीर अस्वस्थ रह सकता है। दोपहर के बाद आर्थिक संकट मिट सकता है। घर का वातावरण आनंदमय रहेगा। व्यापार में आपको लाभ होगा।

मिथुन
काम की सफलता के कारण पदोन्नति और यश मिलेगा। दोपहर के बाद आप मनोरंजन के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं। परिवार के साथ अच्छे भोजन का लुत्फ उठा पाएंगे। व्यापार में भागीदारों के साथ लाभदायी विचार-विमर्श होगा।

कर्क
पेट सम्बंधी तकलीफ रहेगी। प्रवास के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। आपके विरोधियों की कोई भी चाल आपके खिलाफ सफल नहीं हो सकेगी। वाणी में संयम बरतें।

सिंह
मन में भय और सुस्ती के कारण आप निराशा का अनुभव करेंगे। परिवार में संघर्ष और निकटस्थ लोगों के साथ मतभेद हो सकता है। समय पर भोजन नहीं मिल सकेगा। सार्वजनिक रूप से सम्मान की हानि न पहुंचे।

कन्या
मनोरंजक प्रवृत्ति में खोए रहेंगे। दोस्तों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बनेगा। अच्छे खान-पान और अच्छे वस्त्र खरीदने में आपकी रुचि रहेगी। दोपहर के बाद आप कुछ अधिक ही इमोशनल बने रहेंगे। इससे मन की व्यथा और बढ़ सकती है। आज नए काम की शुरुआत कर सकेंगे।

तुला
किसी बात की चिंता से आज शरीर भी शिथिल रहेगा। माता का भी स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। परिजनों के साथ विवाद हो सकता है। धन हानि के भी योग हैं। पानी से संभलकर चलें। यात्रा न करें। संतान के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है।

वृश्चिक
आपको मानसिक भय और उलझन रहेगी, जिसके कारण आप को योग्य निर्णय नहीं ले सकेंगे। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है। संतान की चिंता हो सकती है। काम में सफलता नहीं मिलने से निराशा हो सकती है।

धनु
आप किसी भी प्रकार से संकट में ना पड़ें। व्यवसाय में आप पार्टनर के साथ वाणी संयमित रखें। आज भाग्य आपका साथ नहीं देगा। पदोन्नति होने की भी संभावना है। योजनानुसार काम करने से आर्थिक लाभ भी मिलेगा।

मकर
अधिकारी के साथ वाद-विवाद को टालें और उनके कहें अनुसार आज काम करें। विरोधियों के साथ चर्चा उग्र हो सकती है। काम में सफलता मिलने में विलंब हो सकता है, धैर्य से काम करें। आज आप मौज-मस्ती में व्यस्त रहने वाले हैं।

कुंभ
खर्च में वृद्धि होगी। अनैतिक तथा नेगेटिव काम से आज दूर रहें। प्रभु की भक्ति और ध्यान से मन को शांति मिलेगी। किसी तरह का आर्थिक लाभ आपको हो सकता है। व्यापार करने वालों के लिए आज का दिन लाभदायी है।

मीन
आज आप कुछ ज्यादा ही भावुक रहेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। आज नए काम शुरू ना करें। वाणी में संयम बरतें। खान-पान में ध्यान रखें। व्यवसाय के क्षेत्र में विघ्न आ सकता हैं। भाइयों के साथ आनंद के पल गुजारेंगे।

शख्सियत

'हम समाज के लिए बने हैं शरीर से जितनी सामाजिक सेवाएं हो सकें, करनी ही चाहिए क्योंकि शास्त्रों के आधार पर हम खाली हाथ आए थे खाली हाथ ही जाना है बस इन सेवाओं के जरीए हम ऐसा कुछ ले जा सकते हैं जो ईश्वर को पसन्द है'

नमस्कार साथियों हमारे शख्सियत कॉलम के आज के आदर्श के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी ऊर्जा कहीं ना कहीं जवानों से भी अधिक है। पाकिस्तान के डेरा स्माइल खां की तहसील कांक में सन 1942 में जन्मे दौलत राम हजरत जी ने बचपन से ही संघर्ष का वह दौर देखा है जब 1947 में मई के भीषण गर्मी के महीने में भारत और पाकिस्तान में बंटवारे का वो भयावह दृश्य शुरू हुआ । बटवारें के बाद ये भारत आए और आर्मी के कैंप में पूरा परिवार रूका। वहां से पूरा परिवार वारापसी रहा तीन से चार महीने बाद फिर सरकार ने इन्हें बहाला अलवर जिले में 16 बीघा जमीन दी और विस्थापित किया पांचवी तक यह बहाला गाँव में ही पढ़े उसके बाद यशवंत स्कूल से इन्होंने अपनी पढ़ाई की । शिक्षा पूर्ण कर ये जयपुर में 2 साल ट्रेनिंग की इंस्पेक्टर के लिए और कानपुर ट्रेनिंग आईटीआई में असिस्टेंट प्रिंसिपल में चयन हुआ। थौलपुर में भी रहे। सन 1986 में टैक्निकल से इंडस्ट्रियल लाइन में आ गए और इंडो जर्मन प्रोजेक्ट में इन्होंने शानदार भूमिका निभाई और जिला उद्योग केंद्र में रहकर विभिन्न योजनाओं के तहत उद्योगपतियों को सरकारी योजनाओं के लाभ से लाभान्वित कर सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित कराया। असिस्टेंट डायरेक्टर व बाद में डिप्टी डायरेक्टर से सन 2000 में रिटायर्ड होने के बाद 58 साल की उम्र में 3 साल के लिए जयपुर उद्योग भवन में यह लगाए गए। पुरुषार्थी धर्मशाला के अध्यक्ष रहे। शांतिकुंज में महिला छात्रावास बनवाया। हजरती स्मृति ट्रस्ट बना रखा है जिसमें चंदा लेते नहीं बल्कि अपने पैसों से सामाजिक सरोकार के काम करते हैं। इन्होंने जर्मनी पैटर्न पर टूल डेवलप किया,ईक्लूड टूल इन्हीं के द्वारा डेवलप किए गए थे। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को इन्होंने डेमोंसट्रेशन करके दिखाया तो खुद प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव उसे समय खड़े होकर इनका अभिवादन किया। यही नहीं प्रधानमंत्री दूलकिट योजना का भी शुभारंभ इनके डेमोंसट्रेशन के बाद प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने कराया। सतीश भाटिया पैरिटेबल ट्रस्ट के लिए ट्रस्टी हैं, खानचन्द चिमनी बाई के संस्थान के ट्रस्टी हैं ,संतोष कुमार जानकी देवी संस्था के ट्रस्टी हैं ,आलम चंद धर्मशाला के भी यह ट्रस्टी हैं और धर्मशाला के संरक्षक भी है। आजकल नेक कमाई टीम के संरक्षक हैं । विभिन्न सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर रुचि लेते हैं और अभी फिलहाल नेक कमाई फाउंडेशन में अपनी माहिती भूमि का निभाकर सभी युवाओं का हौसला अफ्जाई करने के साथ-साथ सामाजिक सरोकार के कार्य करते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस उम्र में इस जज्बे के साथ सामाजिक सरोकार के काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हमें दौलत राम हजरती जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि सच में आपकी सेवाएं आपकी सामाजिक व्यवस्थाएं उम्र का मोहताज नहीं होती आपके अंदर सामाजिक कार्य करने का जज्बा और जुनून होना चाहिए। मैं यह कहूंगा कि यह 83 से साल के बुजुर्ग नहीं बल्कि 83 से साल के युवा है जो सामाजिक सरोकार के काम में सबसे आगे खड़े मिलते हैं। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम उनके दीर्घायु जीवन स्वस्थ जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना करती है। व्यक्तिगत रूप से मेरे पापा के साथ ये जिला उद्योग केन्द्र में रहें हैं पापा इनके सामाजिक कार्यों के बारे में काफी पहले से हमें बताया करते थे। मेरा सौभाग्य है कि आज इन्ही के बारे में लिखने का मौका मिल रहा है।

दौलत राम हजरती
(प्रमुख समाजसेवी)

जय हिंद
रूपक शर्मा

आज का इतिहास

25 सितंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच कॉमन बॉर्डर को लेकर 1237 में संधि हुई।
- इंग्लैंड और फ्रांस ने 1340 में 'निरस्त्रीकरण संधि' पर हस्ताक्षर किये।
- वास्कोडिगामा आखिरी बार वायसराय बनकर 1524 में भारत आए।
- इंग्लैंड और डेनमार्क ने 1654 को व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- अमेरिकी सेना ने 1846 में मेक्सिको के मोंटेरी पर कब्जा किया।
- ब्रिटेन में पहली बस सेवा की शुरूआत 1897 में हुई।
- फ्रांसीसी युद्धपोत लिब्रीटे में 1911 को टूलॉन हार्बर पर विस्फोट से 285 लोगों की मौत।
- रॉयल जॉर्डन वायु सेना की स्थापना 1955 में हुई।
- मध्य अमेरिकी देश बेलीज संयुक्त राष्ट्र में 1981 को शामिल हुआ।
- अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1992 में 'मार्स ऑब्जर्वर स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजा।
- तालिबान के लड़ाके के 1996 में काबुल के बेहद करीब पहुंचे।
- यमन में 2000 को रिफ्ट वैली बुखार से 211 लोग मरे, सिडनी ओलिम्पिक में 400 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक माइकल जॉनसन तथा केथीफ्रीमेन ने जीता।
- सऊदी अरब ने 2001 में तालिबान मिलिशिया से संबंध तोड़ा।
- पाकिस्तान के 60 वर्ष के इतिहास में 2006 को पहली बार सिंध के थारपारकर ज़िले के निवासी हिन्दू युवक दानेश को पाक सेना में शामिल किया गया।
- यमन के निवर्तमान राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह 2006 को एक बार फिर देश के राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित।
- अंतरिक्ष की सैर पर निकली ईरान की पहली महिला अनुशेह अंसारी ने 2006 को देश के इतिहास में नया अध्याय रचा।

विशेष आलेख

बदलापुर रेप कांड : पहले फांसी की मांग अब एनकाउंटर पर राजनीति!

अशोक भाटिया

कुछ समय पूर्व महाराष्ट्र के बदलापुर के एक स्कूल में कैंजी में पढ़ने वाली दो बच्चियों के साथ शारीरिक शोषण के मामले में मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे की अब एनकाउंटर में मौत पर बवाल मच गया है। इस मुद्दे पर इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल आ गया है। जहां एक तरफ मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे ने इसे सेल्फ डिफेंस में उठाया गया कदम बताया। वहीं, विपक्षी दल कांग्रेस राज्य सरकार के खिलाफ हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए इसे गलत करार दिया लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ रेप जैसे मामलों में सख्ती से निपटने के लिए कांग्रेस की लीडरशिप वाली केंद्र सरकार निर्भया एक्ट लेकर आई थी, लेकिन आज वही कांग्रेस अब इस घटना पर सवाल क्यों उठा रही है। बदलापुर एनकाउंटर के बाद ना सिर्फ शारीरिक शोषण का शिकार हुई दो बच्चियों के घर वाले खुश हैं बल्कि पूरे बदलापुर में खुशी का माहौल है। सभी का मानना है कि बच्चियों से गलत काम करने वालों को उनके किए की सजा मिली और उनकी मौत के साथ इस मामले में सही इंसाफ हुआ है। शहर में पटाखे फोड़े जा रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त बदलापुर में जश्न का माहौल है। कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी चिंता आरोपी अक्षय शिंदे की एनकाउंटर में मौत नहीं बल्कि महाराष्ट्र में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव हैं।

साल 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था तो लोग सड़कों पर उतर आए थे। तब देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी। बच्चों से यौन शोषण के मामलों से सख्ती से निपटने के लिए बेहद सख्त पोक्सो एक्ट बनाया गया, जिसमें दोषी के लिए उम्र कैद से लेकर फांसी तक का प्रावधान किया गया। कांग्रेस पार्टी अक्सर इस कानून को बनाने का श्रेय भी लेती है और लेना भी चाहिए। क्योंकि कानून कड़े होने से ही आरोपियों के हौसले पस्त होते हैं। अब कांग्रेस पार्टी को राज्य में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव सामने दिख रहे हैं। ऐसे में उन्हें पता है कि इस एनकाउंटर के बाद लोगों के मन में भाजपा और उसके सहयोगी दलों के बीच सहानुभूमि बढ़ेगी। यूपी के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ का मॉडल अगर महाराष्ट्र में फेमस हुआ तो सीधे तौर पर बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। महाराष्ट्र के ताजा राजनीतिक हालातों पर नजर डालें तो इस वक्त वहां खिचड़ी पकी हुई है। साल 2019 में वहां भाजपा और शिवसेना ने मिलकर चुनाव जड़ा था लेकिन मुख्य मंत्री पद को लेकर दोनों पार्टियों में तकरार हो गई। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। यह सरकार ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। शिवसेना से एकनाथ शिंदे गुट अलग हो गया और उन्होंने जून 2022 में भाजपा के समर्थन से नई सरकार का गठन किया। बाद में शरद पवार की एनसीपी में भी फूट पड़ गई। अजित पवार गुट भी एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो गया। मौजूदा वक्त में एक तरफ कांग्रेस के साथ शिवसेना का उद्धव और एनसीपी का शरद पवार गुट है तो दूसरी तरफ भाजपा के साथ शिवसेना का एकनाथ शिंदे और एनसीपी का अजित गुट है। कांग्रेस यह मुद्दा बना रही है कि भाजपा दूसरे दलों में तोड़फोड़ कर सत्ता तक पहुंचने में लगी है। ऐसे में बदलापुर एनकाउंटर हवा का रुख भाजपा की तरफ मोड़ सकता है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महा विकास अघाड़ी को तरफ से इस एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की आलोचना की जा रही है। शिवसेना (उद्धव ठाकरे) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे महायुति सरकार की अक्षमता करार देते हुए कहा कि मामले के सह आरोपी अभी तक भाग रहे हैं और मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया। ऐसा लग रहा है जैसे यह पूरी कहानी राज्य सरकार द्वारा लिखी गई है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर सांसद प्रियंका ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि आरोपी मर चुका है और पॉक्सो के तहत अन्य सह आरोपी, जो स्कूल बोर्ड के सदस्य और साथ ही भाजपा पदाधिकारी थे, भाग रहे हैं। अक्षम सरकार द्वारा लागू की गई गोली मारो और भाग जाओ रणनीति का ऐसा किताबी मामला। अगले भाग में देखिए, किसी ने भी 6 साल के बच्चों का यौन उत्पीड़न नहीं किया। राज्य सरकार द्वारा लिखित,प्रायोजित और क्रियान्वित एक कहानी।वहीं शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि गृह मंत्री और पुलिस को मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन करना चाहिए क्योंकि इसमें कई संदेह हैं। सरकार और पुलिस को स्पष्टीकरण देना चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि क्या हुआ। बदलापुर के आरोपी के एनकाउंटर पर विपक्षी सवालों पर मुख्य मंत्री शिंदे ने कहा कि कुछ दिनों पहले तक यही विपक्ष उसे फांसी देने की बात कर रहा था, अगर उसने पुलिस पर हमला किया होगा तो क्या पुलिस अपना बचाव नहीं करती विपक्ष हर बात पर सवाल उठाता है, मुझे लगता है कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है और इस पर राजनीति करना गलत है। इसके बाद घटना की जानकारी देते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि आरोपी के ऊपर उसकी पूर्व पत्नी ने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था।पुलिस चार्ट के साथ उसे जांच के लिए ले जा रही थी। इसी दौरान उसने साथ में मौजूद पुलिस वालों से बंदूक छीन ली और एक पुलिस कर्मी नीलेश मोरे पर गोली चलाई, गोली लगने से पुलिसकर्मी घायल हो गया उसे तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,इन्डस्ट्रियल सेड खन्दवा,निमाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतीक्षा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-नन्दजी पाठन*। प्रधान संपादक-राय बिलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निमाई, टोंक फोन नं.01432-244881 निमाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-पोहाम सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। बुधवार, 25 सितंबर 2024

क्या करेंगे सिद्धारमैया

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जुड़े एक मामले में मंगलवार को आया कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला पहली नजर में कांग्रेस और सिद्धारमैया सरकार के लिए झटका है। BJP ने स्वाभाविक ही इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है।

अपवाद माना | हालांकि देखा जाए तो हाईकोर्ट का यह फैसला मुख्यमंत्री की भूमिका पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं है। कोर्ट के सामने सवाल यह था कि मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच को मंजूरी देने का राज्यपाल का फैसला सही है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल आम तौर पर कैबिनेट की सलाह के मुताबिक ही काम करते हैं, लेकिन अपवाद के तौर पर कुछ मामलों में वह अपने विवेक से फैसला कर सकते हैं। मौजूदा मामला हाईकोर्ट के मुताबिक अपवाद की श्रेणी में आता है।

हाईकोर्ट ने दिया झटका

जांच की निष्पक्षता | हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब यह रास्ता खुल गया है कि इस मामले में जांच की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री दोषी हैं या नहीं, यह तो जांच के बाद साफ होगा। मगर मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी मामले में जांच शुरू होना भी कोई छोटी बात नहीं है। इसके साथ यह सवाल भी जुड़ जाता है कि क्या संबंधित व्यक्ति के मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हुए सरकारी एजेंसियां निष्पक्ष जांच कर पाएंगी।

सुप्रीम कोर्ट का विकल्प | यही वजह है कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को बल मिल गया है। हालांकि अभी हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील का विकल्प बाकी है। बहुत संभव है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कांग्रेस पार्टी इस मसले पर अपना रुख बदलने से पहले सुप्रीम कोर्ट की राय सामने आने का इंतजार करें।

अलग-अलग प्रतिक्रियाएं | हाल के वर्षों में जहां राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और सरकार चला रहे लोगों के खिलाफ आरोपों और विवादों में तेजी आई है, वहीं इन विवादों पर संबंधित पक्षों से एकदम अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। मसलन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेल जाने से पहले पद छोड़ दिया और जमानत मिलने के बाद वापस पद पर काबिज हो गए। दूसरी ओर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए पद पर बने रहे और जमानत पर बाहर आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया।

राजनीति के विविध रंग | ऐसे हर मामले में राजनीति के अलग-अलग समीकरण देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, ये मामले देश की लोकतांत्रिक चेतना के अलग-अलग पहलुओं का भी परिचय देते हैं। देखना होगा कि कर्नाटक का घटनाक्रम आगे चुनावी राजनीति का कौन सा रंग दिखाता है।

कभी-कभी

सैलरी और ख़ुशी

ललित वर्मा

एक मित्र ने कम उम्र से नौकरी शुरू कर दी थी। काम में अच्छा था, लेकिन जिस पेशे में था, उसमें तनख्वाह बढ़ने की स्पीड बहुत कम थी। बिना नौकरी चेंज किए, जॉब मिलना नामुमकिन था। लॉयल्टी उसकी कमजोरी थी, इसलिए लंबा वक्त एक जगह गुजार देता था। मुझसे जब मिला तो नौकरी और तनख्वाह से कमोबेश खुश था। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। जैसा कि सैलरी (धन) के मामले में अक्सर होता है। ज्यादा के लिए उसने नौकरी बदली और दिन-रात काम में उलझ गया। सालभर बाद कहना शुरू कर दिया कि पहले वाली नौकरी में पैसे कम थे, लेकिन सुकून था। खैर, अबकी बार खूब कोशिश के बाद भी दुबारा नौकरी चेंज नहीं कर पाया। कुछ दिन पहले अचानक बहुत कम सैलरी में फिर से सुकून वाली नौकरी में लौट आया। शहर बदला, घर बदला, सोसायटी बदली, हवा-पानी बदल लिया। अब मौज-मस्ती की रील बनाकर अक्सर इंस्टा पर अपलोड करता रहता है।

इत्तफाक से मेरे सर्कल में एक नहीं, ऐसे कई दोस्त हैं। ऐसे में अक्सर चर्चा होती है कि बढ़ी हुई सैलरी खुशियों की गारंटी क्यों नहीं हो पाती। ब्रिटिश अर्थशास्त्री रिचर्ड लेयर्ड को खुशियों का शहंशाह कहा जाता है। खुशहाली पर उनका अच्छा-खासा रिसर्च वर्क है, कई किताबें हैं। एक किताब है 'द ऑरिजिंस ऑफ हैपिनेस'। लेयर्ड इसके पांच लेखकों में से एक हैं। वह कहते हैं, दुनियाभर में बेशक आमदनी बढ़ी है, पर उस अनुपात में खुशी नहीं बढ़ी। इसकी एक वजह समाज के ताने-बाने में आया बिखराव, व्यक्तिवाद और उपभोक्तावाद में इजाफा होना है। एक दूसरे का खयाल रखने वाला समानतावादी चरित्र खुशहाली के लिए बहुत जरूरी है। यह सोच कि पैसा सारी समस्याएं खत्म कर देगा, अपने आप में एक समस्या है। खुद की तुलना दूसरों से करके हम अपना तनाव बढ़ा रहे हैं।

खैर, अपनी सोच और प्रायॉरिटीज तो हमें ही तय करनी है, लेकिन इस मामले में सरकारों की भी बड़ी भूमिका है। बेशक यह अपने देश में तो नहीं दिख रही। फिनलैंड, भूटान, UAE जैसे देशों की पॉलिसी में खुशियों के लिए जो जगह है, वह शायद ही कहीं और दिखती हो। 5 से 10 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी के लक्ष्य बनाने वाले देशों के यहां खुशहाली का कोई लक्ष्य नहीं बनता। सेंसेक्स कब एक लाख का स्तर छू लेगा, इसकी जिज्ञासा तो खूब है, लेकिन खुशियों का कोई इंडेक्स कब देश की चिंता बनेगा, कोई नहीं जानना चाहता।

सैलरी या आमदनी खुशियों के पीछे एक फैक्टर जरूर हो सकती है, लेकिन खुशियों की गारंटी नहीं। खुशी तो मन की एक अवस्था है। भीतर से ही मिलती है। जैसे किसी मृग की कस्तूरी।

एकदा

लिंकन की ढाल

Subrata Dhar

बात उस समय की है, जब अब्राहम लिंकन के राष्ट्रपति बन जाने से अमेरिका में सभी हैरान थे। उनका अब तक का जीवन असफलताओं से भरा था। कैबिनेट में मौजूद हर व्यक्ति पीठ पीछे उनकी निंदा करता। वे लोग कहते, 'आखिर पश्चिम से आए इस शख्स के अंदर में कौन काम करेगा, जो किस्से-कहानियां सुनाता रहता है।' तत्कालीन अटॉर्नी जनरल एडवर्ड बेट्स ने लिंकन के नामांकन के बाद अपनी डायरी में लिखा था कि, 'रिपब्लिकन से भयानक भूल हुई है। लिंकन ऐसे आदमी हैं, जिसके पास न कोई मकसद है और न ही कोई इच्छा।' राजकीय मामलों के मंत्री विलियम हेनरी सिवार्ड तो बात-बात में यह कहने से नहीं चूकते थे कि इलिनॉय के एक अदने से वकील को इतने बड़े पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। कैबिनेट में कोई भी शुरुआत में अब्राहम लिंकन को सम्मान नहीं देता था। लेकिन, इन सब बातों से बेपरवाह लिंकन अपने काम में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। उन्हें देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की लगन थी। इसलिए अपनी आलोचनाओं पर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एक दिन उनके एक शुभचिंतक ने पूछा, 'सर, आप में कुछ तो अलग बात है। आखिर कैसे लोगों के कड़े तीखे शब्द बाण आपको घायल नहीं कर पाते? लिंकन मुस्कराते हुए बोले, 'अरे भई, घायल तो तब करें, जब मैं उन बाणों को अपने तक पहुंचने दूं। मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देता इसलिए उनके बाण उन्हीं के पास लौट जाते हैं।' वाकई लिंकन के कोई प्रतिक्रिया न देने पर उनके शत्रु हाथ मलकर रह जाते थे। वे ईर्ष्या से जल-भुन उठते कि लिंकन पर उनकी बातों का असर क्यों नहीं होता।

संकलन : रेनू सैनी

पड़ोसी देश में वामपंथी अनुरा कुमारा दिसानायके की जीत से बदल जाएंगे समीकरण

किस 'दिसा' जाएगा भारत-श्रीलंका रिश्ता

कल्लोल चक्रवर्ती

राष्ट्रपति चुनाव में श्रीलंका के मतदाताओं ने श्रमिक के बेटे अनुरा कुमारा दिसानायके को चुना। यह दो दशकों से संसदीय राजनीति में है। उन्होंने चुनाव अभियान के दौरान गरीबों और कामगारों के हित में और एलीट राजनेताओं के खिलाफ आवाज उठाई थी।

गठबंधन की जीत | साल 2019 में राजनीतिक पार्टियों, युवाओं, महिला समूहों, ट्रेड यूनियनों और सिविल सोसायटी समूहों को जोड़कर नैशनल पीपल्स पावर (NPP) का गठन किया गया। जनता विमुक्ति पैरामुना (JVP) के दिसानायके इसके प्रत्याशी थे। उन्होंने भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करने, राष्ट्रीय विकास बैंक गठित करने, महिला सशक्तीकरण और गरीबों की मुश्किलें दूर करने के लिए IMF से दोबारा बात करने की प्रतिबद्धता जताई थी।

ऐतिहासिक चुनाव | मतदाताओं ने न सिर्फ भारी संख्या में मतदान किया, बल्कि जमे-जमाए प्रत्याशियों को बाहर कर बदलाव की बात करने वाले को चुना। कई चीजें पहली बार हुईं। जैसे, पहली बार दूसरे दौर की गिनती हुई और 50% से कम वोट पाने वाला उम्मीदवार राष्ट्रपति चुना गया। पहली बार एक वामपंथी नेता राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने जा रहा है। 2019 के चुनाव में 3% से कुछ अधिक वोट पाने वाले दिसानायके को पांच साल बाद सबसे अधिक वोट मिले, तो इसी से उनकी लोकप्रियता का पता चलता है।

बदलाव की जरूरत | दिसानायके की पार्टी JVP हिंसक संघर्ष के लिए जानी जाती रही है। हालांकि दिसानायके के नेतृत्व में पार्टी ने सशस्त्र क्रांति की हिंसक पहचान को छोड़कर पारदर्शिता, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक समाजवाद के रास्ते पर चलना शुरू किया। लेकिन, श्रीलंका को बदलने के लिए दिसानायके को और बदलना होगा। उन्होंने अल्पसंख्यक तमिलों और मुस्लिमों को कभी महत्व नहीं दिया। अब उन्हें अपनी सोच बदलनी होगी। उन्हें कारोबारियों को भी भरोसा दिलाना होगा कि वह उनके विरोधी नहीं।

तमिलों की चिंता | चुनाव अभियान के दौरान जब तमिलों को उनका अधिकार दिलाने के लिए संविधान के 13वें संशोधन को लागू करने का मुद्दा उठा था, तब दिसानायके ने संविधान ही बदल देने की बात की थी। यह देश के 23 लाख तमिलों के लिए झटका था। अब संविधान बदलने की तो बात दूर, देश की 11.2% तमिल आबादी को उन्हें भरोसा दिलाना होगा कि वह उनके हित में काम करेंगे। दिसानायके ने IMP के कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए उससे दोबारा बात करने का वादा किया था। लेकिन, वह भी जानते हैं कि यह आसान नहीं, क्योंकि IMP के कर्ज के साथ शर्तें जुड़ी होती हैं।

भारत विरोधी छवि | दिसानायके और उनकी पार्टी जनता विमुक्ति पैरामुना की छवि भारत-विरोधी की रही है। NPP में शामिल सिविल सोसायटी और पर्यावरण समूह भी भारत विरोधी बताए जाते हैं। JVP ने 1987 में दूसरा सशस्त्र विद्रोह भारत और श्रीलंका के बीच हुए समझौते के खिलाफ किया था। ऐसे ही, वर्ष 2005 में चंद्रिका कुमारतुंग की सरकार में मंत्री रहे दिसानायके ने तमिल आतंकी संगठन लिट्टे के साथ मिलकर काम करने से इनकार कर दिया था। पिछले साल दिसानायके ने अडाणी ग्रुप के विंड एनर्जी प्रॉजेक्ट को पर्यावरण-विरोधी बताकर रद्द करने की बात कही थी।

चुनौतियां
- देश को आर्थिक संकट से निकालना
- महंगाई, 36 बिलियन डॉलर का कर्ज
- विदेश नीति में संतुलन साधना

संतुलन की चाहत | हालांकि चुनाव से पहले ही दिसानायके ने भारत-विरोधी रुख में बदलाव का संदेश दिया था। फरवरी में भारत आए दिसानायके ने कहा था कि भारत की संवेदनशीलता का ध्यान रखा जाना चाहिए। नतीजे आने के बाद JVP ने जिस तरह कहा कि श्रीलंका को भारत और चीन की भू-राजनीतिक लड़ाई का केंद्र नहीं बनने देंगे, उससे भी साफ होता है कि नई सरकार संतुलन बनाकर चलेगी। दिसानायके यह भी कैसे भूल सकते हैं कि श्रीलंका के आर्थिक संकट के समय भारत ने उसे चार अरब डॉलर कर्ज दिया था।

चीन से रिश्ते | यह भी देखना होगा कि वामपंथी दिसानायके की सरकार का चीन के प्रति अतिरिक्त झुकाव रहता है या नहीं। श्रीलंका ने अपने प्रमुख बंदरगाह हंबनटोटा को 99 साल की लीज पर चीन को तो सौंपा ही, 2006 से 2022 के बीच श्रीलंका को कर्ज, अनुदान और राहत पैकेज के तौर पर चीन से बड़ी आर्थिक मदद मिली।

मालदीव की सीख | फिलहाल खुद को साबित करने की दिसानायके की चुनौती ज्यादा बड़ी है। श्रीलंका पर 36 बिलियन डॉलर का कर्ज है। इसमें से 7 बिलियन डॉलर का कर्ज तो अकेले चीन का है। करीब 26% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। बढ़ती महंगाई के कारण लोगों की क्रय शक्ति प्रभावित हुई है। लिहाजा दिसानायके सबसे पहले श्रीलंका को पटरी पर लाना चाहेंगे।

मालदीव को देखिए | जहां तक भारत-विरोध की बात है, तो मालदीव के जरिये इसे बेहतर समझा जा सकता है। वहां मुइज्जू ने चुनाव ही भारत-विरोध के नाम पर लड़ा था। सत्ता में आने के बाद उन्होंने भारत-विरोधी फैसले लिए। लेकिन, जल्दी ही उन्हें पटरी पर आना पड़ा। मालदीव की तुलना में श्रीलंका की स्थिति ज्यादा जटिल है। ऐसे में, नई सरकार भारत के खिलाफ सख्त रुख अपनाना अफोर्ड नहीं कर सकेगी।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

बहतीं नदियां प्लास्टिक की

प्लास्टिक से पट चुकी हैं हमारी नदियां। महाराष्ट्र के ठाणे, रायगढ़ और पुणे से होकर बहने वाली उल्हास नदी टनों प्लास्टिक लेकर अरब सागर से मिल रही है। यह प्लास्टिक कचरा ले जाने वाली दुनिया की टॉप 5 नदियों में शामिल हो चुकी है। विकसित देशों के संगठन OECD के मुताबिक दुनिया में सबसे अधिक प्लास्टिक कचरा जिन 50 नदियों में है, उनमें से 44 एशिया में हैं। समझते हैं पानी में भरे प्लास्टिक का हाल...

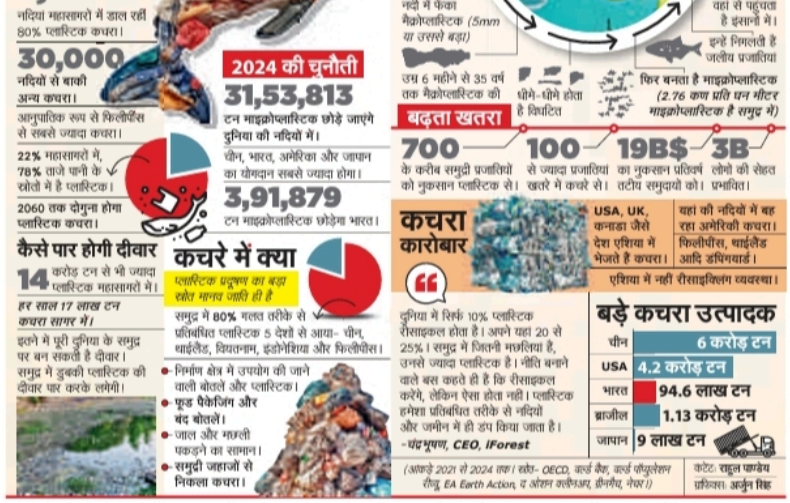

चिंता की बाढ़

1,000
नदियां महासागरों में डाल रहीं 80% प्लास्टिक कचरा।

30,000
नदियों से बाकी अन्य कचरा।

आनुपातिक रूप से फिलीपींस से सबसे ज्यादा कचरा।

22% महासागरों में, **78%** ताजे पानी के स्रोतों में है प्लास्टिक।

2060 तक दोगुना होगा प्लास्टिक कचरा।

2024 की चुनौती

31,53,813
टन माइक्रोप्लास्टिक छोड़े जाएंगे दुनिया की नदियों में।

चीन, भारत, अमेरिका और जापान का योगदान सबसे ज्यादा होगा।

3,91,879
टन माइक्रोप्लास्टिक छोड़ेगा भारत।

बढ़ता खतरा

700 के करीब समुद्री प्रजातियों को नुकसान प्लास्टिक से।

100 से ज्यादा प्रजातियां खतरे में कचरे से।

19B$ का नुकसान प्रतिवर्ष लोगों की सेहत का तटीय समुदायों को। प्रभावित।

3B लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित।

कैसे पार होगी दीवार

14 करोड़ टन से भी ज्यादा प्लास्टिक महासागरों में।

हर साल 17 लाख टन कचरा सागर में।

इतने में पूरी दुनिया के समुद्र पर बन सकती है दीवार।

समुद्र में डूबकी प्लास्टिक की दीवार पार करके लगेगी।

कचरे में क्या

प्लास्टिक प्रदूषण का बड़ा स्रोत मानव जाति ही है

समुद्र में **80%** गलत तरीके से प्रतिबंधित प्लास्टिक 5 देशों से आया- चीन, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस।

- निर्माण क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली बोतलें और प्लास्टिक।
- फूड पैकेजिंग और बंद बोतलें।
- जाल और मछली पकड़ने का सामान।
- समुद्री जहाजों से निकला कचरा।

कचरा कारोबार

"दुनिया में सिर्फ 10% प्लास्टिक रीसाइकल होता है। अपने यहां 20 से 25% । समुद्र में जितनी मछलियां हैं, उनसे ज्यादा प्लास्टिक है। नीति बनाने वाले बस कहते ही हैं कि रीसाइकल करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। प्लास्टिक हमेशा प्रतिबंधित तरीके से नदियों और जमीन में ही डंप किया जाता है।

-चंद्रभूषण, CEO, IForest

USA, UK, कनाडा जैसे देश एशिया में भेजते हैं कचरा।	यहां की नदियों में बह रहा अमेरिकी कचरा। फिलीपींस, थाईलैंड आदि डंपिंगयार्ड।

एशिया में नहीं रीसाइक्लिंग व्यवस्था।

बड़े कचरा उत्पादक

चीन	6 करोड़ टन
USA	4.2 करोड़ टन
भारत	94.6 लाख टन
ब्राजील	1.13 करोड़ टन
जापान	9 लाख टन

(आंकड़े 2021 से 2024 तक। स्रोत- OECD, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड फॉर्मूलेशन रीयू EA Earth Action, द ओशन क्लीनअप, डीनौथ, नेचर।)

कंटेंट: राहुल पाण्डेय
ग्राफिक्स: अर्जुन सिंह

पीएम मोदी की US यात्रा से क्या हासिल हुआ

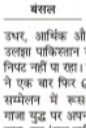

ललित मोहन बंसल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा ऐसे समय हुई है, जब विश्व संकट के दौर में है। रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म होता नहीं दिख रहा, जबकि इस्राइल-गाजा संघर्ष भी दूसरे इलाकों में फैलने को तैयार है। उधर, आर्थिक और राजनीतिक संकट में उलझा पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद से निपट नहीं पा रहा। ऐसे समय में पीएम मोदी ने एक बार फिर QUAD देशों के शिखर सम्मेलन में रूस-यूक्रेन और इस्राइल-गाजा युद्ध पर अपनी चिंता दोहराई। उन्होंने कहा, यह 'युद्ध नहीं, शांति का युग है' और 'विश्व बंधुत्व' से ही शांति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। मोदी ने यही संदेश पिछले दिनों रूस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सीधे तौर पर दिया था।

युद्ध पर चिंता | QUAD के संयुक्त घोषणापत्र में दुनिया में जारी दोनों युद्धों पर चिंता व्यक्त की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में QUAD के चौथे समिट में पहली बार बड़े स्तर पर प्रशांत हिंद महासागर के देशों में शिक्षा, चिकित्सा, सौर ऊर्जा के साथ पोर्ट सुरक्षा और दूसरे मुद्दों की सुध ली गई। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के विस्तार पर अमेरिका ने सहमति जताई है। परिषद में नॉन-वीटो पावर के साथ तीन नए स्थायी सदस्यों- भारत, जापान और जर्मनी की एंट्री के लिए वह प्रस्ताव रखेगा।

गहरी होती दोस्ती | बाइडन ने भारतीय प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने रात्रि भोजन के समय मोदी के हिंदी में दिए गए संबोधन के अंग्रेजी अनुवाद को ध्यान से सुना। इस दौरान बाइडन की बॉडी लैंग्वेज को देखकर इन दोनों नेताओं की प्रगाढ़ मित्रता का सहज अनुमान कोई भी लगा सकता था। पीएम मोदी ने रात्रि भोज के समय भारत-अमेरिका की विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी, सामरिक क्षेत्र में भागीदारी और आर्थिक क्षेत्र में हिस्सेदारी पर बाइडन के सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि बाइडन के कार्यकाल में लोकतांत्रिक मूल्यों पर जिस तरह एक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी निभाई गई, वह बेमिसाल है।

डायस्पोरा से जुड़ाव | तीन दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन न्यू यॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में आयोजित अभिनंदन समारोह में पीएम मोदी ने अपने पिछले दो कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाईं। इस बात को रेखांकित किया गया कि तीसरी बार सत्ता हासिल करने का सीधा मतलब यह है कि भारतीय जनसमूह का उनकी सरकार की उपलब्धियों और उनके प्रति अगाध विश्वास रहा है। पीएम मोदी ने सहज, सरल भाषा में बात की और उन लोगों से जुड़ाव बना पाए जो देश से हजारों मील दूर रहकर भी देश को याद करते रहते हैं। प्रधानमंत्री ने छोटे-छोटे शहरों में पहुंच रही डिजिटल बैंकिंग, शिक्षा और चिकित्सा के विस्तार, पर्यावरण संतुलन, नासा की मदद से अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट भेजे जाने, चंद्रयान और मंगलयान की अनूठी उपलब्धियों की चर्चा की। पीएम मोदी ने जब यह कहा कि भारत में पिछले अरसे में हुए बदलाव से झोली भर-भरकर निवेश आया है, तो वहां मौजूद लोगों की प्रतिक्रिया देखने लायक थी।

कॉमन रूम

विकास की चर्चा | पीएम मोदी ने दावा किया कि भारत में पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचे को बनाने-संवारने में इतना काम हुआ, जितना पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने अमेरिका और भारत के बीच विभिन्न स्तरों पर साझेदारी बढ़ाए जाने की अपील करते हुए कहा कि इस समय भारत में निवेश का स्वर्णिम अवसर है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भारतीय विविधता में एकता से लेकर अमेरिका में हुए टी-20 विश्व कप में भारतीय योगदान तक की चर्चा की। 'प्रीडम ऑफ स्पीच' और 'मीडिया की आजादी' पर भी वह बोले।

भारतीयों का उत्सव | समारोह में देखने वाली बात यह थी कि अभिनंदन समारोह को एक उत्सव के रूप में मनाया गया। लोगों ने सभागार में एंट्री के लिए घंटों इंतजार किया। बहुत से लोग कार्यक्रम स्थल तक पहुंच ही नहीं पाए। प्रधानमंत्री मोदी ने अफसोस जताया कि यह सभागार (15 हजार क्षमता) भले ही छोटा पड़ गया, पर अपनी अगली अमेरिका यात्रा में वह किसी भारतीय को निराश नहीं करेंगे।

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

तुलना करने में लगे रहे, तो प्रेम को कब समझेंगे

जे. कृष्णमूर्ति

आप कहते हैं, यह चीज उस चीज से बेहतर है। आप अपनी तुलना किसी ऐसी चीज से करते हैं, जो अधिक सुंदर और अधिक हेयिंग्स है। आप तब भी तुलना ही कर रहे होते हैं जब आप कहते हैं, 'इस नदी को मैंने पिछले साल भी देखा था और मुझे याद है कि यह तब भी इतनी ही सुंदर थी।' आप किसी और से अपनी तुलना करते हैं। किसी आदर्श से, किसी परम आदर्श से तुलना करके किसी नतीजे पर पहुंच जाना मन को मलीन बना देता है।

किसी दिन आप सूर्यास्त देखते हैं और तत्काल ही कभी पहले देखे गए सूर्यास्त से उसकी तुलना करते हैं। आप किसी पहाड़ को देखते हैं और उसकी सुंदरता को निहारते हुए कहने लगते हैं, 'दो वर्ष पहले मैंने इससे भी सुंदर पहाड़ देखा था।' जब आप तुलना कर रहे होते हैं तब आप उसे दरअसल देख ही नहीं रहे होते, जो आपके सामने हो रहा होता है, बल्कि आप उसे इसलिए देखते हैं ताकि उसकी किसी और चीज के साथ तुलना कर सकें। इसप्रकार तुलना आपको किसी चीज को पूरी तरह से देखने से रोक देती है, उसे समग्रता में देखने से वंचित कर देती है। मैं आपको देखता हूं, आप अच्छे हैं। लेकिन मैं सोचने लगता हूं, 'मैं तो इससे भी अच्छे व्यक्ति को जानता हूं। इससे अधिक श्रेष्ठ, या अधिक बेवकूफ व्यक्ति को जानता हूं।' जब मैं ऐसा कर रहा होता हूं तब दरअसल मैं आपको देख ही नहीं रहा होता, क्योंकि तब मेरे मन में कुछ और ही चल रहा होता है।

सही मायने में देखना है तो तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। जब मैं आपको बिना किसी तुलना और उस तुलना के द्वारा पहुंचे किसी नतीजे व निष्कर्ष के बिना देखता हूं, केवल तभी मैं आपको सचमुच देख व समझ पाता हूं। मैं आपकी तुलना किसी और से करता हूं, और यह तुलना करना ही व्यक्ति की गरिमा को गिराना होता है। जब मैं बिना तुलना किए आपको देखता हूं, तब मेरा सरोकार केवल आपके साथ रहता है, न कि किसी और के साथ। तुलना नहीं बल्कि यह सरोकार ही व्यक्ति की गरिमा को उभारता है। तो जब तक मन तुलना कर रहा है, तब तक उसमें प्रेम नहीं हो सकता। और मन हर समय तुलना करता रहता है, कोई नतीजा या निष्कर्ष निकालता रहता है। माप-तोल में लगा रहता है, कमी या कमजोरी ढूंढता रहता है। जहां तुलना है वहां प्रेम नहीं है।

यदि माता-पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो वे उनकी तुलना नहीं करते। वे अपने एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से नहीं करते। वह उनका बच्चा है और वे उससे सम्र प्रेम करते हैं। लेकिन, आप अपनी तुलना किसी बेहतर से, श्रेष्ठतर से, अधिक धनवान से करते हैं, और इस तरह अपने अंदर प्रेम का अभाव पैदा कर देते हैं। अपने साथ आपका सरोकार हमेशा किसी और के मुकाबले में है। मन जितना अधिक तुलनात्मक बनता जाता है, जितना अधिक निर्धर होता जाता है। वह एक ऐसा पैटर्न बनाता है जिसकी गिरफ्त में वह खुद फंस जाता है, और इसीलिए वह किसी भी चीज को ऐसे नजरिए से नहीं देख पाता है जो नया, कोरा और ताजातरीन हो। इस तरह वह उस असली चीज को समझने से वंचित हो जाता है। वह चीज जो जीवन की मौलिक सुगंध है यानी प्रेम।

(साभार : 'प्रेम क्या है' पुस्तक से)

नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली, पंजीकृत कार्यालय: एबीपी प्राइवेट लिमिटेड, 7, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। प्रधान संपादक: राजेश मित्तल। प्रबंध संपादक: राजीव जैन। प्रबंधक (मार्केटिंग): अनिल कुमार। प्रबंधक (सर्कुलेशन): विनोद कुमार। प्रबंधक (विज्ञापन): अनिल कुमार। प्रबंधक (प्रोडक्शन): विनोद कुमार। प्रिंटर: एबीपी प्राइवेट लिमिटेड, 7, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से मुद्रित। प्रधान संपादक, नवभारत टाइम्स, 1-4, डी. डी. आर्केड, नेताजी सुभाष मार्ग, दिल्ली-110006 से प्रकाशित। मुद्रक: एबीपी प्राइवेट लिमिटेड, 7, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से मुद्रित। प्रधान संपादक (प्रिंटलाइन पब्लिश्ड) : आलोक नंदन। (इस अंक में प्रकाशित समाचार सामग्री के चयन एवं संपादन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी)